

RNI No. GUJHIN/2010/35230

महानगर मेट्रो

राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र

कार्यालय :- सी-8 रिची हाउस, स्वामी नारायण मंदिर के सामने मणिनगर अहमदाबाद गुजरात-380008

महानगर मेट्रो
राष्ट्रीय दैनिक हिन्दी समाचार पत्र, प्रेस नोट एवं विज्ञापन के लिए कार्यालय पर सम्पर्क करें
सरबजीत माकन
+91-9638877700
mahanagarmetro7@gmail.com

वर्ष :16 । अंक: 41 । पेज: 12। mahanagarmetro7@gmail.co || अहमदाबाद, 7 अक्टूबर 2026 (बुधवार) || सम्पादक - सरबजीत माकन (9638877700)।। मूल्य :- 1.50 रु.-/

भारत-पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच के लिए टिकटों की जबरदस्त डिमांड, 3 दिन में 1 लाख से ज्यादा आवेदन



महानगर मेट्रो ब्यूरो

दिल्ली। 2027 वनडे वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस मैच के टिकटों के लिए पिछले तीन दिनों में आईसीसी के पास एक लाख से ज्यादा आवेदन पहुंच चुके हैं। भारत-पाकिस्तान का यह मुकाबला जोहान्सबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में प्रस्तावित है, जिसकी दर्शक क्षमता करीब 34 हजार है। ऐसे में टिकटों की मांग उपलब्ध सीटों से काफी ज्यादा रहने की संभावना है। पूरे टूर्नामेंट के टिकटों के लिए अब तक करीब 11 लाख आवेदन किए जा चुके हैं। वहीं 3 लाख 20 हजार से ज्यादा प्रशंसक टिकट बैलेट में अपना पंजीकरण करा चुके हैं। टिकट बैलेट में पंजीकरण की अंतिम तारीख 21 नवंबर है।

करजन में खराब सड़कों को लेकर कांग्रेस का हंगामा

R&B ऑफिस प्रशासन के खिलाफ कड़ा विरोध जताने पहुंचा, जनता की परेशानी के मुद्दे पर कड़े आंदोलन की धमकी दी

महानगर मेट्रो ब्यूरो/पवन माकन

करजन। विकास का बड़ा-बड़ा ढिंढोरा पीटने वाली सरकारों और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के दावों की पोल खोलती खराब और वाली सड़कें अब आम लोगों और गाड़ी चलाने वालों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए बड़ा खतरा बन गई हैं। वडोदरा ज़िले के करजन-शिनोर पंथ में सड़कों की बहुत खराब और जानलेवा हालत के खिलाफ़ जनता का गुस्सा अब चरम पर पहुंच गया है। इस गंभीर मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाते हुए कांग्रेस वर्कर, लोकल नेता और नागरिक बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट ऑफिस पर धावा बोल दिया और प्रशासन के खिलाफ़ कड़ा विरोध जताया। इलाके की मुख्य सड़कों पर लोगों को हो रही इस कमरतोड़ परेशानी को नज़रअंदाज़ करने की प्रशासन की पॉलिसी के खिलाफ़ कड़ा गुस्सा ज़ाहिर किया गया है। मालसर, शिनोर-सधाली और नरेश्वर-पालेज सड़कें 'मौत का कुआं' बन गई हैं ज़मीनी हकीकत देखने पर पता चलता है कि करजन-शिनोर इलाके से गुज़रने वाली बहुत ज़रूरी और बिज़ी सड़कें जैसे मालसर रोड, शिनोर-सधाली रोड, पोर और बहुत ज़रूरी नरेश्वर-पालेज रोड की हालत इतनी खराब हो गई है कि इनसे गुज़रना मौत को बुलावा देने जैसा है। इन सड़कों पर मगरमच्छ के मुंह जैसे बड़े और गहरे हो गए हैं, जिससे न सिर्फ़ मानसून के मौसम में बल्कि आम दिनों में भी गाड़ी चलाने वालों, स्कूली बच्चों, कर्मचारियों और पैदल चलने वालों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ झेलनी पड़ रही है। की वजह से रोज़ छोटे-बड़े हादसे हो रहे हैं, गाड़ियों के पुर्जे टूट रहे हैं और लोग गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं, फिर भी नाकाबिल प्रशासन का पेट ज़रा भी नहीं पसीजा। नरेश्वर-पालेज़ रोड पर अनोखे विरोध के बावजूद, प्रशासन शांत है हाल ही में, स्थानीय ग्रामीणों और जागरूक नागरिकों ने नरेश्वर-पालेज़ रोड की बहुत खराब और खस्ताहाल हालत के खिलाफ अनोखा विरोध दर्ज कराया है। जनता ने अपनी आवाज़ उठाने के लिए पहले भी कई बार ज्ञापन दिए हैं, फिर भी रोड और बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों की निष्क्रियता और उदासीनता बनी हुई है। जब लोगों की इस रोज़मर्रा की और वाजिब समस्या के लिए प्रशासन की ओर से कोई ठोस या संतोषजनक कदम नहीं उठाए गए, तो आखिरकार कांग्रेस पार्टी लोगों की तरफ से सामने आई और R&B ऑफिस का घेराव किया और अधिकारियों की पिटाई की गई।

अब प्रशासन की कार्रवाई पर सबकी मीटिंगः बड़े आंदोलन को हवा

कांग्रेस के इस आक्रामक प्रदर्शन और धमकी के बाद, अब इलाके के सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि R&B डिपार्टमेंट के सोए हुए अधिकारी कब अपनी नींद से जागेंगे और इन खस्ताहाल सड़कों की रीकार्पेटिंग या मरम्मत का काम कब शुरू होगा। अगर जल्द ही इन सड़कों की मरम्मत नहीं की गई, तो कांग्रेस पार्टी और स्थानीय लोगों ने एक ज़ोरदार आंदोलन करने और रोड जाम करने की धमकी दी है।

रेंट कानून में अफसरों को न्यायिक अधिकार देने पर कांग्रेस का सवाल, संविधान की मूल भावना का मुद्दा उठाया



दाहोद में युवक-नाबालिग ने आत्महत्या की लाइव स्ट्रीमिंग की, करीब 50 लोग देख रहे थे; परिवार ने पुलिस को दी सूचना

महानगर मेट्रो ब्यूरो

दाहोद। गुजरात के दाहोद जिले के हीरापुर गांव में युवक और नाबालिग लड़की ने आत्महत्या कर ली। घटना से पहले दोनों ने सोशल मीडिया पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी की। करीब 50 लोग इस लाइव स्ट्रीमिंग को देख रहे थे, जिनमें दोनों के परिवार के सदस्य भी शामिल थे। परिवार वालों को घटना की जानकारी होने के बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी, लेकिन दोनों गांव से करीब पांच किलोमीटर दूर जंगल में थे। ऐसे में पुलिस समय रहते उनकी सटीक लोकेशन तक नहीं पहुंच सकी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिंगवड तालुका के पीएसआई एसएम झाला ने बताया कि मृतक युवक की पहचान राजेश (22) के रूप में हुई है, जबकि लड़की की उम्र 16 साल थी। पुलिस के अनुसार दोनों पिछले काफी समय से एक-दूसरे के संपर्क में थे और उनके बीच संबंध थे। राजेश कुछ दिन पहले लड़की को अपने माता-पिता से मिलवाने के लिए घर भी लेकर गया था। उसने परिवार से लड़की से शादी करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन उसके माता-पिता ने इसकी मंजूरी नहीं दी थी। पुलिस के मुताबिक दोनों एक ही जाति से थे पुलिस के अनुसार घटना 4 अक्टूबर की है। राजेश और नाबालिग लड़की सुबह ही गांव से निकल गए थे। इसके बाद दोनों हीरापुर गांव के जंगल क्षेत्र में पहुंच गए।



शराब जांच के लिए फूंक मारने को कहा तो भड़का युवक, ASI को पहले मारा थप्पड़

जवाब में पुलिसकर्मी ने भी जड़ा चांटा

महानगर मेट्रो ब्यूरो

पानीपत। भरे चौराहे पर वाहन जांच के दौरान एक युवक और पुलिसकर्मी के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच हाथापाई हो गई। बिना नंबर प्लेट की बाइक चलाने के आरोप में पुलिस ने युवक को रोका था। पुलिसकर्मियों को युवक के मुंह से शराब की गंध आने पर एल्को सेंसर से जांच कराने के लिए कहा गया, लेकिन युवक सेंसर में फूंक मारने के बजाय पुलिसकर्मियों से बहस करने लगा। इसी दौरान युवक ने एएसआई पवन कुमार के कंधे पर हाथ मार दिया। एएसआई ने गुस्से में युवक को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद युवक ने भी एएसआई के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। आसपास मौजूद लोगों ने युवक को पुलिसकर्मी से दूर किया। घटना मंगलवार शाम संजय चौक पर हुई। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एएसआई और युवक के बीच शराब की जांच को लेकर बहस होती दिखाई दे रही है। वीडियो में एएसआई युवक से सेंसर में फूंक मारने के लिए कहता सुनाई देता है और उससे शराब नहीं पीने की कसम खाने के लिए भी कहता है। युवक इस दौरान खुद को मुसलमान बताते हुए कुरान की कसम खाने की बात कहता है और एएसआई से भी कसम खाने के लिए कहता है। वीडियो में युवक पुलिसकर्मी पर गाली देने का आरोप लगाते हुए लगातार बहस करता नजर आ रहा है। एएसआई उससे पूछता है कि गाली देने की बात का उसके पास क्या सबूत है। पुलिसकर्मी युवक से बार-बार फूंक मारने के लिए कहता है, जबकि युवक इसी बात को लेकर पुलिसकर्मी से उलझता रहता है। बहस के दौरान दोनों के बीच तीखी नोकझोंक होती रही। इसी बीच मामला हाथापाई तक पहुंच गया। युवक असलम ने एएसआई पवन के कंधे पर हाथ मार दिया। इसके बाद एएसआई ने उसे थप्पड़ मार दिया। जवाब में असलम ने भी एएसआई के मुंह पर थप्पड़ मार दिया।



आसपास खड़े लोगों ने तुरंत हस्तक्षेप कर युवक को दूर हटाया। डीएसपी सुरेश सैनी ने बताया कि एएसआई पवन कुमार वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने युवक को रोका, जिसके बाद युवक ने एएसआई के साथ मारपीट की। पुलिस ने एएसआई की शिकायत पर असलम के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। असलम विद्यानंद कॉलोनी का रहने वाला बताया गया है। पुलिस उसके आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच करा रही है। इसके साथ ही जिस बाइक पर वह सवार था, उसकी भी जांच की जा रही है।

SIR के विरोध में 7 घंटे से धरना, CEC से मिलने पर अड़े राहुल गांधी; तिरंगे को लेकर अफसर से हुई तीखी बहस

महानगर मेट्रो ब्यूर

नई दिल्ली। SIR के विरोध और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आकाशवाणी भवन परिसर में सात घंटे से अधिक समय से धरने पर बैठे हैं। राहुल गांधी मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने पर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि वे उनसे मिले बिना कहीं नहीं जाएंगे। धरने के दौरान तिरंगे को लेकर राहुल गांधी और एक अधिकारी के बीच तीखी बहस भी हुई। एक कार्यकर्ता तिरंगा लेकर खड़ा था। इसी दौरान एक अधिकारी उसके पास पहुंचा। राहुल गांधी तेजी से वहां पहुंचे और अधिकारी से कहा, 'इसे मत छूना।' प्रियंका गांधी भी तिरंगे के सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गईं। अधिकारी का कहना था कि तिरंगे में लगा डंडा किसी को चोट पहुंचा सकता है। इस पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि यह डंडा नहीं, तिरंगा है। इससे पहले इंडिया ब्लॉक की ओर से 'सेव डेमोक्रेसी मार्च' का आयोजन किया गया। मार्च सुबह करीब 10 बजे संसद के मकर द्वार से शुरू हुआ, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत नेताओं को हिरासत में लेकर बस में बैठाया गया। वहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त से राहुल गांधी की मुलाकात को लेकर चुनाव आयोग के सूत्रों का अलग दावा सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं की ओर से अब तक मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने के लिए कोई प्रस्ताव या अपॉइंटमेंट नहीं मांगा गया है।चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी बिना पूर्व अपॉइंटमेंट और तय एजेंडे के सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय जाना चाहते हैं। दूसरी ओर, राहुल गांधी का रुख है कि वे मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात किए बिना धरना खत्म नहीं करेंगे। स्ट्रक्चर के मुद्दे और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष के इस प्रदर्शन के बीच दिल्ली में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं।



दिनदहाड़े अधिवक्ता की हत्या से आक्रोश, कटिहार में आज वकील नहीं करेंगे न्यायिक काम

महानगर मेट्रो ब्यूरो

कटिहार। सोमवार सुबह कोर्ट जा रहे अधिवक्ता अजीमुद्दीन अंसारी उर्फ गुड्डू अंसारी की दिनदहाड़े हत्या के विरोध में जिले के अधिवक्ताओं में आक्रोश है। घटना के विरोध में मंगलवार को जिले के सभी अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से दूर रहने का निर्णय लिया है। वकीलों ने हत्या की घटना पर विरोध जताते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। जानकारी के अनुसार, अजीमुद्दीन अंसारी सोमवार सुबह स्कूटी से कोर्ट जा रहे थे। इसी दौरान हमलावरों ने उन्हें घेर लिया और स्कूटी से गिरा दिया। इसके बाद सड़क पर ही डंडे और लाठियों से उनकी बेरहमी से पिटाई की गई। हमलावरों ने चाकू से भी कई वार किए और अंत में सिर में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। घटना के बाद हमलावर हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, वारदात के दौरान आसपास मौजूद कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए दूर हट गए, जबकि कुछ लोगों ने पूरी घटना का वीडियो मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया। मृतक अधिवक्ता की पत्नी निक्की खान ने बताया कि उनके पति की किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी।



पटना मेट्रो का एक साल पूरा, अभी 6.2 किमी ट्रैक पर ही दौड़ रही ट्रेन; दिसंबर में खेमनीचक इंटरचेंज की तैयारी

महानगर मेट्रो ब्यूरो

पटना। पटना मेट्रो के परिचालन को शुरू हुए एक साल पूरा हो गया है। तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6 अक्टूबर 2025 को पटना मेट्रो के पहले प्रायोरिटी कॉरिडोर का उद्घाटन कर परिचालन को हरी झंडी दिखाई थी। हालांकि एक साल बाद भी 32.5 किलोमीटर लंबे प्रस्तावित नेटवर्क में फिलहाल सिर्फ 6.2 किलोमीटर हिस्से में ही मेट्रो चल रही है। अभी आईएसबीटी, जीरोमाइल, भूतनाथ और मलाही पकड़ी समेत चार स्टेशनों तक मेट्रो का परिचालन हो रहा है। खेमनीचक स्टेशन पर फिलहाल मेट्रो का ठहराव नहीं है। पटना में आईएसबीटी से दानापुर तक कुल 32.5 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन का निर्माण किया जा रहा है। इसमें कॉरिडोर-1 की लंबाई 17.93 किलोमीटर और कॉरिडोर-2 की लंबाई 14.55 किलोमीटर है। कॉरिडोर-1 में 7.39 किलोमीटर एलिवेटेड और 10.54 किलोमीटर अंडरग्राउंड ट्रैक है। वहीं कॉरिडोर-2 में 6.63 किलोमीटर एलिवेटेड और 7.92 किलोमीटर अंडरग्राउंड ट्रैक बनाया जा रहा है। मेट्रो नेटवर्क के विस्तार में अब सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव खेमनीचक इंटरचेंज स्टेशन माना जा रहा है। इसे अक्टूबर में शुरू करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन निर्माण कार्य पूरा नहीं होने के कारण समयसीमा बढ़ाकर दिसंबर कर दी गई है। खेमनीचक से मलाही पकड़ी और मीठापुर की ओर दो प्रमुख रूट जुड़ते हैं। जरूरी काम पूरा होने के बाद यात्रियों के लिए स्टेशन खोला जाएगा खेमनीचक से मीठापुर के बीच 3.1 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रूट पर जून 2027 तक मेट्रो परिचालन शुरू करने का लक्ष्य है। इस विस्तार के लिए छह बोगी वाली तीन मेट्रो ट्रेन सेट की तैयारी भी की जा रही है। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने पुणे मेट्रो को तीन ट्रेन सेट का ऑर्डर दिया है। इन्हें तीन साल की लीज पर लिया जा रहा है और दिसंबर तक इनके पटना पहुंचने की उम्मीद है। फिलहाल तीन बोगी वाली ट्रेनों का परिचालन हो रहा है। वहीं, कॉरिडोर-2 के मोइनुल हक स्टेडियम से पटना जंक्शन वाले हिस्से में पांच अंडरग्राउंड स्टेशनों पर जल्द फिनिशिंग वर्क शुरू होगा।



CM ऑफिस से जुड़े कथित करप्शन केस में CBI का एक्शन भगवंत मान के कैंप ऑफिस समेत OSD के ठिकानों पर जांच

महानगर मेट्रो ब्यूरो

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के चंडीगढ़ स्थित कैंप ऑफिस में मंगलवार शाम केंद्रीय जांच ब्यूरो की टीम पहुंची। CBI की अलग-अलग टीमें मोहाली और संगरूर भी पहुंचीं, जहां मुख्यमंत्री के OSD राजबीर सिंह घुम्मन और उनके परिवार से जुड़े ठिकानों पर जांच की जा रही है। संगरूर में घुम्मन के घर और मोहाली में उनके भाई के घर पर भी जांच की जानकारी सामने आई है।यह कार्रवाई पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 5 अक्टूबर के आदेश के बाद हुई है। मामला मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और ट्रांसफर-पोस्टिंग सहित सरकारी कामकाज में कथित हस्तक्षेप के आरोपों से जुड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय ने जांच के दौरान मुख्यमंत्री के हस्ष्ठ राजबीर सिंह घुम्मन का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर सामने रखा था। हालांकि, पंजाब पुलिस की ओर से उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी। श्वष्ठ ने जुलाई और अगस्त 2026 में पंजाब के DGP गौरव यादव को तीन पत्र भेजकर मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी। इन पत्रों में ट्रांसफर-पोस्टिंग, नीतिगत फैसलों, टेंडर, सीएलयू और अन्य सरकारी मंजूरियों में कथित दखल के आरोप लगाए गए थे। श्वष्ठ के अनुसार, जांच में नितिन गोहल, राजबीर सिंह घुम्मन और अन्य लोगों की भूमिका सामने आई। एजेंसी ने गोहल को सरकारी काम कराने के इच्छुक लोगों और मुख्यमंत्री के हस्ष्ठ के बीच कथित बिचौलिया बताया। जांच एजेंसी ने व्हाट्सऐप चैट और अन्य डिजिटल साक्ष्यों का भी हवाला दिया है। इनमें ट्रांसफर-पोस्टिंग, नीतिगत फैसलों, टेंडर और सरकारी दस्तावेजों तक कथित पहुंच से संबंधित बातचीत होने का दावा किया गया।



जयपुर में 10 घंटे बंद रहेगा सीबीआई रेलवे फाटक, हजारों लोगों को करना होगा वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल

महानगर मेट्रो ब्यूरो

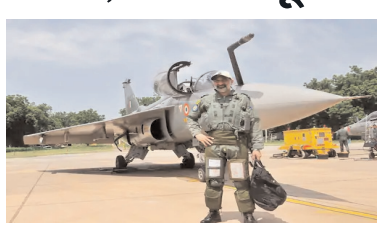
जयपुर। खातीपुरा और जगतपुरा रेलवे स्टेशन के बीच स्थित सीबीआई रेलवे फाटक नंबर 214 मंगलवार, 7 अक्टूबर को 10 घंटे के लिए बंद रहेगा। रेलवे ट्रैक के मेंटेनेंस कार्य के चलते सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक फाटक से वाहनों और लोगों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। इस दौरान वाहन चालकों और स्थानीय लोगों को वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करना होगा।उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि रेलवे ट्रैक पर आवश्यक मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा। काम पूरा होने तक सीबीआई फाटक नंबर 214 से वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। रेलवे की ओर से लोगों से अपील की गई है कि निर्धारित अवधि के दौरान फाटक की ओर जाने से बचें और अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए दूसरे मार्गों का उपयोग करें। आसपास के कई इलाकों को जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग पर स्थित है।



आशुतोष दीक्षित संभालेंगे वायुसेना की कमान, 31 अक्टूबर को बनेंगे 29वें एयर चीफ मार्शल

महानगर मेट्रो ब्यूरो

नई दिल्ली। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख होंगे। वह 31 अक्टूबर को वायुसेना प्रमुख का पदभार संभालेंगे और देश के 29वें एयर चीफ मार्शल होंगे। फिलहाल वह वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने 1 जुलाई 2026 को वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ की जिम्मेदारी संभाली थी। करीब 40 वर्ष के सैन्य करियर वाले एयर मार्शल दीक्षित का लड़ाकू विमान उड़ाने और सैन्य अभियानों का लंबा अनुभव है। वह कारगिल युद्ध में भी शामिल रहे हैं। युद्ध के दौरान उन्होंने लड़ाकू विमान से घुसपैठियों के ठिकानों पर बमबारी की थी। उन्हें करीब 20 प्रकार के लड़ाकू और अन्य सैन्य विमानों को उड़ाने में महारत हासिल है। एयर मार्शल दीक्षित ने अब तक 3500 घंटे से अधिक उड़ान भरी है। उन्होंने मिराज-2000, मिग के विभिन्न संस्करणों, जगुआर, तेजस, हॉक, आईएल-78, एएन-32, किरण, एचपीटी-32 और एवरो जैसे विमानों को उड़ाया है। वह एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट के साथ-साथ क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर भी हैं। अपने सैन्य करियर के दौरान उन्होंने ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन रक्षक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों में हिस्सा लिया। इसके अलावा कोप-इंडिया सहित कई सैन्य अभ्यासों में भी उनकी भूमिका रही है। भारतीय वायुसेना में स्वदेशी एलसीए तेजस और अन्य स्वदेशी विमान परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एयर मार्शल दीक्षित को 6 दिसंबर 1986 को भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन मिला था। सैन्य प्रशिक्षण और उच्च शिक्षा के दौरान वह नेशनल डिफेंस एकेडमी, डिफेंस स्टाफ सर्विस कॉलेज (बांग्लादेश) और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र रहे हैं।



MLA कुमार कनानी ने पुलिस सिस्टम और होम डिपार्टमेंट के खिलाफ खोला मोर्चा, सरकार की परफॉर्मेंस पर उठाए सवाल

महानगर मेट्रो ब्यूरो

सूरत। सूरत शहर की पॉलिटिक्स इस समय गुजरात की पॉलिटिक्स में चर्चा का सबसे बड़ा सेंटर बन गई है। सूरत के वराछा इलाके से ज़मीनी और बेबाक BJP MLA कुमार कनानी ने



अपनी ही पार्टी की सरकार और पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। कुमार कनानी ने राज्य में होम डिपार्टमेंट संभाल रहे और सूरत से आने वाले टॉप लीडरशिप की परफॉर्मेंस पर सवाल उठाकर पॉलिटिकल गलियारों में बड़ी हलचल मचा दी है। कुमार कनानी ने सूरत पुलिस कमिश्नर और पुलिस सिस्टम पर एक के बाद एक लेटर लिखकर कड़े सवाल पूछे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सूरत शहर में ट्रैफिक नियमों के नाम पर सिर्फ गरीब और मिडिल क्लास टू-व्हीलर (बाइक-स्कूटर) ड्राइवरों से ही फाइन वसूला जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि पुलिस बड़ी गाड़ियों को अनदेखा क्यों करती है, जबकि बड़े भारी वाहन (ट्रक, डंपर और गाड़ियां) नियमों का उल्लंघन करते हैं कनानी ने पुलिस विभाग की पोल खोलते हुए कहा है कि सूरत शहर में सुरक्षा के लिए लगाए गए 800 से ज़्यादा CCTV कैमरे लंबे समय से बंद हैं, फिर भी प्रशासन इस बारे में कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। अगर जनता के टैक्स के पैसे से बना सिस्टम सजावट की चीज़ बनकर रह गया, तो इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने साफ कहा है कि ट्रैफिक सुधारने के नाम पर पुलिस द्वारा की जा रही पैसे की उगाही तुरंत बंद होनी चाहिए।

गुजरात रेंट बिल का विरोधः नडियाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर वकीलों ने कानून जलाकर अपना गुस्सा निकाला

महानगर मेट्रो ब्यूरो

नडियाद। गुजरात में किराए और प्रॉपर्टी के झगड़ों को लेकर सरकार के लाए गए नए गुजरात रेंट बिल के खिलाफ वकीलों में बहुत गुस्सा है। इस कानून के विरोध में वकील नडियाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर जमा हुए और गुजरात रेंट बिल जलाया और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। वकीलों के इस ज़बरदस्त विरोध से कोर्ट परिसर में काफी हंगामा हुआ। नडियाद बार एसोसिएशन के नेताओं और वकीलों ने कहा कि किराए से जुड़े झगड़ों और प्रॉपर्टी के मामलों को ज्यूडिशियल कोर्ट के बजाय एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के सामने ले जाने का प्रोविज़न किया गया है। इस व्यवस्था के कारण, इस बात का पक्का डर है कि आम पार्टियों और क्लाइंट्स को सही कानूनी प्रक्रिया और समय पर न्याय पाने में बड़ी मुश्किलों और रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। ज्यूडिशियल प्रक्रिया को बायपास करने से आम नागरिकों के कानूनी अधिकार खतरे में पड़ सकते हैं। पुराने किराएदारों के हित और वकीलों की रोजी-रोटी खतरे में नडियाद बार एसोसिएशन ने खास तौर पर पुराने किराएदारों के हितों की सुरक्षा और वकीलों की नौकरी को लेकर गहरी चिंता जताई है। वकीलों का मानना है कि ऐसे कानूनों से सालों से किराए पर रह रहे मिडिल क्लास और गरीब किराएदारों में बेघर होने का डर पैदा होगा, और ज्यूडिशियल सेक्टर से जुड़े वकीलों की प्रैक्टिस और नौकरी पर भी बुरा असर पड़ेगा। नडियाद कोर्ट के बाहर वकीलों के इस विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रशासन और सरकार के खिलाफ जोरदार नारे लगाए गए। वकीलों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर सरकार इस जनविरोधी और प्रॉपर्टी मालिक-किराएदार विरोधी रेंट बिल को वापस नहीं लेती है, तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज किया जाएगा।



ध्यान देकर सोने की अंगूठियां चुराने वाला कुख्यात गैंग पुलिस के हत्थे कुछ ही घंटों में चढ़ा

महानगर मेट्रो ब्यूरो

अहमदाबाद। रानीप पुलिस स्टेशन की सर्विलांस टीम ने अहमदाबाद शहर में आम लोगों को टारगेट करके चोरी और धोखाधड़ी करने वाले लोगों पर नकेल कस दी है। रानीप पुलिस ने रानीप इलाके में रिक्शा में सफर कर रही एक मासूम बहन पर ध्यान देकर उसकी कीमती सोने की अंगूठी चुराने वाले को कुछ ही घंटों में चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की इस तेज और सराहनीय कार्रवाई से रिक्शा चोरों और लुटेरों में भारी हलचल मच गई है। घटना की पूरी जानकारी के अनुसार, शिकायत करने वाली बहन रानीप इलाके से गुजर रही थी और सफर के लिए रिक्शा में बैठी थी। इसी बीच, रिक्शा में पहले से बैठे माहिर तस्करों ने अपनी चालाकी से बहन की नजरें चुरा लीं और जैसे ही उसने नजरें हटाईं, उसके हाथ से कीमती सोने की अंगूठी छीन ली। जैसे ही बहन को इस धोखाधड़ी और चोरी के बारे में पता चला, उसने तुरंत राणिप पुलिस स्टेशन से संपर्क किया और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। घटना की गंभीरता को देखते हुए, राणिप पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर और सर्विलांस स्क्वाड टीम तुरंत एक्शन में आ गई। पुलिस ने घटना स्थल के आसपास के CCTV फुटेज चेक किए और टेक्निकल सर्विलांस और मुखबिरों का जाल बिछाया। राणिप पुलिस की गहन और बारीकी से जांच के परिणामस्वरूप, चोरी को अंजाम देने वाले आरोपी कुछ ही घंटों में पुलिस के चंगुल में फंस गए।



अहमदाबाद रूरल में GVCL के बिजली के तार चुराने वाला कुख्यात गैंग पकड़ा गया

महानगर मेट्रो ब्यूरो

अहमदाबाद. अहमदाबाद रूरल लोकल क्राइम ब्रांच ने अहमदाबाद जिले में बिजली कंपनी के खंभों से चालू और चालू बिजली के तार चुराकर भागने वाले तस्करों पर नज़र रखी है। रूरल LCB टीम ने नॉर्थ गुजरात पावर कंपनी लिमिटेड से बिजली के तार चुराने वाले एक कुख्यात और सक्रिय गैंग के 6 सदस्यों को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से कुल 6.50 लाख रुपये जब्त किए हैं और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना की जानकारी के अनुसार, पिछले कुछ समय से अहमदाबाद रूरल इलाके में UGVCL के बिजली के खंभों से अचानक तार गायब होने और बिजली सप्लाई में रुकावट आने की घटनाएं बढ़ रही थीं। इसे गंभीरता से लेते हुए, रूरल LCB टीम ने इन अपराधों को रोकने के लिए मुखबिरों और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से जांच शुरू की। इस दौरान, खास जानकारी के आधार पर पुलिस ने छापा मारकर एक इंटर-स्टेट या सक्रिय गैंग का भंडाफोड़ किया। पुलिस कस्टडी में 6 आरोपियों की पहचान रूरल LCB द्वारा गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों की ऑफिशियल लिस्ट इस तरह है जगदीश गुर्जर. शिवराज रावत, मदन रावत,छोटूलाल भील , श्रवण रावत, त्रिलोक रावत, इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उनसे उन जगहों के बारे में गहराई से पूछताछ की है जहां वे चोरी करते थे और चोरी के तार किसे बेचते थे। आरोपियों की तेजी से गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनसे कुल 6.50 लाख रुपये की जब्त प्रॉपर्टी जब्त की है, जिसमें चोरी के बिजली के तारों के साथ-साथ क्राइम में इस्तेमाल की गई गाड़ियां और इक्विपमेंट शामिल हैं। इस गैंग की गिरफ्तारी से अहमदाबाद रूरल एरिया के कोथ पुलिस स्टेशन और धोलका पुलिस स्टेशन में दर्ज बिजली के तार चोरी के गंभीर और अनसुलझे क्राइम ऑफिशियली सॉल्व हो गए हैं। रूरल की इस तारीफ़ के काबिल और तेज कार्रवाई से पूरे जिले के किसानों और बिजली कंज्यूमर्स ने राहत की सांस ली है।

गुजरात रेंट बिल-2026 के खिलाफ वकीलों की आंखें लाल

कांग्रेस ने BJP सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, आरोप लगाया कि यह कानून गरीब और मिडिल क्लास विरोधी है

किराए के मामलों में अफसरों को न्यायिक अधिकार देने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल



महानगर मेट्रो ब्यूरो/पवन माकन

अहमदाबाद। गुजरात में BJP सरकार द्वारा लाए गए विवादित 'गुजरात रेंट एक्ट, 2026' के खिलाफ राज्य भर के वकीलों और बार एसोसिएशन का विरोध और हड़ताल जारी है। इस कानून को पूरी तरह से गरीब, आम और मिडिल क्लास विरोधी बताते हुए, गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी लीगल सेल के प्रेसिडेंट और जाने-माने कानूनविद श्री योगेश रवानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने इस कानून को सीधे तौर पर संविधान विरोधी बताया है और इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। यह कानून संविधान की मूल भावना और शक्तियों के बंटवारे के खिलाफ हैः योगेश रवानी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, श्री योगेश रवानी ने कहा कि यह रेंट एक्ट, जिसे गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली में गुजरात बिल नंबर 22 ऑफ़ 2026 के तौर पर पास किया गया था और 31-08-2026 को गजट में पब्लिश किया गया था, भारत के मूल संविधान के खिलाफ है। भारतीय संविधान सरकार के तीन स्वतंत्र अंग बनाता हैः

1. **लेजिस्लेटिव (विधान सभा/संसद)**
2. **एग्जीक्यूटिव (कार्यकारी)**
3. **ज्यूडिशियरी (न्यायपालिका)**

इन तीनों अंगों के कामकाज और सीमाओं को पक्का किया गया है, और ज्यूडिशियरी पूरी तरह से स्वतंत्र रहते हुए न्याय प्रक्रिया को चलाने के लिए एक ऑटोनॉमस संस्था है। लेकिन, सरकार द्वारा लाए गए नए रेंट एक्ट के सेक्शन-30 के तहत डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारियों को 'रेंट अथॉरिटी' और सेक्शन-33 के तहत एडिशनल कलेक्टर को 'रेंट कोर्ट' बनाया गया है। एग्जीक्यूटिव अधिकारियों को न्यायिक प्रक्रिया और शक्ति देने का यह कानून संविधान के मूल प्रावधानों पर सीधा हमला है। ये सरकारी अधिकारी कभी भी बड़े सरकारी अधिकारियों के दबाव या निर्देशों को नज़रअंदाज़ करके बिना किसी भेदभाव के न्याय नहीं दे सकते, और उन्हें कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया का भी उतना अनुभव नहीं होता।

अफसरों को न्यायिक अधिकार देने पर सबसे बड़ा सवाल

गुजरात रेंट बिल-2026 में किराए से जुड़े मामलों के लिए डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारियों को रेंट अथॉरिटी और अतिरिक्त कलेक्टर स्तर के अधिकारियों को रेंट कोर्ट की ज़िम्मेदारी देने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ ने इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता और शक्तियों के बंटवारे से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताते हुए कानून वापस लेने की मांग की है

गलत कानूनी प्रावधान और भेदभाव न करने वाले नियम

कांग्रेस लीगल सेल के प्रेसिडेंट ने आगे हमला करते हुए कहा कि इस कानून को लागू करने के लिए 'इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड-2023' (जो पुराने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का नया रूप है और क्रिमिनल कोर्ट की प्रक्रिया के लिए एक कानून है) के प्रावधानों को लागू किया गया है, जो पूरी तरह से गलत है। इसके अलावा, यह नया कानून रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल प्रॉपर्टी और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के बीच कोई फर्क या भेद नहीं करता है। नतीजतन, आम रेजिडेंशियल मामलों में भी छोटे लोगों और गरीब किराएदारों को भविष्य में बड़ी मुश्किलों और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

कांग्रेस पार्टी की कड़ी धमकीः कानून को तुरंत रद्द करें

गुजरात रेंट बिल-2026 कई गंभीर कमियों और गड़बड़ियों से भरा है, जिससे राज्य के नागरिकों में नाराजगी की आग जल रही है। क्योंकि यह कानून लोगों के हित में नहीं है, इसलिए कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि सरकार अपना अहंकार छोड़े और इस जनविरोधी कानून को तुरंत रद्द करे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉ. मनीष एम. दोशी (मीडिया कन्वीनर और प्रवक्ता) भी खास तौर पर मौजूद थे। वकीलों के लगातार विरोध और कांग्रेस के इस आक्रामक रुख के कारण आने वाले दिनों में राजनीतिक और कानूनी मोर्चे पर हंगामा होने की पूरी संभावना है।

कांकरिया से हथियारों के साथ कुख्यात आदमी गिरफ्तार, 2 देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस जब्त

महानगर मेट्रो ब्यूरो

अहमदाबाद। अहमदाबाद शहर में असामाजिक तत्वों और अपराधियों पर नकेल कसने में सक्रिय अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने एक और गंभीर अपराध का खुलासा किया है। क्राइम ब्रांच टीम ने शहर के बहुत लोकप्रिय और व्यस्त कांकरिया इलाके से अवैध बंदूक के साथ घूम रहे एक कुख्यात युवक को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के पास से बड़ी मात्रा में घातक हथियार मिलने के बाद पुलिस बल में काफी हलचल मच गई है। मिली जानकारी के अनुसार, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम शहर में गश्त और नाकाबंदी पर थी, इसी दौरान मिली खास सूचना के आधार पर फरमान अंसारी नाम के एक व्यक्ति को घेराबंदी करके कांकरिया इलाके से गिरफ्तार किया गया। जब पुलिस ने उसकी गहन तलाशी ली, तो उसके पास से 2 देसी पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस मिले। पुलिस ने इन सभी घातक हथियारों और कारतूसों को जब्त कर लिया है और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी पहले भी कई गंभीर अपराधों में शामिल रहा है क्राइम ब्रांच की शुरुआती जांच में पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी फरमान अंसारी का लंबा क्रिमिनल इतिहास है। इससे पहले भी यही शख्स अहमदाबाद शहर के वटवा और करंज जैसे थाना इलाकों में गैर-कानूनी शराब, जुआ और धोखाधड़ी जैसे गंभीर अपराधों में पकड़ा जा चुका है। पिछले अपराधों से छूटने के बाद भी, पुलिस ने गहराई से जांच शुरू कर दी है कि क्या वह फिर से गैर-कानूनी हथियारों के साथ एक्टिव था और कोई बड़ा अपराध करने की योजना बना रहा था। शहर में कानून-व्यवस्था की स्थिति मजबूत है कांकरिया जैसे सार्वजनिक और घनी आबादी वाले इलाके से हथियारों के साथ इस अपराधी की गिरफ्तारी से नागरिकों में दहशत फैल गई थी, लेकिन क्राइम ब्रांच ने समय पर कार्रवाई करके एक बड़ी अनहोनी को टाल दिया है। पुलिस ने यह पता लगाने के लिए रिमांड लिया है कि उसे ये हथियार किसने दिए और वह उन्हें कहां से लाया और इस पूरे नेटवर्क को खत्म करने की कोशिश कर रही है

गरीबों के घरों पर बुलडोज़र चलाने वाली AMC कुछ समाजों के दबाव में मूकदर्शक क्यों बनी रही?

महानगर मेट्रो ब्यूरो

अहमदाबाद। अहमदाबाद शहर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कामकाज पर जनता की तरफ से कई सवाल उठाए जा रहे हैं। गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि AMC लगातार आम जनता और गरीब वर्ग के साथ भेदभाव कर रही है। एक तरफ अधिकारियों ने टाउन प्लानिंग स्कीम के नाम पर हजारों गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों के घर तोड़कर उन्हें बेघर कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ, स्ट के ही नरोडा नॉर्थ जोन यानी सरदारनगर वार्ड में प्रशासन की मिलीभगत या लाचारी साफ दिख रही है। TP 97 की 12 मीटर की सड़क सिर्फ़ कागज़ों तक सीमित, मंदिर के बहाने दबाव बनाने वालों के ख़िलाफ़ प्रशासन चुप

जानकारी के अनुसार, सरदारनगर वार्ड में TP स्कीम नंबर 97 में 12 मीटर चौड़ी सड़क को सरकारी तौर पर मंज़ूरी दी गई है और नक्शे में भी दिखाया गया है। लेकिन असलियत यह है कि यह सड़क ज़मीन पर है ही नहीं! इस सार्वजनिक सड़क का काम इस इलाके के समाज के कुछ प्रभावशाली लोगों ने मंदिर का बहाना बनाकर या बैरिकेड लगाकर रुकवा दिया है। आम लोगों के विकास का दावा करने वाली, स्ट इस गैर-कानूनी रोक और दबाव को देखकर आँखें मूंदकर चुपचाप बैठी है। जब भी शहर में गरीबों की झोपड़ियाँ या आम घर गिराने होते हैं, तो, स्ट प्रशासन तुरंत पुलिस बल के साथ पहुँच जाता है और उन्हें कानून का पाठ पढ़ाता है। लेकिन जब किसी इलाके के बड़े लोग या कुछ समाज के लोग सरकारी सड़क पर दबाव बनाकर उसे रोकते हैं, तो प्रशासन की अथॉरिटी शक के दायरे में आ जाती है। क्या कानून और नियम सिर्फ़ गरीब और मिडिल क्लास के लिए हैं? अधिकारियों और , स्ट अधिकारियों की इस दोधारी नीति से नरोदा पंथक के लोगों में बहुत गुस्सा है। स्थानीय लोग ज़ोर देकर मांग कर रहे हैं कि, स्ट इस मामले में



जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करे, मंदिर की आड़ में डाला जा रहा दबाव हटाए और 12 मीटर का TP रोड खोले, ताकि आम जनता को आने-जाने में राहत मिले। अगर प्रशासन इस मामले में सही कार्रवाई नहीं करता है, तो आने वाले दिनों में जनआंदोलन शुरू करने की धमकी भी दी गई है।

लवली स्टोर को निशाना बनाकर 25 हज़ार से ज़्यादा कैश चोरी, पूरी घटना CCTV में कैद

महानगर मेट्रो ब्यूरो

डभोई। शहर में आधी रात के करीब कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। तस्करों ने डभोई रेलवे स्टेशन जाने वाली मेन रोड पर मौजूद एक जाने-माने प्रोविजन स्टोर को निशाना बनाया है और स्टोर से पच्चीस हज़ार रुपये से ज़्यादा कैश चुराकर भाग गए हैं। इस दुस्साहसिक चोरी से पूरे व्यापारी समुदाय में भारी हंगामा और गुस्सा फैल गया है। मिली जानकारी के मुताबिक, डभोई रेलवे स्टेशन रोड पर मौजूद मैजेस्टिक टॉकीज़ के बगल में पीर मोहम्मद जमालभाई पानवाला का लवली स्टोर नाम का एक प्रोविजन स्टोर है। चूंकि यह दुकान सालों से बंद एक पुराने बोर्डिंग लॉज के निचले हिस्से में है, इसलिए इसका पिछला हिस्सा बहुत ही जर्जर हालत में है। दुकान में अभी मरम्मत का काम चल रहा था और मलबा हटाने के लिए सामने लगाई गई लोहे की सिक्योरिटी नेट को व्यापारी ने अनलॉक कर दिया था, जो खुली रही। इस खुले जाल और टूटे-फूटे हिस्से का फ़ायदा उठाकर, देर रात एक शातिर अनजान तस्कर नकाब पहनकर दुकान में घुस गया। हाथ में टॉर्च लिए तस्कर ने दुकान में सारा सामान बिखेर दिया और तिजोरी में रखे पच्चीस हज़ार रुपए से ज़्यादा कैश ले गया। यह सारी शरारत दुकान में लगे CCTV कैमरे में साफ़-साफ़ कैद हो गई है। सुबह के आस-पास जब व्यापारी दुकान खोलने पहुँचा, तो अंदर सामान अस्त-व्यस्त देखकर उसके होश उड़ गए। उसने तिजोरी चेक की, तो कैश गायब देखकर उसे चोरी का बहुत बुरा लगा। व्यापारी ने तुरंत डभोई पुलिस स्टेशन को इसकी जानकारी दी। घटना की गंभीरता को देखते हुए, डभोई पुलिस का एक काफ़िला तुरंत मौके पर पहुँचा और कड़ी जाँच की। पुलिस ने दुकान के CCTV फुटेज को अपने कब्ज़े में लेकर वेरिफ़िकेशन शुरू कर दी है,



बनासकांठा में खाकी का बड़ा भंडाफोड़ः शिहोरी में स्कॉर्पियो कार से लाखों की विदेशी शराब के साथ कुख्यात शराब तस्कर पकड़ा गया

महानगर मेट्रो ब्यूरो

पालनपुर। जहां जिला पुलिस प्रमुख ने बनासकांठा जिले में शराब तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है, वहीं LCB बनासकांठा-पालनपुर टीम ने राजस्थान से गुजरात में तस्करी करके लाई जा रही बड़ी मात्रा में विदेशी शराब पर कार्रवाई करते हुए एक बड़ा ऑपरेशन किया है। शिहोरी थाना इलाके से पुलिस ने एक स्कॉर्पियो कार में ले जाई जा रही 7,33,524/- रुपये की बड़ी मात्रा में विदेशी शराब और बीयर जब्त की है। इस छापेमारी में पुलिस ने कार और मोबाइल फोन समेत 11,63,524/- रुपये का भारी मात्रा में सामान जब्त किया है और शराब तस्करी में शामिल एक इंटरस्टेट गैंग का भंडाफोड़ किया है। बनासकांठा रेंज पुलिस इंस्पेक्टर जनरल श्री परीक्षित राठौड़ और बनासकांठा जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट श्री प्रशांत सुंबे के सख्त निर्देशों के मुताबिक, राजस्थान के बॉर्डर से शराब की गैर-कानूनी तस्करी को खत्म करने के लिए पूरे जिले में कड़ी नाकाबंदी और ड्राइव चलाई गई। इन बड़े अधिकारियों के निर्देशों के बाद, LCB पालनपुर के पुलिस इंस्पेक्टर श्री डी.एम. राठौड़ और पुलिस सब इंस्पेक्टर श्री आर.बी. जडेजा और श्री जे.एस. गढ़वी ने अलग-अलग टीमें बनाकर पंथक में निगरानी शुरू कर दी। सिनेमा पंजाबः फिल्मी अंदाज में स्कॉर्पियो ने ओवरटेक किया आज, LCB टीम को मिली खास जानकारी के आधार पर, पुलिस का एक काफिला तैयार होकर शिहोरी ब्रिज के पास हाईवे रोड पर नाकाबंदी में बैठा था। इसी दौरान, पुलिस ने तेज रफ्तार से आ रही संदिग्ध स्कॉर्पियो गाड़ी को रुकने का इशारा किया। लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी रोकने के बजाय उसे भगा दिया। पुलिस ने तेजी से फिल्मी अंदाज में उसका पीछा किया। शिहोरी से मानपुर जाते समय, S.M. Enterprises के सामने हाईवे रोड पर एक प्राइवेट पुलिस गाड़ी ने स्कॉर्पियो गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी सड़क से नीचे उतरकर सीधे एक पेड़ से टकराकर रुक गई। एक्सीडेंट के बाद, पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार ड्राइवर से पूछताछ करने पर उसका नाम प्रवीण उर्फ पम्शा मोहनलाल बिश्नोई (निवासी सांतरू, ता. रानीवाड़ा, जी. जालोर, राजस्थान) बताया गया। यह व्यक्ति अपनी स्कॉर्पियो कार में बिना किसी पास परमिट के गैर-कानूनी तरीके से विदेशी शराब की बोतलें और बीयर नंबर 3172 गुजरात में ला रहा था। पुलिस जांच में इस स्कैम के मुख्य साजिशकर्ताओं के नाम भी सामने आए हैं।



बनासकांठा में किसानों का गुस्सा फूटाः पालनपुर में किसानों के हंगामे और भारी ट्रैफिक जाम से एडमिनिस्ट्रेशन में हड़कंप

महानगर मेट्रो ब्यूरो

छोटाउदेपुर। पास गंभीर रेल हादसा 23 साल का हिम्मत राठवा, जो अपनी क्लास खत्म करके घर लौट रहा था, एक टावर वैगन की चपेट में आ गया, और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। छोटाउदेपुर जिले में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा सामने आया है। खजुरिया गांव के एक 23 साल के होनहार युवक की रेलवे लाइन पर मरम्मत के काम के दौरान टावर वैगन की चपेट में आने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक, खजुरिया गांव के रहने वाले हिम्मतभाई नसरभाई राठवा (उम्र करीब 23) झाबुगाम से अपनी क्लास खत्म करके ट्रेन से पुनियावत लौटे थे। स्टेशन या हॉल्ट से उतरने के बाद, वह रेलवे लाइन के पास अपने गांव खजुरिया की ओर पैदल जा रहे थे। इसी बीच, रेलवे लाइन पर मरम्मत के काम में इस्तेमाल होने वाली टावर वैगन मशीन अचानक आ गई और हिम्मतभाई उसकी चपेट में आ गए और गंभीर चोटों के कारण मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही आस-पास के इलाकों से बड़ी संख्या में गांव वाले मौके पर पहुंच गए। युवक की अचानक मौत से खजुरिया और आस-पास के इलाकों में गहरा दुख और मातम छा गया है।

छोटाउदेपुर SOG का बड़ा ऑपरेशनः नसवाड़ी के मतोरा गांव से 8.01 लाख का हरा गांजा ज़ब्त

महानगर मेट्रो ब्यूरो

छोटाउदेपुर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने नसवाड़ी तालुका के मतोरा गांव में एक खेत में छापा मारकर बड़ी मात्रा में गैर-कानूनी हर्बल हरा गांजा ज़ब्त किया। राज्य में नशीले पदार्थों की तस्करी और फैलाव को रोकने के लिए, सीनियर पुलिस अधिकारियों के निर्देश और गाइडेंस में जिले में NDPS अपराधों का पता लगाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है। जिसके तहत, छोटाउदेपुर SOG पुलिस सब



इंस्पेक्टर एम.एच. जादव को मिली जानकारी के आधार पर नसवाड़ी के मतोरा गांव में छापा मारा गया। जांच के दौरान, आरोपियों के कब्जे वाले खेतों से अवैध रूप से लगाए गए हरे मारिजुआना के पौधे पाए गए:, दोनों आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और उन्हें आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए नसवाड़ी पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया है। विष्णुभाई रामाभाई राठवा (निवासी मोटा फलिया, मटोरा, ता. नसवाड़ी, जी. छोटाउदेपुर) दमनभाई कचराभाई राठवा (निवासी मोटा फलिया, मटोरा, ता. नसवाड़ी, जी. छोटाउदेपुर) इस सफल ऑपरेशन में, A.H.T.U (एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट) छोटाउदेपुर PI S.D. कलारा, SOG P.S.E. M.H. जादव, ASI मिनेशभाई नरसिंहभाई, ASI दशरथभाई लच्छूभाई, HC सुरेंद्रसिंह खुमानसिंह, HC विकमभाई कोतवालभाई और HC प्रवीणभाई तेरियाभाई शामिल हुए।

यू रानीप में फुटपाथ से 1 महीने के मासूम बच्चे को छीनने वाले कुख्यात स्मगलिंग गैंग का पर्दाफाश

महानगर मेट्रो ब्यूरो

अहमदाबाद। गुजरात की एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक कैपिटल माने जाने वाले अहमदाबाद शहर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बच्चा चोरी की एक बहुत ही शर्मनाक और चौंकाने वाली साज़िश का पर्दाफाश अहमदाबाद क्राइम ब्रांच और रानीप पुलिस की जॉइंट और एक्टिव जांच से हुआ है। पुलिस ने उस गैंग के सरगना को गिरफ्तार कर लिया है जिसने शहर के न्यू रानीप इलाके में अहवालिया झील के पास खुले फुटपाथ पर खाट पर गहरी नींद में सो रहे एक मजदूर परिवार के 1 महीने और 7 दिन के बच्चे को छीन लिया था। बिना बच्चे वाले कपल को ऊंचे दाम पर बच्चा बेचने की इस घिनौनी साज़िश में जिनल और प्रवीण यादव समेत कुल 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूरे शहर में काफी चर्चा है। फुटपाथ पर सो रहे एक मज़दूर परिवार की ज़िंदगी का बसेरा बिखर गया मिली जानकारी के मुताबिक, न्यू राणिप इलाके में अहवालिया झील के पास फुटपाथ पर दिन-रात मेहनत करके गुज़ारा करने वाला एक गरीब मज़दूर परिवार रहता था। दिन भर की थकान और मेहनत के बाद यह मज़दूर दंपत्ति अपने परिवार के साथ फुटपाथ पर रखी खाट पर गहरी नींद में सो रहा था। इसी बीच तस्करों की बुरी नज़र इस गरीब परिवार के 1 महीने 7 दिन के नवजात बच्चे पर पड़ गई। देर रात अंधेरे का फ़ायदा उठाकर असामाजिक तत्वों ने खाट पर सो रहे इस मासूम कबूतर को छीन लिया। जब सुबह माता-पिता जागे तो उन्होंने अपने प्यारे बच्चे को गायब पाया। बच्चे के किडनैप होने से मज़दूर माता-पिता की दिल दहला देने वाली चीखों से माहौल गमगीन हो गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए राणिप पुलिस स्टेशन और अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीमों ने तुरंत जांच शुरू कर दी। पुलिस जांच में जो बातें सामने आईं, वे बेहद चौंकाने वाली हैं। यह बच्चा चोरी कोई आम किडनैपिंग नहीं थी, बल्कि एक सोची-समझी और प्लान की हुई क्रिमिनल साज़िश का हिस्सा थी। आरोपियों ने बच्चे को बिना बच्चे वाले दंपत्ति को गैर-कानूनी तरीके से बेचकर लाखों रुपये कमाने की नापाक साज़िश रची थी।

ACB ने देवगढ़बरिया सिविल हॉस्पिटल में छापा मारा

महानगर मेट्रो ब्यूरो

दाहोद। दाहोद ज़िले से एक बहुत ही शर्मनाक और चौंकाने वाला स्कैम सामने आया है, जो दिखाता है कि गुजरात के सरकारी हॉस्पिटल में मरीज़ों की सेवा करने की कसम खाने वाले कुछ ज़िम्मेदार अधिकारी किस हद तक करप्शन के दलदल में डूबे हुए हैं। दाहोद के देवगढ़बरिया में जे.एस. चौहान सिविल हॉस्पिटल में काम करने वाले एक क्लास-1 (क्लास-वन) मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने मेडिकल स्टूडेंट्स से हॉस्पिटल में अच्छी ड्यूटी देने और नौकरी के दौरान उन्हें परेशान न करने के बदले रिश्वत मांगी। एंटी-करप्शन ब्यूरो की टीम ने हॉस्पिटल कैंपस



में सफलतापूर्वक ट्रैप लगाकर इस करप्ट क्लास-1 डॉक्टर को रंगे हाथों पकड़ लिया, जिससे पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया। डिस्ट्रिक्ट रेजीडेंसी प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को धमकाकर रिश्वत मांगी गई मिली जानकारी के मुताबिक, अलग-अलग मेडिकल कॉलेजों के 8 रेजिडेंट मेडिकल स्टूडेंट्स को देवगढ़बरिया के जे.एस. चौहान सरकारी हॉस्पिटल में 'डिस्ट्रिक्ट रेजीडेंसी प्रोग्राम' के तहत ट्रेनिंग के लिए अपॉइंट किया गया था। ये युवा स्टूडेंट्स अपने मेडिकल करियर के तौर पर हॉस्पिटल में सेवा देने आए थे, लेकिन हॉस्पिटल के हरफनमौला मेडिकल सुपरिटेंडेंट (क्लास-1) डॉ. रहीमभाई इब्राहिमभाई मेमन की नज़र इन स्टूडेंट्स पर थी। हेल्थ ऑफिसर डॉ. रहीमभाई मेमन ने इन सभी 8 मेडिकल स्टूडेंट्स के सामने एक अनचाही मांग रखी थी। उन्हें हॉस्पिटल में पसंदीदा और अच्छी ड्यूटी देने और ड्यूटी के दौरान किसी भी तरह की परेशानी या परेशानी न करने के बदले में, 5,000 रुपये प्रति स्टूडेंट के हिसाब से कुल 40,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई थी। अपनी पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बनने के सफर पर निकले इन युवा स्टूडेंट्स से खुलेआम किश्तें वसूलने की इस घटिया हरकत ने पूरी मेडिकल कम्युनिटी को शर्मसार कर दिया है। ACB का कामयाब जालः क्लास-1 डॉक्टर को क्वार्टर से ही पकड़ा गया इस मामले में, पीड़ित मेडिकल स्टूडेंट्स ने एंटी-करप्शन ब्यूरो से कॉन्टैक्ट किया और उन्हें पूरी बात पता चल गई। ACB टीम ने बहुत चालाकी और चुपके से जाल बिछाया था।



गांधीनगर में परेड कर्मियों के लिए फॉगिंग और सर्विलांस का काम वॉर फुटिंग पर शुरू

महानगर मेट्रो ब्यूरो

गांधीनगर। राज्य में मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी वेक्टर से होने वाली बीमारियों पर असरदार कंट्रोल और बचाव के उपायों के तहत, हेल्थ मिनिस्टर श्री प्रफुल पंशेरिया की अध्यक्षता में गांधीनगर में हेल्थ डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारियों के साथ एक बहुत ज़रूरी हाई-लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। इस मीटिंग में, राज्य के सभी जिलों और म्युनिसिपल एरिया में महामारी की मौजूदा स्थिति का डिटेल में रिव्यू किया गया।

नेशनल यूनिटी डे परेड में हिस्सा लेने वाले कर्मियों की हेल्थ के लिए बड़े पैमाने पर उपाय

आने वाली 'नेशनल यूनिटी डे परेड' में हिस्सा लेने के लिए देश के अलग-अलग राज्यों से BSF, CRPF और ITBP के जवान 21 सितंबर से ही गांधीनगर पहुंच चुके हैं। इन सुरक्षा कर्मियों के लिए गांधीनगर शहर के सेक्टर-28 और 29 में सरकारी आवास में टेम्परारी रहने का इंतज़ाम किया गया है। लेकिन, इस नए बने सरकारी आवास कॉम्प्लेक्स में पानी भरने की वजह से मच्छरों का बहुत ज़्यादा प्रकोप हो गया, जिसकी वजह से कुछ जवानों में डेंगू के मामले सामने आए और उनका गांधीनगर सिविल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। इस गंभीर मामले को ध्यान में रखते हुए हेल्थ मिनिस्टर ने तुरंत सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।

हर ब्लॉक में 4 हेल्थ वर्कर नियुक्त करने का मिनिस्टर का आदेश

जवानों की हेल्थ की हालत को गंभीरता से लेते हुए, मिनिस्टर श्री प्रफुल्ल पंशेरिया ने आदेश दिया है कि हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमें प्रभावित इलाकों में युद्ध स्तर पर इंटेंसिव फॉगिंग, दवाओं का स्प्रे और पेशेंट ट्रैकिंग करें। इसके अलावा, जवानों के घरों के साथ-साथ परेड ग्राउंड में भी फीवर सर्विलांस, डिसइंफेक्शन का काम और रोज़ाना फॉगिंग इंटेंसिव तरीके से की जाए। मिनिस्टर ने साफ तौर पर निर्देश दिया था कि जवानों के सरकारी आवास के हर ब्लॉक में 4-4 हेल्थ वर्कर



नियुक्त किए जाएं। यह ज़ोर देकर कहा गया है कि रहने की जगह के किसी भी कोने या इलाके में पानी न भर जाए, इसकी इंटेंसिव जांच की जाए और इसे तुरंत हटाया जाए। चांदीपुरा वायरस पर कंट्रोल और महामारी के संतोषजनक आंकड़े मीटिंग के दौरान, मंत्री ने खुशी जताई और कहा कि पिछले दो महीनों में राज्य में चांदीपुरा वायरस का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। पहला मामला सामने आने के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम ने दिन-रात जो शानदार काम किया, उससे इस वायरस को फैलने से रोकने में कामयाबी मिली है। इसके अलावा, मंत्री ने आंकड़ों की जानकारी देते हुए कहा कि साल 2026 में, राज्य में मलेरिया के मामलों में पिछले साल के मुकाबले 39.6 प्रतिशत और डेंगू के मामलों में 20.6 प्रतिशत की बड़ी कमी आई है। इस साल के 40वें हफ्ते तक, पूरे राज्य में 1.39 करोड़ से ज़्यादा ब्लड सैंपल की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 1,401 मरीज़ों में मलेरिया पाया गया है। डेंगू की सही पहचान के लिए राज्य के मेडिकल कॉलेजों से जुड़े 42 अस्पतालों में खास डायग्नोस्टिक सेंटर बनाए गए हैं, जहां 1.50 लाख से ज़्यादा सैंपल की जांच के बाद 2,345 मरीज़ पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य में एंटी-मलेरिया दवाओं, कीटनाशकों और लार्वा नाशकों का पर्याप्त स्टॉक है। मंत्री ने राज्य के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अपने घरों और आस-पास के इलाकों में पानी जमा न होने दें और वेक्टर-बोर्न बीमारियों से बचने के लिए खास सावधानी बरतें।

संसद से चुनाव आयोग तक मार्च, जो लोकतंत्र का प्रदर्शन हैः राजनीतिक भूचाल ने राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों को रास्ते में रोका, आक्रामक हमला कहा 'ज्ञानेश कुमार डरे हुए हैं'

महान गर मेट्रो ब्यूरो

दिल्ली। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के बड़े-बड़े दावों के बीच आज देश की राजधानी दिल्ली में राजनीतिक गर्मी चरम पर पहुंच गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अगुवाई में 'भारत' गठबंधन के सैकड़ों सांसदों ने संसद भवन से चुनाव आयोग तक एक विशाल विरोध मार्च (मार्च) निकाला। लेकिन, लोकतंत्र के पवित्र स्तंभ माने जाने वाले इन दो महत्वपूर्ण स्थानों के बीच दिल्ली पुलिस ने कड़े इंतजाम करके और बैरिकेड लगाकर विपक्षी सांसदों को आगे बढ़ने से रोक दिया, जिससे राष्ट्रीय राजनीति में हाई-वोल्टेज ड्रामा और हंगामा हो गया। चुनाव आयोग सिर्फ 50 मीटर दूर था, फिर भी सांसदों को रोका गयाः राहुल गांधी दिल्ली पुलिस ने लोकसभा में विपक्ष के नेता को चुनाव आयोग के मुख्य ऑफिस से सिर्फ 50 मीटर दूर रोक दिया, जिससे राहुल गांधी का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। गुस्से में राहुल गांधी ने मीडिया के सामने एक बड़ा बयान देते हुए सरकार और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने गरजते हुए कहा, 'हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और उनके दो साथियों से मिलना चाहते थे। हम देश के करोड़ों आम नागरिकों की आवाज हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस देश के चुने हुए नुमाइंदों को क्यों रोका जा रहा है? इलेक्शन कमीशन यहां से सिर्फ 50 मीटर दूर है, फिर भी हमें आगे नहीं जाने दिया जा रहा। आखिर सवाल क्या है और किसके कहने पर एडमिनिस्ट्रेशन यह सब कर रहा है? ' राहुल गांधी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर सीधा और तीखा हमला किया और गंभीर आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन का मुख्य काम पूरी तरह से निष्पक्ष रहकर देश और डेमोक्रेसी को चलाना है। लेकिन आज जब देश के



करीब 300 MP इलेक्शन कमिश्नर से मिलकर अपनी वाजिब बातें रखना चाहते हैं, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार डरे हुए हैं। उन्होंने लाल आंखों से सवाल उठाया, 'अगर देश के नुमाइंदों का यह बड़ा डेलीगेशन खुद इलेक्शन कमिश्नर से नहीं मिल सकता, तो इस देश में डेमोक्रेसी और संविधान का क्या मतलब है? ' विपक्ष का देश भर में हंगामा, सरकार के खिलाफ जमकर गुस्सा संसद भवन से इलेक्शन कमीशन तक इस प्रोटेस्ट मार्च के दौरान, विपक्षी सांसदों ने केंद्र सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जोरदार नारे लगाए।

अहमदाबाद के मकरबा ब्रिज के डिज़ाइन में गंभीर खामीः AMC की लाल आँख, ज़िम्मेदार 'डेल्फ़ कंसल्टेंसी' के ख़िलाफ़ कड़ा नोटिस!

महानगर मेट्रो ब्यूरो

अहमदाबाद। अहमदाबाद शहर में लाखों-करोड़ों रुपये के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कैसे करप्ट प्लानिंग और लापरवाही का शिकार होते हैं, इसका एक और जीता-जागता उदाहरण मकरबा रेलवे ओवरब्रिज मामले में सामने आया है। स्त हाईवे और आस-पास के इलाकों को जोड़ने वाले विवादित ब्रिज के डिज़ाइन में बड़ी लापरवाही और गंभीर खामियाँ सामने आने के बाद, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (ख्ष्ट) सिस्टम आखिरकार हरकत में आया है।ख्ष्ट ने लाल आँख करके उस कंसल्टेंसी फर्म के ख़िलाफ़ कड़ा नोटिस जारी किया है जिसने ब्रिज की प्लानिंग और डिज़ाइन में गंभीर खामियाँ दिखाकर जनता के टैक्स का पैसा बर्बाद किया। मिली ऑफिशियल जानकारी के मुताबिक, मकरबा रेलवे ओवरब्रिज का हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उद्घाटन किया था। इस ब्रिज के उद्घाटन के बाद ट्रैफिक की समस्या कम होने के दावे खोखले साबित हुए और इसके उलट, यह ब्रिज गाड़ी चलाने वालों के लिए बहुत बड़ी समस्या और सिरदर्द बन गया है। ब्रिज की लैंडिंग और मोड़ इतनी खराब जगह पर बनाए गए हैं कि गाड़ी चलाने वालों को आते-जाते समय बहुत खतरा और एक्सीडेंट का डर बना रहता है। क्योंकि ब्रिज सीधे कॉर्पोरेट रोड के चौराहे पर उतर रहा है और विज़न साफ़ नहीं है, इसलिए ट्रैफिक जाम की भयानक समस्या पैदा हो गई है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि उद्घाटन के अगले ही दिन प्रशासन को मेन रोड बंद करके बैरिकेड्स और डायवर्जन लगाने पड़े। इस गंभीर परेशानी के कारण, स्थानीय नागरिकों और रोज़ाना गाड़ी चलाने वालों को 300 से 500 मीटर का एक्स्ट्रा चक्कर लगाना पड़ रहा है। चूंकि पास में फायर स्टेशन जैसी ज़रूरी सुविधाएं हैं, इसलिए इमरजेंसी गाड़ियां भी ट्रैफिक में फंस रही हैं। डिज़ाइन तैयार करने वाली 'डेल्फ़ कंसल्टेंसी' को कारण बताओ नोटिस पुल की इस घटिया और बेतुकी प्लानिंग पर जनता और मीडिया के गुस्से के बाद, ख्ष्ट प्रशासन जागा है। नोटिस में कॉर्पोरेशन ने साफ़-साफ़ कहा है .

धोलेरा के मिंगलपुर गांव में महाकाली मंदिर के पास चल रहे जुए के अड्डे पर रेड, 8 जुआरी रंगे हाथों पकड़े गए

महानगर मेट्रो ब्यूरो

अहमदाबाद। अहमदाबाद रूरल लोकल क्राइम ब्रांच ने अहमदाबाद जिले में असामाजिक गतिविधियों और गैर-कानूनी जुए के अड्डों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया है। एक टिप-ऑफ के आधार पर, रूरल टीम ने धोलेरा पुलिस स्टेशन एरिया के मिंगलपुर गांव में रेड मारी है। पुलिस ने रेड करके 8 बदनाम जुआरियों को रंगे हाथों पकड़ा है जो महाकाली मंदिर के पास खुली जगह में जुआ खेल रहे थे। मिली जानकारी के मुताबिक, जब अहमदाबाद रूरल LCB टीम पेट्रोलिंग पर थी, तो उन्हें खास जानकारी मिली कि धोलेरा पुलिस स्टेशन के तहत मिंगलपुर गांव के पाडर में महाकाली मंदिर के पास कुछ लोग खुले में जुआ खेल रहे हैं। जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस के काफिले ने अचानक उस जगह पर रेड मारी। पुलिस को अचानक देखकर जुआरियों में भगदड़ मच गई, लेकिन तैयार पुलिस टीम ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और सभी आरोपियों को पकड़ लिया।

62 हजार से ज़्यादा कैश ज़ब्त

पुलिस ने मौके से पकड़े गए जुआरियों के शरीर के अंग और उनके दांव पर लगाए गए पैसे के साथ-साथ कुल 62 हजार रुपये से ज़्यादा कैश ज़ब्त किया है। ग्रामीण LCB की इस ज़बरदस्त कार्रवाई से जुआ खेलने वालों और असामाजिक तत्वों में भारी हलचल मच गई है। पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ धोलेरा पुलिस स्टेशन में जुआ एक्ट के तहत



मामला दर्ज किया गया है और सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है। पुलिस की इस सख्त कार्रवाई से यह साफ हो गया है कि ग्रामीण इलाकों में गैर-कानूनी काम करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस आगे की जांच कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या ये जुआरी पहले भी ऐसे अपराधों में शामिल थे और इस नेटवर्क के पीछे कौन ऑपरेटर है।

अहमदाबाद सेशंस कोर्ट के बाहर वकीलों का विरोधः रेंट बिल की कॉपियां जलाईं, सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, हड़ताल जारी

महानगर मेट्रो ब्यूरो

अहमदाबाद। गुजरात में किराए और प्रॉपर्टी के झगड़ों से जुड़े एक नए विवादित कानून ने न्याय जगत में भूचाल ला दिया है। आज अहमदाबाद सेशंस कोर्ट के बाहर वकीलों ने एक बहुत ही ज़बरदस्त और अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। सरकार द्वारा लाए गए नए रेंट बिल के विरोध में वकीलों ने सेशंस कोर्ट के बाहर कानून की कॉपियां जलाकर खुलकर अपना गुस्सा जाहिर किया। वकीलों के इन ज़बरदस्त प्रदर्शनों से कोर्ट परिसर में भारी हंगामा हुआ। बिना लिखित गारंटी के पीछे हटने को तैयार नहीं, वकील अपनी ज़िद पर अड़े नए रेंट बिल के खिलाफ वकील पिछले कुछ समय से हड़ताल और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आज भी पूरे ज़ोर-शोर से जारी हैं। वकीलों की साफ मांग है कि जब तक सरकार इस काले कानून को लेकर कोई संतोषजनक लिखित गारंटी नहीं देती, तब तक उनका आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। सेशंस कोर्ट परिसर में जमा हुए हजारों वकीलों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए और कानून की कॉपियों को सरेआम आग के हवाले कर दिया। आम केस करने वालों और वकीलों की रोजी-रोटी पर बड़ा संकट आंदोलन कर रहे वकीलों का आरोप है कि किराए से जुड़े झगड़ों को सिविल कोर्ट के बजाय एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या दूसरे फोरम में ले जाने के नियम से आम केस करने वालों और क्लाइंट्स को बहुत मुश्किल होगी। सही इंसाफ मिलने का प्रोसेस मुश्किल होने के साथ-साथ इस फील्ड से जुड़े वकीलों की नौकरी और पुराने किराएदारों के हितों को भी गंभीर खतरा हो गया है। सरकार के खिलाफ



वकील आर-पार की लड़ाई के मूड में अहमदाबाद सेशंस कोर्ट के बाहर कानून की कॉपी जलाकर वकीलों ने सरकार को साफ चेतावनी दी है कि अगर यह जनविरोधी और मकान मालिक-किराएदार विरोधी बिल जल्द से जल्द वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को राज्य भर में और भी उग्र बनाया जाएगा। वकीलों के इस आक्रामक मूड ने राजनीतिक और कानूनी माहौल को गर्म कर दिया है।

सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय लोकतंत्र का आधार, देश की नींव

महानगर मेट्रो ब्यूरो

नागदा। लोकतंत्र केवल मतदान का अधिकार या सरकारी सुविधाएं प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह अधिकारों के साथ कर्तव्यों, समानता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना भी सिखाता है। ऐसे में समाज के सामने एक गंभीर आत्ममंथन का प्रश्न है–क्या हमारी पहचान परिस्थितियों के अनुसार बदलती है? कर और टैक्स चुकाते समय हम सबसे पहले भारतीय नागरिक होते हैं। चुनाव के समय हमारी जातीय, सामाजिक अथवा धार्मिक पहचान कई बार प्रमुख हो जाती है और सरकारी योजनाओं, आरक्षण अथवा अन्य सुविधाओं का लाभ लेते समय हम अपनी पात्रता और वर्ग के आधार पर अधिकार की बात करते हैं। यह विरोधाभास किसी एक व्यक्ति या समाज तक सीमित नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिक चेतना से जुड़ा व्यापक विषय है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यूजीसी सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का उद्देश्य शिक्षा के अवसरों को व्यापक बनाना और विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का अवसर देना है। सामाजिक न्याय की नीतियों का उद्देश्य उन वर्गों को अवसर उपलब्ध कराना है, जो ऐतिहासिक रूप से शिक्षा और विकास के समान अवसरों से वंचित रहे हैं। ऐसे प्रयासों का सम्मान करते हुए यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और सुविधाओं का लाभ वास्तविक पात्र एवं जरूरतमंद व्यक्ति तक पारदर्शी तरीके से पहुंचे। सामाजिक न्याय का अर्थ किसी एक वर्ग को दूसरे के विरुद्ध खड़ा करना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था तैयार करना है जिसमें ऐतिहासिक वंचना को दूर करने के साथ आर्थिक रूप से कमजोर और वास्तविक जरूरतमंद व्यक्ति को भी आगे बढ़ने का उचित अवसर मिले। इस विषय पर केवल सरकार और व्यवस्था से सवाल करना पर्याप्त नहीं है।

भावनात्मक - ईश्वर ने भेजा था निमित्त बनाकर, जानापाव पर जैन सोश्यल ग्रुप ने दिया जीवनदान

महानगर मेट्रो ब्यूरो

नागदा। यूँ तो अनेक धार्मिक एवं मनोरंजन यात्रा निकलती रहती है, पर जैन सोश्यल ग्रुप नागदा की एक दिवसीय पातालपानी यात्रा इस बार सामान्य नहीं रही। एक हृदय विदारक घटना ने इस यात्रा को एडवेंचर टूर में परिवर्तित कर दिया और मानवता की मिसाल बन गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार जैन सोश्यल ग्रुप नागदा के सदस्य एक दिवसीय पातालपानी टूर पर निकले थे। लौटते समय उनका काफिला जानापाव पहाड़ी के समीप से गुजर रहा था। यह स्थान उनकी नियोजित यात्रा में शामिल नहीं था, पर सदस्यों की इच्छा पर बस को जानापाव की ओर मोड़ा गया। जानापाव की खड़ी और संकरी चढ़ाई देखकर बस ड्राइवर ने बस को ऊपर ले जाने से मना कर दिया। ड्राइवर का कहना था कि खड़ी चढ़ाई यात्रियों के लिए जोखिम भरी हो सकती है। इस पर सभी सदस्यों ने पैदल चढ़ाई करने का निर्णय लिया।ल चढ़ाई के दौरान ही सभी ने देखा कि आगे एक कार जो चढ़ाई चढ़ने का प्रयास कर रही थी, अचानक अनियंत्रित होकर रिवर्स में पीछे की ओर आने लगी। सड़क के एक तरफ पहाड़ और झाड़ियाँ थी तो दूसरी तरफ गहरी खाई। कार में एक पूरा परिवार - पति-पत्नी, बच्चे और बुजुर्ग सहित चार लोग सवार थे। चूंकि कार की गति अभी कम थी.

बिग बॉस फेम अनुराग डोभाल गिरफ्तार रिश्तेदार पर जानलेवा हमले का आरोप

महानगर मेट्रो ब्यूरो

देहरादून। बिग बॉस फेम और चर्चित यू-ट्यूबर अनुराग डोभाल उर्फ UK®| Rider एक बार फिर गंभीर विवाद में घिर गए हैं। देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में एक रिश्तेदार की शिकायत के बाद पुलिस ने अनुराग डोभाल और उनके तीन साथियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले में मारपीट, रास्ता रोकने और जान से मारने की धमकी समेत धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला 5 अक्टूबर की शाम का बताया जा रहा है। शिकायतकर्ता राज सिंह चौहान के मुताबिक, वह हरिद्वार बाईपास स्थित एक कैफे के पास अनुराग और उनके साथियों से मिलने पहुंचे थे। आरोप है कि बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया और इसके बाद उनके साथ मारपीट शुरू कर दी गई। शिकायत में लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं। राज सिंह चौहान का दावा है कि अनुराग डोभाल ने उनका गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। इसके बाद उनके साथ मौजूद लोगों ने कथित तौर पर लोहे की रॉड और डंडों से हमला किया। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें कार के नीचे डालकर कुचलने की कोशिश की गई। साथ ही चाकू और बंदूक दिखाकर डराने तथा जान से मारने की धमकी देने का भी दावा किया गया है। हालांकि, ये सभी आरोप शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए हैं। पुलिस जांच के बाद ही पूरे घटनाक्रम की वास्तविक तस्वीर स्पष्ट होगी। शिकायत के मुताबिक, मारपीट के दौरान मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की गई। शिकायतकर्ता ने अपनी सोने की चेन और घड़ी ले जाने का भी आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, शिकायत में अनुराग डोभाल और उनके साथियों पर शिकायतकर्ता तथा उनके परिवार को जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया गया है। फिलहाल इतना साफ है कि सोशल मीडिया की चमक और लोकप्रियता के बीच अनुराग डोभाल एक गंभीर कानूनी विवाद में फंस गए हैं। पुलिस की कार्रवाई के बाद अब मामले की अगली दिशा जांच और न्यायिक प्रक्रिया तय करेगी।

पाली जिला कलक्टर ने ली अधिकारियों की क्लास, पेयजल, त्योहारी सीजन में मिलावट और योजनाओं में प्रगति के दिए कड़े निर्देश

महानगर मेट्रो ब्यूरो

पाली। पाली जिला कलक्टर कार्यालय के सभागार में सोमवार को जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलक्टर ने विभिन्न विभागों के कामकाज, विशेष रूप से पेयजल वितरण और चिकित्सा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए आगामी समय की योजनाओं को लेकर अधिकारियों को कड़े और स्पष्ट निर्देश दिए बैठक के दौरान जिला कलक्टर ने प्रमुख विभागीय योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की। उन्होंने पेयजल को लेकर विशेष कार्ययोजना तैयार करने, शहरी व ग्रामीण वार्डों में जलापूर्ति, पेयजल परिवहन, गांवों में टांकों का चिन्हीकरण तथा पानी के टैंकरों की व्यवस्था सुचारू रखने के निर्देश जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और जल संसाधन विभाग को दिए। इसके अलावा, पशुपालन विभाग को चारे की व्यवस्था और पशु शिविरों के आयोजन तथा कृषि विभाग को क्रॉप कटिंग, फसल खराबा और गिरदावरी से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए। आगामी त्योहारी सीजन के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा और जनस्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए जिला कलक्टर ने चिकित्सा विभाग को मिलावटखोर?? के खिलाफ सख्त अभियान चलाने के निर्देश दिए। इसके तहत नकली दूध, पनीर, मावा और घी के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई करने की बात कही गई। साथ ही रसद विभाग, जल संसाधन विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग को सैम (ख़ूरू) व मैम (ख़ूरू) बच्चों की स्थिति की निगरानी तथा नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा शिक्षा, उद्योग सहित अन्य विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई और आगामी पंचायत चुनावों को लेकर आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्थाएं व पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश भी दिए.



सरकारी नौकरी के पीछे ही न भागें युवा, कौशल-प्रतिभा से रोजगार देने वाले बनें : भजनलाल

महानगर मेट्रो ब्यूरो

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को युवाओं से सरकारी नौकरी के पीछे ही भागने के बजाय अपने कौशल और प्रतिभा के दम पर रोजगार देने वाला बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। मुख्यमंत्री जयपुर के सिरसी रोड स्थित अलंकार महिला पीजी कॉलेज में 51वीं सब-जूनियर एवं जूनियर राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के समय पेपर लीक की घटनाएं होती थीं, जबकि उनकी सरकार के करीब ढाई साल के कार्यकाल में 415 परीक्षाएं आयोजित की गई हैं और एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर भी सरकार का ध्यान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग केवल राजस्थान ही नहीं, बल्कि भारत की प्राचीन संस्कृति और अनमोल धरोहर है। आज छोटे बच्चे और युवा योग को केवल अभ्यास के रूप में नहीं, बल्कि प्रतियोगिता के तौर पर भी अपना रहे हैं। जयपुर में 3 से 6 अक्टूबर तक आयोजित 51वीं सब-जूनियर एवं जूनियर राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में देशभर से खिलाड़ी पहुंचे। उन्होंने प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ियों की प्रतिभा और अनुशासन की सराहना की। भजनलाल शर्मा ने कहा कि योग और प्राणायाम आज करोड़ों लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं। योग शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का काम करता है। उन्होंने कहा कि योग को दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। 21 जून को पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और योग भारत की सीमाओं से निकलकर विश्व को जोड़ने का माध्यम बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्म की कुशलता ही वास्तविक योग है। जीवन में योग को अपनाने से शरीर स्वस्थ और मजबूत रहता है, तनाव कम होता है तथा सकारात्मकता बढ़ती है। उन्होंने बच्चों की एकाग्रता, अनुशासन और योग के प्रति उनकी रुचि की भी सराहना की।



धनतेरस के कारण टोंक में बदली पंचायत चुनाव की तारीख, अब 4 की जगह 3 नवंबर को मतदान

153 ग्राम पंचायतों में तीसरे चरण में होगी वोटिंग, जिला परिषद के 17 और पंचायत समिति के 86 वार्ड भी शामिल



महानगर मेट्रो ब्यूरो

टोंक। राज्य निर्वाचन विभाग ने पंचायती राज चुनावों के कार्यक्रम में बदलाव करते हुए टोंक जिले में तीसरे चरण के मतदान की तारीख एक दिन पहले कर दी है। धनतेरस के कारण अब 4 नवंबर की जगह 3 नवंबर को जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए मतदान कराया जाएगा। जिले में पंचायत चुनाव के तीसरे और चौथे चरण में मतदान होना है। चौथे चरण के चुनाव कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है तीसरे चरण में जिले की कुल 282 ग्राम पंचायतों में से 153 ग्राम पंचायतों के चुनाव होंगे। इसी चरण में जिला परिषद के कुल 31 वार्डों में से 17 वार्डों के लिए मतदान कराया जाएगा। इनमें पीपलू पंचायत समिति के चार, पचेवर के दो, मालपुरा का एक, देवली के पांच और उनियारा के पांच जिला परिषद वार्ड शामिल हैं। इसी तरह जिले की कुल 160 पंचायत समिति सीटों में से 86 वार्डों के चुनाव तीसरे चरण में होंगे। इनमें पीपलू पंचायत समिति के 17, पचेवर के 15, मालपुरा के छह, देवली के 25 और उनियारा के 23 पंचायत समिति वार्ड शामिल हैं।

19 अक्टूबर को जारी होगी अधिसूचना

तीसरे चरण के चुनाव के लिए 19 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी और इसी के साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 23 अक्टूबर निर्धारित की गई है। नामांकन पत्रों की जांच के बाद 26 अक्टूबर को नाम वापसी की प्रक्रिया होगी। इसके बाद 3 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। चुनाव परिणाम 20 नवंबर को जारी किए जाएंगे। धनतेरस को देखते हुए निर्वाचन विभाग ने तीसरे चरण के मतदान की तारीख में बदलाव किया है। पहले तीसरे चरण में 4 नवंबर को मतदान प्रस्तावित था, जिसे अब एक दिन पहले 3 नवंबर कर दिया गया है। वहीं चौथे चरण के चुनाव कार्यक्रम में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। जिले में चौथे चरण के चुनाव निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही कराए जाएंगे।

जर्जर स्कूल भवन पर लगाया ताला, अब माताजी के चबूतरे के पास चलेगा स्कूल

महानगर मेट्रो ब्यूरो

उदयपुर। भींडर क्षेत्र के वाणियातलाई ग्राम पंचायत स्थित गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नारदा में मंगलवार सुबह करीब 11 बजे बड़ा हादसा हो गया। क्लासरूम की छत का प्लास्टर अचानक गिरने से कमरे में पढ़ रहे 32 बच्चों में अफरा-तफरी मच गई। मलबे की चपेट में आने से तीन बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि दो बच्चों को मामूली चोट आई। घायल बच्चों को तत्काल भींडर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। हेडमास्टर लालसिंह शक्तावत ने बताया कि पहली कक्षा की छात्रा कृष्णा कुमारी, कार्तिक और पांचवीं कक्षा के छात्र गणेशलाल के सिर में चोट लगी है। तीनों का भींडर सरकारी अस्पताल में उपचार कराया गया। घटना के समय कमरे में अलग-अलग कक्षाओं के बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। अचानक तेज आवाज के साथ छत का प्लास्टर गिरने से बच्चों और शिक्षकों में हड़कंप मच गया।

घटना के बाद स्कूल भवन पर लगाया ताला

शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन के निर्देश के बाद एहतियात के तौर पर स्कूल भवन पर ताला लगा दिया गया है। अब स्कूल को यहां से शिफ्ट कर माताजी के चबूतरे के पास संचालित किया जाएगा। घटना की सूचना मिलने के बाद सीबीईओ भींडर राजेंद्र कुमार चौबीसा भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। हेडमास्टर ने बताया कि स्कूल पांचवीं कक्षा तक संचालित है और इसमें कुल 37 बच्चे नामांकित हैं। उन्होंने कहा कि जर्जर भवन को लेकर शिक्षा विभाग को पूर्व में सूचना दी जा चुकी थी। स्कूल भवन का निर्माण वर्ष 2001 में हुआ था। समय के साथ भवन की हालत खराब हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि भवन लंबे समय से जर्जर स्थिति में है और शिकायतों के बावजूद इसकी मरम्मत या सुधार पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। स्कूल में दो कमरे और एक बरामदा है और ग्रामीणों के अनुसार सभी की स्थिति जर्जर है। ग्रामीणों ने कहा कि गनीमत रही कि पूरी छत नहीं गिरी, वरना हादसा और गंभीर हो सकता था। घटना के बाद अभिभावकों और स्थानीय ग्रामीणों में भी नाराजगी है इस घटना ने झालावाड़ के मनोहरथाना ब्लॉक के पिपलोदी सरकारी स्कूल हादसे की याद दिला दी। 25 जुलाई 2025 को स्कूल भवन का हिस्सा गिरने से सात बच्चों की मौत हो गई थी और कई बच्चे गंभीर घायल हुए थे। हादसे के समय बच्चे कक्षा में बैठे थे और छत ढहने से 35 बच्चे मलबे में दब गए थे। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर बच्चों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया था।





क्लास में 32 बच्चे पढ़ रहे थे, अचानक छत का प्लास्टर गिरा

10 लाख के ओपन जिम उपकरण कबाड़, झाड़ियों और गंदगी से घिरा गुलाब बाग

महानगर मेट्रो ब्यूरो

माउंट आबू। पर्यटन नगरी माउंट आबू का गुलाब बाग (रोज गार्डन) इन दिनों बदहाली का शिकार है। सैलानियों और स्थानीय लोगों के लिए सैर-सपाटे और व्यायाम की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकसित किए गए इस गार्डन में लगाए गए 10 लाख रुपए से अधिक कीमत के ओपन जिम उपकरण खराब पड़े हैं। वहीं, गार्डन में जगह-जगह झाड़ियां उगने और गंदगी जमा होने से इसकी स्थिति भी खराब हो गई है। हालांकि, पिछले तीन दिनों से गार्डन में सफाई अभियान शुरू किया गया है। नगरपालिका अध्यक्ष सुनील आचार्य ने 10 से 15 दिनों में गार्डन की पूरी तरह सफाई कराने का दावा किया है। सफाई के बाद गार्डन को दोबारा व्यवस्थित करने की तैयारी की जा रही है।

2021 में हुआ था उद्घाटन

गुलाब बाग का उद्घाटन वर्ष 2021 में तत्कालीन राज्य मंत्री प्रमोद जैन भाया ने किया था। इस दौरान सिरोही विधायक संयम लोढ़ा और कांग्रेस विधायक रतन देवासी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। गार्डन को इस उद्देश्य से विकसित किया गया था कि यहां आने वाले सैलानियों और स्थानीय लोगों को घूमने के साथ व्यायाम की सुविधा भी मिल सके।



10 लाख से ज्यादा के उपकरण, अब खराब

नगरपालिका अध्यक्ष सुनील आचार्य के मुताबिक गार्डन में ओपन जिम के उपकरण लगाने पर 10 लाख रुपए से अधिक खर्च किए गए थे। लेकिन देखरेख के अभाव में ओपन जिम के सभी उपकरण खराब पड़े हैं। ऐसे में लाखों रुपए की लागत से तैयार की गई यह सुविधा फिलहाल लोगों के उपयोग में नहीं आ पा रही है। गार्डन में जगह-जगह झाड़ियां और गंदगी जमा होने से इसकी हालत खराब हो गई है। पिछले तीन दिनों से सफाई का काम चल रहा है। नगरपालिका की ओर से सफाई के बाद गार्डन को व्यवस्थित करने की तैयारी की जा रही है।

रिपेयर होंगे ठीक उपकरण, खराब की जगह नए लगेंगे

नगरपालिका अध्यक्ष सुनील आचार्य ने बताया कि 10 से 15 दिनों में गार्डन की पूरी तरह सफाई कर दी जाएगी। ओपन जिम के जो उपकरण मरम्मत योग्य हैं, उन्हें रिपेयर करवाकर दोबारा चालू किया जाएगा। वहीं, जो उपकरण पूरी तरह खराब हो चुके हैं, उनकी जगह नए उपकरण लगाए जाएंगे।

जालोर और बागरा को मिली नई 108 एंबुलेंस, मरीजों को समय पर मिलेगी चिकित्सा सुविधा

महानगर मेट्रो ब्यूरो

जालोर। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जालोर और बागरा क्षेत्र को नई 108 एंबुलेंस की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर से प्रदेश में 60 नई 108 एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें से दो एंबुलेंस जालोर जिले को मिली हैं। एक एंबुलेंस जालोर और दूसरी बागरा क्षेत्र के लिए उपलब्ध कराई गई है। जालोर और बागरा में पहले से संचालित पुरानी एंबुलेंस के बार-बार खराब होने के कारण मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। विशेषकर सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों और गंभीर मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने में दिक्कतें आती थीं। नई एंबुलेंस मिलने से अब मरीजों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। सोमवार को दोनों नई 108 एंबुलेंस जालोर पहुंचीं। जयपुर से एंबुलेंस लेकर पहुंचे पायलट पूरण सिंह और इकबाल खान तथा ईएमटी गौतम कुमार और दिनेश का चिकित्सा विभाग की टीम एवं स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। इस दौरान सभी को मिठाई खिलाकर बधाई दी गई और नई एंबुलेंस के साथ पायलट व ईएमटी का भी स्वागत किया गया। जालोर पहुंचने के बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) भैराराम जाणी ने दोनों नई 108 एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि नई एंबुलेंस के माध्यम से जरूरतमंद मरीजों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने और उन्हें अस्पताल तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। इससे आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद है।



धनतेरस पर नहीं होगी पंच-सरपंच की वोटिंग, अब उपसरपंच का चुनाव

महानगर मेट्रो ब्यूरो

जालोर। धनतेरस पर्व को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज चुनाव के कार्यक्रम में बदलाव किया है। जालोर जिले की 14 पंचायत समितियों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव दूसरे, तीसरे और चौथे चरण में कराए जाएंगे। संशोधित कार्यक्रम के तहत अब पोलिंग पार्टियां निर्धारित मतदान तिथि से एक दिन पहले रवाना होंगी। चुनाव कार्यक्रम में बदलाव के बाद पंच-सरपंच के लिए प्रस्तावित मतदान धनतेरस के दिन नहीं होगा। धनतेरस के दिन अब संबंधित पंचायतों में उपसरपंच का चुनाव कराया जाएगा। इससे पहले धनतेरस के दिन पंच-सरपंच के चुनाव कराए जाने थे। पर्व को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम में बदलाव किया है। जालोर जिले में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव तीन चरणों में होने हैं। इनमें जिले की 14 पंचायत समितियां शामिल हैं। चुनाव प्रक्रिया के दौरान मतदान दलों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने की व्यवस्था संशोधित कार्यक्रम के अनुसार की जाएगी। अब पोलिंग पार्टियां मतदान से एक दिन पहले अपने निर्धारित केंद्रों के लिए रवाना होंगी निर्वाचन कार्यक्रम में बदलाव के बाद संबंधित पंचायतों में मतदान और उपसरपंच के चुनाव की प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। निर्वाचन विभाग की ओर से चुनाव प्रक्रिया को लेकर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।

पेंशनर्स की समस्याओं पर चर्चा, नगरपालिका अध्यक्ष का किया स्वागत

महानगर मेट्रो ब्यूरो

माउंट आबू। राजस्थान पेंशनर्स समाज उपशाखा माउंट आबू की कार्यकारिणी की मासिक बैठक समाज अध्यक्ष बाबूसिंह परमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में संयोजक दलपत सिंह दहिया रहे। इस दौरान समाज के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। बैठक में पेंशनर्स से जुड़ी विभिन्न समस्याओं, उनके समाधान और जरूरी सुविधाओं को लेकर चर्चा की गई। बैठक के दौरान पेंशनर्स समाज की ओर से नवनिर्वाचित नगरपालिका अध्यक्ष सुनील आचार्य का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं पार्षद महेंद्र सिंह परमार का भी अभिनंदन किया गया। नगरपालिका आयुक्त त्रिकमदान चारण का माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर पेंशनर्स समाज के पदाधिकारियों ने नगरपालिका अध्यक्ष के समक्ष पेंशनर्स से जुड़ी विभिन्न समस्याएं और सुविधाओं की मांगें रखीं। उन्होंने पेंशनर्स के हित में जरूरी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने की मांग की। नगरपालिका अध्यक्ष सुनील आचार्य ने सभी मांगों पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। ग्लोबल अस्पताल में आरजीएचएस सुविधा शुरू कराने की बात नगरपालिका अध्यक्ष सुनील आचार्य ने पेंशनर्स को आश्वस्त किया कि ग्लोबल अस्पताल में आरजीएचएस की सुविधा शुरू कराने के लिए प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने पेंशनर्स के लिए समाज भवन उपलब्ध कराने को भी प्राथमिकता देने की बात कही। पेंशनर्स समाज के पदाधिकारियों ने नगरपालिका से सहयोग की अपेक्षा जताई। कार्यक्रम का संचालन समाज सचिव केके बारासेनी ने किया। बैठक में पेंशनर्स समाज के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे।



पेंशनर्स की मांगों पर नगरपालिका अध्यक्ष ने दिया आश्वासन

पेंशनर्स समाज ने नगरपालिका अध्यक्ष सुनील आचार्य के सामने विभिन्न समस्याएं और सुविधाओं की मांगें रखीं। आचार्य ने नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने ग्लोबल अस्पताल में आरजीएचएस सुविधा शुरू कराने के प्रयास करने तथा पेंशनर्स के लिए समाज भवन उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देने की बात कही

अहमदाबाद में माउंट आबू पालिका अध्यक्ष सुनील आचार्य का सम्मान

महानगर मेट्रो ब्यूरो

माउंट आबू। नगरपालिका अध्यक्ष सुनील आचार्य का अहमदाबाद में विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान स्वागत और सम्मान किया गया। इस दौरान गुजरात से माउंट आबू आने वाले पर्यटकों तथा राजस्थान और गुजरात के बीच पर्यटन संबंधों को और मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। अहमदाबाद में आयोजित धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों में आचार्य का अभिनंदन किया गया।रू शंकेश्वर तीर्थ गच्छाधिपति हेमचंद्र सूरीश्वर महाराज के 66वें जन्मोत्सव और गुरु प्रेम सूरीश्वर महाराज की 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष सुनील आचार्य का सम्मान किया गया। गच्छाधिपति हेमचंद्र सूरीश्वर महाराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष सिंघवी के परिवार सहित उद्योग जगत से जुड़े लोग मौजूद रहे। भाजपा राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य कमल रावल ने साफा पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर और स्मृति चिह्न भेंट कर आचार्य का अभिनंदन किया। इस दौरान माउंट आबू के विकास और गुजरात से आने वाले पर्यटकों को पर्यटन की नई पहचान से जोड़ने सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई।



राजस्थानी प्रवासी संघ ने भी किया स्वागत

अहमदाबाद में राजस्थानी प्रवासी संघ की ओर से भी नगरपालिका अध्यक्ष सुनील आचार्य का स्वागत किया गया। संघ प्रमुख तुलसीभाई पटेल के नेतृत्व में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया। इस दौरान संघ की ओर से मांग रखी गई कि गुजरात से माउंट आबू आने वाले पैदल संघों के साथ चलने वाले एक-दो वाहनों अथवा रथों से टोल नाके पर नगरपालिका शुल्क नहीं लिया जाए।

नगरपालिका अध्यक्ष आचार्य ने संघ की मांग को नगरपालिका की बैठक में रखने और नियमानुसार निर्णय लेने का आश्वासन दिया। इस दौरान माउंट आबू और गुजरात के बीच पुराने सामाजिक एवं पर्यटन संबंधों को लेकर भी चर्चा हुई। माउंट आबू का गुजरात से पुराना संबंध रहा है। राजस्थान में शामिल होने से पहले यह क्षेत्र गुजरात और उससे पहले मुंबई राज्य का हिस्सा रहा था। वर्ष 1863 में स्थापित माउंट आबू नगरपालिका को देश की पुरानी नगरपालिकाओं में गिना जाता है। गुजरात से हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक माउंट आबू पहुंचते हैं। ऐसे में अहमदाबाद में हुए स्वागत और कार्यक्रमों को पर्यटन तथा प्रवासी संपर्क के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अहमदाबाद के स्कूल में खतरनाक बवंडरः क्लास में घूरने की शिकायत पर भड़के शिक्षक छात्र को मारने दौड़े

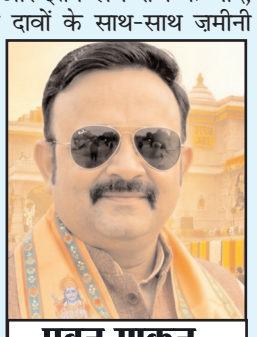
महानगर मेट्रो ब्यूरो

अहमदाबाद। संस्कारी नगरी अहमदाबाद के पूर्वी इलाके बापूनगर से शिक्षा जगत को झकझोर कर रख देने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली एक बेहद सनसनीखेज घटना सामने आई है। शहर के एक जाने-माने स्कूल के क्लासरूम में शुरू हुआ मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि पूरा स्कूल कैंपस अखाड़े में तब्दील हो गया। क्लास में एक छात्रा को घूरने के मामले को लेकर शुरू हुई कहासुनी में शिक्षक ने छात्र को समझाने के बजाय हिंसक रवैया अपनाया, जिसके बाद गुस्से में आगबबूला हुए नाबालिग छात्र ने अपने ही दोस्त को बेरहमी से पीटकर बेहोश कर दिया और एक अन्य छात्र की साइकिल तोड़कर जमकर आतंक मचाया। इस गंभीर और विवादित मामले में स्कूल प्रबंधन ने सख्त कदम उठाते हुए अल्पसंख्यक समाज के उस नाबालिग छात्र को तुरंत प्रभाव से स्कूल से बाहर का रास्ता दिखाते हुए एलसी (स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट - LC) थमा दिया है। प्राप्त विवरण के अनुसार, स्कूल के क्लासरूम में पढ़ाई के दौरान एक छात्रा ने सहपाठी नाबालिग छात्र पर गंभीर आरोप लगाया कि वह उसे लगातार घूर रहा है या ताक रहा है। छात्रा ने इस बात की शिकायत तुरंत क्लास के शिक्षक से कर दी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मामले को शांत कराने के बजाय संबंधित शिक्षक का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। शिक्षक ने छात्र को प्यार से समझाने या डांटने के बजाय सार्वजनिक रूप से उसे धमकाना शुरू कर दिया और गुस्से में आकर उसे मारने के लिए उसकी तरफ दौड़े। शिक्षक का यह आक्रामक और अशोभनीय व्यवहार देखकर पूरी क्लास के विद्यार्थियों में खौफ फैल गया और माहौल भारी तनावपूर्ण हो गया।



विकास की धुंध के सामने ज़मीनी हकीकतः 27 साल के राज के बाद, गुजरात की जनता अब सवाल पूछेगी

गांधीनगर गुजरात को देश के सबसे डेवलप्ड राज्यों में से एक मानने के दावे पिछले कई सालों से लगातार किए जा रहे हैं। 'गुजरात मॉडल', 'वाइब्रेंट गुजरात', इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दों को सरकार की कामयाबी के उदाहरण के तौर पर पेश किया जाता है। गुजरात में BJP सरकार लंबे समय से सत्ता में है और इतने लंबे राज के बाद, यह स्वाभाविक है कि सरकार के दावों के साथ-साथ ज़मीनी हकीकत का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। सवाल सरकार के हर विकास के काम को नकारने का नहीं है। गुजरात में कई सेक्टर में विकास हुआ है, बड़े प्रोजेक्ट आए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी काम हुआ है। लेकिन विकास की असली परीक्षा बड़े प्रोजेक्ट या बड़े प्रोग्राम से नहीं, बल्कि आम नागरिक की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितना बदलाव आया है, इससे होनी चाहिए। अगर विकास आम आदमी तक पहुँच गया है, तो हम अभी भी सड़क, पानी, सीवेज, ट्रैफिक, हेल्थ, एजुकेशन, रोज़गार और सरकारी ऑफिस में काम जैसी बेसिक समस्याओं की शिकायतें क्यों सुन रहे हैं? इन सवालों पर सीरियस चर्चा की ज़रूरत है। शराबबंदीः कानून सख्त है, लेकिन उसे लागू करना कितना असरदार है? गुजरात में शराबबंदी को लंबे समय से राज्य की एक खास पहचान के तौर पर पेश किया जाता रहा है। महात्मा गांधी की धरती पर शराबबंदी पर कानून होना गर्व की बात है। लेकिन ज़मीनी स्तर पर शराब की गैर-कानूनी बिक्री और नशे में धुत लोगों की हरकतों के जो आरोप समय-समय पर सामने आते हैं, वे चिंताजनक हैं। चाहे शहर हो या ग्रामीण इलाका, अगर गैर-कानूनी शराब आसानी से मिलने के आरोप सामने आते रहते हैं, तो सिर्फ़ शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई काफी नहीं है। पूरी सप्लाई चेन और उसे रोकने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के असर पर भी सवाल उठने चाहिए। कानून कागजों पर जितना सख्त हो, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़मीन पर उसे सख्ती से लागू किया जाए।रूयुवाओं को नशे से दूर रखने के लिए सिर्फ़ पुलिस एक्शन की ही ज़रूरत नहीं है, बल्कि एजुकेशन, अवेयरनेस और एक असरदार सोशल सिस्टम की भी ज़रूरत है गुजरात के कई शहरों और गांवों में सड़कों की क्वालिटी को लेकर लोग शिकायत करते रहते हैं। मॉनसून के बाद, पानी भरना और टूटी सड़कें आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती हैं। यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कोई सड़क बनने के तुरंत बाद टूट जाए तो इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? अगर जनता के पैसे से करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं, तो काम की क्वालिटी की भी उतनी ही जांच होनी चाहिए। अगर खराब काम हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्टर से लेकर संबंधित अधिकारियों तक की ज़िम्मेदारी तय होनी चाहिए। क्योंकि सड़क सिर्फ़ विकास की निशानी नहीं है; यह सीधे लोगों की सुरक्षा और जान से जुड़ा मुद्दा है। सरकारी दफ्तरों में आम आदमी की परेशानी आज के डिजिटल ज़माने में सरकार 'ई-गवर्नेंस' और ऑनलाइन सर्विस की बात करती है। लेकिन कई लोग आज भी छोटे-बड़े सरकारी कामों के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की शिकायत करते हैं। आम आदमी के लिए सरकार की असली इमेज बड़े मंत्रालय में नहीं, बल्कि तालुका ऑफिस, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, सरकारी अस्पताल और दूसरे लोकल दफ्तरों में बनती है।



पवन माकन
ग्रुप एडिटर, महानगर मेट्रो

अगर नागरिक का काम समय पर और ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा, तो उसे अच्छा शासन मिलेगा। अगर उसे बार-बार फाइल के लिए धक्के खाने पड़ेंगे, तो विकास के बड़े-बड़े दावे उसकी नज़रों में फीके पड़ जाएंगे। युवाओं का भविष्य सबसे बड़ा सवाल है
गुजरात के लाखों युवा पढ़ाई के बाद सरकारी और प्राइवेट नौकरियों की उम्मीद करते हैं। भर्ती परीक्षाओं में ट्रांसपेरेंसी और समय पर प्रोसेस उनकी सबसे बड़ी उम्मीदें हैं।
भर्ती में पेपर लीक या गड़बड़ी के किसी भी आरोप का असर सिर्फ एक परीक्षा पर नहीं पड़ता। वे हजारों उम्मीदवारों की मेहनत, समय और भरोसे पर असर डालते हैं। युवाओं को भाषण नहीं, मौके चाहिए। युवाओं को भरोसा नहीं, ट्रांसपेरेंट भर्ती चाहिए। युवाओं को विज्ञापन नहीं, रोजगार चाहिए। इस मुद्दे पर सरकार की ज़िम्मेदारी सबसे ज़्यादा है। गुजरात की तरक्की की चर्चा किसानों के बिना अधूरी है। किसान पानी, बिजली, खाद, बीज, फसल के दाम और मार्केट सिस्टम को लेकर लगातार परेशान रहते हैं। किसानों की इनकम और खेती की स्थिरता को मज़बूत किए बिना ग्रामीण गुजरात का हर तरह का विकास मुमकिन नहीं है। सरकार के लिए स्कीमों की घोषणा करना अच्छी बात है, लेकिन उनका असर आखिरी किसान तक पहुँच रहा है या नहीं, यह देखने के लिए रेगुलर जाँच भी ज़रूरी है। करप्शन के खिलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस ज़रूरी है किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है। जब सरकारी काम में गड़बड़ी, लापरवाही या करप्शन की शिकायत हो, तो जाँच जल्दी होनी चाहिए और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जनता को जनता के पैसे से चलने वाली हर स्कीम का हिसाब माँगने का अधिकार है। कितना पैसा मंजूर हुआ? कितना काम हुआ? काम की क्वालिटी क्या थी? और अगर कोई कमी पाई गई, तो ज़िम्मेदार पार्टी के खिलाफ़ क्या कार्रवाई की गई? इन सवालों के जवाब पब्लिक ऑर्डर का एक अहम हिस्सा होने चाहिए। डेवलपमेंट की अली परीक्षा होर्डिंग्स नहीं, क लोगों की ज़िंदगी है। बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ज़रूरी हैं। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। सड़कें, मेट्रो, एक्सप्रेसवे और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़रूरी हैं।

खेती से प्रोसेसिंग तक गोंडा की अर्थव्यवस्था को मिल रहा सहारा

दाल उद्योग से ग्रामीण कारोबार और रोजगार के अवसर बढ़े

गोंडा। जिले की अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। उपजाऊ कृषि भूमि और अनुकूल परिस्थितियों के चलते बड़ी संख्या में लोग दालों, अनाज और अन्य खाद्य फसलों की खेती से जुड़े हुए हैं। अब कृषि के साथ तेजी से बढ़ता फूड प्रोसेसिंग उद्योग भी स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। स्थानीय स्तर पर पैदा होने वाली कृषि उपज की प्रोसेसिंग होने से उसे बेहतर रूप में बाजार तक पहुंचाने के अवसर मिल रहे हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में कारोबार और रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं।

गोंडा में फूड प्रोसेसिंग उद्योग का एक प्रमुख आधार स्थानीय स्तर पर पैदा होने वाली दालें हैं। यहां अरहर, चना, मसूर, उड़द और मूंग जैसी दालों की सफाई से लेकर ग्रेडिंग, छिलका उतारने, मिलिंग, पॉलिशिंग और पैकेजिंग तक की प्रक्रिया की जाती है। इस प्रक्रिया के बाद तैयार दालें बेहतर पैकेजिंग के साथ बाजार में पहुंचती हैं। इससे स्थानीय कृषि उपज को वैल्यू एडिशन मिलता है और दालों से जुड़े कारोबार को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है।

कृषि उपज की स्थानीय स्तर पर प्रोसेसिंग होने से खेती और बाजार के बीच की कड़ी भी मजबूत हो रही है। किसानों को अपनी उपज के लिए स्थानीय स्तर पर ही बाजार उपलब्ध होता है, जबकि प्रोसेसिंग से जुड़े कामों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे कारोबारियों और उद्यमियों के लिए नए अवसर बनते हैं। मिलिंग, पैकेजिंग और अन्य गतिविधियों के जरिए स्थानीय स्तर पर कारोबार का दायरा बढ़ रहा है।

दाल उद्योग के विस्तार से किसानों के साथ मिलर्स और ग्रामीण उद्यमों को भी सहारा मिल रहा है। खेतों में तैयार होने वाली उपज जब स्थानीय स्तर पर प्रोसेस होकर बाजार तक पहुंचती है तो इससे पूरी वैल्यू चेन को मजबूती मिलती है। कृषि उत्पादन के साथ प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और विपणन जैसी गतिविधियां जुड़ने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं।

गोंडा में खेती और फूड प्रोसेसिंग का यह मेल स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। दालों की प्रोसेसिंग से जहां किसानों की उपज को बाजार से जोड़ने में मदद मिल रही है, वहीं ग्रामीण स्तर पर कारोबार और रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। स्थानीय कृषि उपज को स्थानीय स्तर पर ही मूल्यवर्धित उत्पाद में बदलने से किसानों, मिलर्स और छोटे उद्यमों के बीच आर्थिक गतिविधियों की कड़ी मजबूत हो रही है।



छह महीने में बंगाल में CC और 'लव जिहाद-लैंड जिहाद' पर सख्त कानून का दावा, शुभेंदु अधिकारी बोले- संविधान के अनुसार चलेगी सरकार

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में समान नागरिक संहिता झ लागू करने और 'लव जिहाद' तथा 'लैंड जिहाद' के खिलाफ सख्त कानून लाने का बड़ा ऐलान किया है। कोलकाता में विश्व हिंदू परिषद मशताब्दी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में उत्तराखंड और गुजरात की तर्ज पर UCC लागू किया जाएगा। उन्होंने इसके लिए छह महीने का समय मांगा। अधिकारी ने कहा कि UCC लागू होने के बाद 'लव जिहाद', 'लैंड जिहाद' और धार्मिक मतांतरण के खिलाफ सख्त प्रावधान लाने की दिशा में काम किया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार संविधान के अनुसार काम करेगी, लेकिन भारतीय संस्कृति, सनातन परंपराओं, मंदिरों, मठों और धार्मिक विरासत पर किसी भी तरह का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार स्वामी विवेकानंद और महाप्रभु श्री चैतन्य जैसे आध्यात्मिक महापुरुषों से जुड़ी विरासत की भी रक्षा करेगी। उनके बयान के मुताबिक सरकार का काम संविधान के दायरे में रहकर होगा, लेकिन संस्कृति और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जाएगी। पश्चिम बंगाल में UCC को लेकर सरकार पहले ही प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। राज्य सरकार ने UCC के मसौदे की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। समिति का काम प्रस्तावित कानून के मसौदे की समीक्षा करना और उसे अंतिम रूप देने की दिशा में सुझाव देना है। सरकारी अधिसूचना के अनुसार प्रस्तावित UCC का उद्देश्य अलग-अलग समुदायों के लिए नागरिक कानूनों में एकरूपता लाना है। इसके दायरे में शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे विषय शामिल होंगे। यानी इन नागरिक मामलों में धर्म के आधार पर अलग-अलग नियमों के स्थान पर समान प्रावधान लागू करने की दिशा में व्यवस्था तैयार की जाएगी। UCC को 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रमुख चुनावी वादों में भी शामिल किया गया था। समान नागरिक संहिता का मूल उद्देश्य विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे नागरिक मामलों में सभी समुदायों के लिए समान नियम लागू करना है। इसके समर्थकों का तर्क है कि इससे अलग-अलग समुदायों के लिए अलग नागरिक नियमों की व्यवस्था कम होगी और महिलाओं के अधिकारों में समानता को बढ़ावा मिल सकता है। वहीं, इसके विरोध या चिंता जताने वालों का तर्क है कि अलग-अलग धार्मिक और आदिवासी समुदायों की अपनी परंपराएं और प्रथाएं हैं। ऐसे में एक समान कानून लागू करने से उनके व्यक्तिगत कानूनों और पारंपरिक व्यवस्थाओं पर असर पड़ सकता है। इसलिए पश्चिम बंगाल में UCC के मसौदे के प्रावधान और उसमें विभिन्न समुदायों के लिए किए जाने वाले प्रबंध महत्वपूर्ण होंगे। संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य को पूरे देश में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास करने का निर्देश दिया गया है। इसी संवैधानिक प्रावधान के संदर्भ में देश में लंबे समय से UCC को लेकर चर्चा होती रही है। ससस उत्तराखंड और गुजरात का उदाहरण शुभेंदु अधिकारी ने UCC लागू करने के लिए उत्तराखंड और गुजरात का उदाहरण दिया है। उत्तराखंड आजादी के बादUCC लागू करने वाला पहला राज्य बना। वहीं गुजरात ने 2026 में UCC विधेयक पारित किया था और सितंबर 2026 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद उसके लागू होने की प्रक्रिया आगे बढ़ी। गुजरात के कानून में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और कुछ अन्य नागरिक मामलों को लेकर समान प्रावधान किए गए हैं। बंगाल में अब सरकार की ओर से गठित समिति के मसौदे और उसके बाद बनने वाली कानूनी प्रक्रिया पर नजर रहेगी। अधिकारी के छह महीने के ऐलान के बाद UCC के साथ-साथ 'लव जिहाद', 'लैंड जिहाद' और धार्मिक मतांतरण को लेकर प्रस्तावित कानून भी राज्य की राजनीति और कानूनी बहस का प्रमुख विषय बन सकते हैं। देश में गोवा में लंबे समय से समान नागरिक कानून जैसी व्यवस्था लागू है, जिसकी ऐतिहासिक जड़ें पुर्तगाली सिविल कोड से जुड़ी हैं। हालांकि आजादी के बाद उत्तराखंड को UCC लागू करने वाला पहला राज्य माना गया। भारत में समान नागरिक संहिता को लेकर बहस आजादी से पहले से चली आ रही है। 19वीं सदी में देश के लिए समान कानूनों की जरूरत पर चर्चा शुरू हुई थी, जबकि बाद के दौर में व्यक्तिगत कानूनों को लेकर अलग-अलग व्यवस्थाएं बनी रहीं। ाजादी के बाद हिंदू संहिता विधेयक के जरिए भी व्यक्तिगत कानूनों में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। इसका उद्देश्य हिंदू समाज में विवाह, उत्तराधिकार और महिलाओं से जुड़े अधिकारों सहित कई सामाजिक-कानूनी मामलों में बदलाव लाना था। अब पश्चिम बंगाल में UCC को लेकर सरकार के स्तर पर प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के छह महीने के ऐलान के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रस्तावित UCC का अंतिम स्वरूप क्या रहता है और 'लव जिहाद', 'लैंड जिहाद' तथा धार्मिक मतांतरण से संबंधित कानूनों में सरकार किन प्रावधानों को शामिल करती है।



20 साल पुराने मामले में CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ फिर खुलेगी जांच

तिरुवनंतपुरम। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ करीब दो दशक पुराने एक मामले की दोबारा जांच के आदेश के बाद राजनीतिक विवाद और तेज हो गया है। केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने 2006 में मलेशियाई सिविल इंजीनियर ली सी बीन की आत्महत्या से जुड़े मामले में विजिलेंस जांच फिर से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उस समय ज्ञानेश कुमार केरल के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के सचिव थे। मामला केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (केएसटीपी) के तहत अंगमाली से तिरुवनंतपुरम तक एमसी रोड के उन्नयन से जुड़ा है। शिकायत के मुताबिक, ली सी बीन उस समय सड़क परियोजना से जुड़े PATI-BEL कंसोर्टियम के साथ काम कर रहे थे। आरोप है कि उन्होंने सड़क निर्माण का भुगतान जारी करने के बदले तत्कालीन पीडब्ल्यूडी सचिव ज्ञानेश कुमार पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। इसके बाद इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली थी। मामले में उस समय केरल विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो ने शुरुआती जांच शुरू की थी, लेकिन यह जांच पूरी नहीं हो सकी। अब राज्य सरकार ने पुरानी फाइलें दोबारा तलब कर जांच आगे बढ़ाने का फैसला किया है। गृह मंत्री रमेश चेन्निथला के मुताबिक उन्हें शिकायत मिली थी कि 2006 में हुई विजिलेंस जांच बाहरी दबाव के कारण प्रभावित हुई थी। इसके बाद उन्होंने मामले की दोबारा जांच कराने का आदेश दिया। विजिलेंस अब पूरे प्रकरण की जांच करेगी और जांच में यदि किसी तरह की अनियमितता या कानूनी उल्लंघन सामने आता है तो आगे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यह जांच ऐसे समय दोबारा शुरू हुई है, जब ज्ञानेश कुमार पहले से ही विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर विपक्ष के निशाने पर हैं। ससस 215 करोड़ की एमसी रोड परियोजना से जुड़ा था मामला 2006 में अंगमाली से तिरुवनंतपुरम तक एमसी रोड के पुनर्निर्माण और उन्नयन का काम शुरू हुआ था। परियोजना की लागत करीब 215 करोड़ रुपये बताई गई थी और इसके लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता मिली थी। इस परियोजना का संचालन केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के माध्यम से किया जा रहा था। इसी परियोजना से जुड़े कंसोर्टियम में काम करने वाले मलेशियाई इंजीनियर ली सी बीन की आत्महत्या के बाद मामला सामने आया था। शिकायत और उस समय सामने आए आरोपों में तत्कालीन पीडब्ल्यूडी सचिव ज्ञानेश कुमार का नाम आया था। हालांकि शुरुआती जांच के बाद मामला आगे नहीं बढ़ सका। अब करीब 20 साल बाद फाइलें दोबारा खुलने से पूरे प्रकरण की जांच नए सिरे से होने जा रही है।

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ केरल में पुरानी जांच दोबारा शुरू होने के साथ ही चुनाव आयोग में एसआईआर को लेकर सामने आई अंदरूनी आपत्तियों ने भी विवाद को बढ़ा दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार आयोग के फैसलों और आदेशों पर लिखित आपत्तियां दर्ज की थीं। इनमें मतदाता सूची में नाम जोड़ने-हटाने, नए मतदाताओं के पंजीकरण, एसआईआर प्रक्रिया और मतदाता डेटा के प्रबंधन जैसे मुद्दे शामिल थे। रिपोर्ट के अनुसार दोनों चुनाव आयुक्तों ने कुछ फैसलों को लेकर यह सवाल उठाया कि उन्हें निर्णयों की जानकारी पहले क्यों नहीं दी गई। उन्होंने नए मतदाताओं के लिए फॉर्म-6 में अतिरिक्त जानकारी मांगे जाने, मतदाता डेटाबेस के केंद्रीकरण और चुनावी सॉफ्टवेयर से जुड़े कुछ मुद्दों पर भी आपत्ति दर्ज की थी। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से यह कहा गया कि आयोग के भीतर विचार-विमर्श और असहमति सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है तथा महत्वपूर्ण फैसले पूर्ण आयोग द्वारा लिए गए। एसआईआर को लेकर दर्ज आपत्तियों में फॉर्म-6 में बदलाव का मुद्दा प्रमुख था। रिपोर्ट के मुताबिक नए मतदाताओं से पिछली एसआईआर सूची में स्वयं या परिवार के किसी सदस्य का नाम होने की जानकारी मांगने पर सवाल उठाए गए। इसके अलावा मतदाता डेटाबेस के नियंत्रण को लेकर भी चिंता जताई गई और यह सवाल सामने आया कि राज्यों की भूमिका सीमित करते हुए डेटा तक पहुंच का केंद्रीकरण क्यों किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में हटाए गए नामों से जुड़ी बड़ी संख्या में अपीलों और गोवा में सॉफ्टवेयर संबंधी समस्या के कारण योग्य पाए गए कुछ मतदाताओं के नाम अंतिम सूची में शामिल नहीं हो पाने को लेकर भी सवाल उठाए गए। इन आपत्तियों के सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग तेज कर दी।
एसआईआर विवाद को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं। राहुल गांधी ने मतदाता सूची और एसआईआर से जुड़े विवादों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर 'वोट चोरी' का आरोप लगाया और ज्ञानेश कुमार को लेकर भी तीखी टिप्पणी की।

NEET-UG 2026 पेपर लीक केस में CBI की दूसरी और अंतिम चार्जशीट जल्द

नई दिल्लीNEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो एक सप्ताह के भीतर दूसरी और अंतिम चार्जशीट दाखिल कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जांच एजेंसी की इस चार्जशीट में केंद्र सरकार या राष्ट्रीय परीक्षा एजेंस के अधिकारियों को आरोपी नहीं बनाया जाएगा। मामले में NTA की ओर से नियुक्त किए गए विषय विशेषज्ञों, कोचिंग सेंटर संचालकों, बिचौलियों और परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को आरोपी बनाए जाने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही एजेंसी की ओर से पेपर लीक की पूरी साजिश और इसमें शामिल लोगों की भूमिका को लेकर जांच को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
CBI ने इस मामले में पहली चार्जशीट 28 जुलाई को दाखिल की थी। उस समय एजेंसी ने स्पष्ट किया था कि मामले में शामिल अन्य साजिशकर्ताओं की भूमिका की जांच जारी रखी गई है। जांच एजेंसी को केंद्रीय फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी गवर्नमेंट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन्ड डॉक्यूमेंट्स और दिल्ली विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों की राय से जुड़ी रिपोर्ट का इंतजार था। इन रिपोर्टों के आधार पर जांच के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को अंतिम रूप दिए जाने की बात सामने आई है।
CBI की पहली चार्जशीट में ह्श्वश्वञ्ज-ल 2026 का प्रश्नपत्र तैयार करने की प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी का भी उल्लेख किया गया था। जांच के मुताबिक ने प्रश्नपत्र तैयार करने के कई चरणों में उन्हीं तीन विषय विशेषज्ञों को दोबारा जिम्मेदारी दी थी। एजेंसी ने इस पूरी प्रक्रिया और उससे जुड़े लोगों की भूमिका की जांच की। जांच के दौरान आरोपियों के खिलाफ वित्तीय लेन-देन और संपत्तियों से जुड़े साक्ष्यों को भी खंगाला गया। CBI ने 13 आरोपियों के बैंक खाते और बैंक लॉकर फ्रीज किए हैं। इसके अलावा एक डीमैट खाते को भी फ्रीज किए जाने की जानकारी सामने आई है। एजेंसी ने मामले में आर्थिक लेन-देन से जुड़े साक्ष्यों को जांच का हिस्सा बनाया है।
पेपर लीक मामले में CBI ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और सबूत मिटाने से संबंधित धाराएं लगाई हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के प्रावधानों के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। एजेंसी की जांच का फोकस प्रश्नपत्र तक पहुंच, उसे आगे पहुंचाने की प्रक्रिया, इसमें शामिल बिचौलियों, कोचिंग सेंटर संचालकों, विषय विशेषज्ञों और अभ्यर्थियों के बीच कथित संपर्क तथा आर्थिक लेन-देन पर रहा है। दूसरी चार्जशीट दाखिल होने के बाद मामले में जांच एजेंसी की ओर से अब तक जुटाए गए साक्ष्यों और आरोपियों की भूमिका का विस्तृत ब्यौरा सामने आने की उम्मीद है। NEET-UG 2026 परीक्षा 3 मई 2026 को आयोजित की गई थी। परीक्षा के बाद प्रश्नपत्र लीक होने के आरोप सामने आए। विवाद बढ़ने के बाद सरकार और ने परीक्षा रद्द कर दी थी। इसके बाद 21 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित कराई गई।



(बुधवार) 7 अक्टूबर 2026

मेष — आज आपकी सूझबूझ कई परेशानियों को दूर करेगी, आर्थिक मामलों में लाभ होगा और जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर होंगे

वृषभ — कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं

मिथुन — रुके हुए काम पूरे होने से मन प्रसन्न रहेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा और धन संबंधी मामलों में सावधानी लाभदायक रहेगी

कर्क — जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी; धन संबंधी फैसले सोच-समझकर लें और स्वास्थ्य पर ध्यान दें

सिंह — नए अवसर सामने आएंगे और कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा की सराहना होगी, यात्रा की योजना बन सकती है और मन उत्साहित रहेगा

कन्या — नई योजना पर काम शुरू करने का अवसर मिलेगा, बातचीत से बिगड़े काम बनेंगे और व्यापार में लाभ की संभावना है

तुला — दिन की शुरुआत कुछ व्यस्तता के साथ होगी, लेकिन महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे होंगे; मित्रों और परिवार से सहयोग मिलेगा।

वृश्चिक — मेहनत और आत्मविश्वास से महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे, अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आय के नए रास्ते खुल सकते हैं

धनु — पुराने विवादों का समाधान निकल सकता है, काम में सफलता मिलेगी और आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए किए प्रयास सफल होंगे

मकर — आज भावनाओं में बहने के बजाय समझदारी से निर्णय लें, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी और परिवार में सुखद माहौल रहेगा

कुंभ — सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, करियर में नई संभावना मिल सकती है और अचानक मिलने वाली अच्छी खबर मन को प्रसन्न करेगी

मीन — नौकरी-व्यवसाय में सकारात्मक बदलाव के संकेत हैं, किसी पुराने परिचित से लाभ मिल सकता है और परिवार में खुशी बनी रहेगी

शाहजहांपुर में महिला की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा

महानगर मेट्रो ब्यूरो

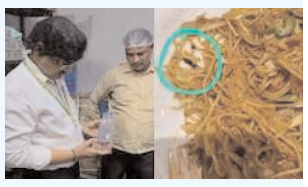
शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक निजी अस्पताल में महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। चौक कोतवाली क्षेत्र स्थित शेखर अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई थी। इसके बाद मृतका के परिजनों ने इलाज में लापरवाही और महिला की मौत की जानकारी समय पर नहीं देने का आरोप लगाते हुए डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ से मारपीट कर दी। आरोप है कि पुलिस के मौके पर पहुंचने के बावजूद परिजनों ने अस्पताल के कर्मचारियों को सड़क पर दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। महिला की मौत की जानकारी मिलने के बाद परिजन आक्रोशित हो गए। उनका आरोप था कि अस्पताल के मेडिकल स्टाफ ने महिला की हालत और मौत के बारे में उन्हें समय पर जानकारी नहीं दी। इसके अलावा परिजनों ने इलाज के दौरान लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया। इन्हीं आरोपों को लेकर अस्पताल में विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते स्थिति हंगामे में बदल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने की कोशिश की। हालांकि, आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में ही कुछ परिजनों ने डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि अस्पताल के कर्मचारियों को बचाने के लिए पुलिसकर्मियों ने बीच-बचाव का प्रयास किया, लेकिन आक्रोशित लोग लगातार मारपीट करते रहे। हंगामे के दौरान कुछ मेडिकल स्टाफ अस्पताल से बाहर निकलकर सड़क की ओर भागते नजर आए। परिजनों ने कथित तौर पर उनका पीछा किया और सड़क पर भी उनके साथ मारपीट की। घटना का वीडियो किसी व्यक्ति ने बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। वीडियो में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में विवाद और मारपीट का घटनाक्रम दिखाई देने का दावा किया जा रहा है।



गढ़मुक्तेश्वर के रेस्टोरेंट में नूडल्स की प्लेट में मिला कथित काला कीड़ा

महानगर मेट्रो ब्यूरो

गढ़मुक्तेश्वर। हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर स्थित बीकानेर रेस्टोरेंट में नूडल्स की प्लेट में कथित तौर पर काला कीड़ा मिलने का मामला सामने आया है। रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंची महिला ने नूडल्स का ऑर्डर किया था। खाना खाते समय उसकी नजर प्लेट में पड़े काले कीड़े पर गई। इसके बाद महिला ने तत्काल रेस्टोरेंट के मैनेजर और स्टाफ से इसकी शिकायत की। महिला का आरोप है कि शिकायत करने के दौरान रेस्टोरेंट के स्टाफ का व्यवहार उसके प्रति ठीक नहीं रहा। मामले को लेकर महिला ने गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत सामने आने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग भी सक्रिय हुआ और टीम ने रेस्टोरेंट पहुंचकर निरीक्षण किया। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रेस्टोरेंट में खाद्य पदार्थों की जांच की और संबंधित खाद्य पदार्थ का नमूना लिया। विभाग की ओर से नमूने को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। अब प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि नूडल्स में मिला पदार्थ वास्तव में क्या था और खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन हुआ है या नहीं। खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त चंद्रशेखर मिश्रा ने बताया कि खाद्य पदार्थ का नमूना जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। रिपोर्ट के आधार पर ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। यदि जांच में खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया जाता है तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। लहाल नूडल्स की प्लेट में कथित तौर पर कीड़ा मिलने के मामले ने रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।



अवधी गायक संजय यदुवंशी के घर रात में पुलिस की दबिश

महानगर मेट्रो ब्यूरो

सुल्तानपुर। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में अवधी गायक संजय यदुवंशी के घर सोमवार देर रात पुलिस की दबिश का मामला सामने आया है। धम्मौर थाना क्षेत्र के उघड़पुर गांव में पुलिस टीम संजय यदुवंशी की तलाश में पहुंची थी। बताया गया कि इस दौरान संजय घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस की कार्रवाई के दौरान उनके पिता, मां और भाई की पुलिसकर्मियों से तीखी बहस हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद मामला चर्चा में आ गया है। परिजनों का आरोप है कि पुलिसकर्मी रात करीब 12 बजे घर पहुंचे और दीवार कूदकर अंदर आने की कोशिश की। परिवार की ओर से पुलिस पर अभद्रता करने के भी आरोप लगाए गए हैं। इस दौरान घर के लोगों और पुलिसकर्मियों के बीच काफी देर तक बहस हुई। वीडियो सामने आने के बाद संजय यदुवंशी के पिता ने भी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए अपने बेटे को लेकर आशंका जताई है। मामले में सुल्तानपुर पुलिस की ओर से सफाई दी गई है। धम्मौर के सीओ रितिक कपूर के अनुसार, थाना कोतवाली नगर में जफरुल हसन ने अपने बेटे शबीब रजा के साथ मारपीट और जानलेवा हमले के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में संजय यदुवंशी आरोपी हैं और वांछित चल रहे हैं। इसी मामले की विवेचना और आरोपी की तलाश के दौरान पुलिस टीम उनके घर पहुंची थी। पुलिस के अनुसार, संजय यदुवंशी के खिलाफ अलग-अलग थानों में भी मामले दर्ज हैं। सीओ बल्दीराय आशुतोष कुमार ने बताया कि 7 सितंबर 2026 को अमहट निवासी जफूर हसन ने धम्मौर थाने में अपने साथ मारपीट के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस के मुताबिक इस मामले में भी संजय यदुवंशी समेत अन्य आरोपी वांछित चल रहे हैं और उनकी तलाश की जा रही है। वहीं, संजय यदुवंशी ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो साझा किया है। उन्होंने धम्मौर थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए और उन्हें निलंबित करने की मांग की। संजय ने कहा कि यदि थाना प्रभारी को निलंबित नहीं किया गया तो वह लखनऊ में धरना देंगे। उन्होंने पुलिस की देर रात की कार्रवाई और घर में प्रवेश करने के तरीके पर भी आपत्ति जताई। संजय यदुवंशी के परिवार और पुलिस के अलग-अलग दावों के बीच अब इस मामले को लेकर विवाद बढ़ गया है। परिवार का कहना है कि पुलिस ने जिस तरीके से रात में दबिश दी, वह उचित नहीं था, जबकि पुलिस का कहना है कि दर्ज मामलों में वांछित आरोपी की तलाश के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जा रही थी। पुलिस ने परिवार की ओर से लगाए गए अन्य आरोपों को असत्य और निराधार बताया है। मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो को साझा किया है। उन्होंने वीडियो के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। इससे मामला राजनीतिक रूप से भी चर्चा में आ गया है। संजय यदुवंशी का राजनीतिक संपर्क भी पहले सामने आ चुका है। इसी साल जनवरी में उन्होंने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। उस मुलाकात की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर सामने आई थी।



आदिवासी किसान का ट्रैक्टर छुड़ाने के लिए 10 घंटे धरने पर बैठे भाजपा विधायक, मुख्यमंत्री के फोन के बाद खत्म हुआ प्रदर्शन

महानगर मेट्रो ब्यूरो

सतना। मध्यप्रदेश के सतना जिले के चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के मझगवां में वन विभाग द्वारा ट्रैक्टर जब्त किए जाने को लेकर सोमवार को जमकर विवाद हुआ। कार्रवाई के विरोध में चित्रकूट से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार वन विभाग के रेंज कार्यालय पहुंच गए और ट्रैक्टर तुरंत छोड़ने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। विधायक करीब 10 घंटे तक धरने पर बैठे रहे। उनके समर्थन में बड़ी संख्या में आदिवासी ग्रामीण भी वन विभाग के कार्यालय परिसर में जमा हो गए। देर रात मामले ने इतना तूल पकड़ा कि प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालनी पड़ी। मामला मझगवां वन परिक्षेत्र के करिया बीट के चुनहाहार क्षेत्र का बताया जा रहा है। वन विभाग के अनुसार, कक्ष क्रमांक पी-830 में वन भूमि पर ट्रैक्टर से कथित तौर पर जुताई किए जाने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों का कहना है कि मौके पर जुताई कर रहे लोगों से जमीन से संबंधित वैध दस्तावेज मांगे गए, लेकिन दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इसके बाद विभाग ने जुताई में इस्तेमाल किए जा रहे बिना नंबर के ट्रैक्टर को जब्त कर वन अपराध का प्रकरण दर्ज किया। वन विभाग की कार्रवाई के बाद यह मामला राजनीतिक विवाद में बदल गया। सोमवार दोपहर करीब 2 बजे विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार मझगवां रेंज कार्यालय पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों के सामने ट्रैक्टर को तत्काल छोड़ने की मांग रखी। विधायक का कहना था कि कार्रवाई गरीब और आदिवासी किसान को परेशान करने वाली है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जब तक ट्रैक्टर नहीं छोड़ा जाता, तब तक वह मौके से नहीं जाएंगे। इसके बाद विधायक कार्यालय परिसर में ही धरने पर बैठ गए। धरने के दौरान विधायक और वन विभाग के अधिकारियों के बीच तीखी बहस भी हुई। विधायक ने कथित तौर पर अधिकारियों से कहा कि या तो ट्रैक्टर छोड़ा जाए या फिर वह रात भी वहीं बैठेंगे। विधायक का तर्क था कि किसान अपनी जरूरत के अनुसार दिन या रात में खेत की जुताई कर सकता है और केवल रात में ट्रैक्टर चलाने को नियम का उल्लंघन बताकर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। वहीं, वन विभाग के अधिकारियों का कहना था कि कार्रवाई रात में ट्रैक्टर चलाने को लेकर नहीं, बल्कि वन भूमि पर कथित अवैध जुताई को लेकर की गई है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, करिया बीट के चुनहाहार इलाके में वन भूमि पर जुताई कर अतिक्रमण के प्रयास की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची टीम ने स्थिति का निरीक्षण किया और भूमि से संबंधित दस्तावेज मांगे। दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाने के बाद भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत वन अपराध का प्रकरण दर्ज किया गया। विभाग का कहना है कि ट्रैक्टर को कानूनी प्रक्रिया के तहत जब्त किया गया है और आगे की कार्रवाई भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही होगी। उधर, विधायक के धरने की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में आदिवासी ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों और विधायक के समर्थन में लोगों के जमा होने से वन विभाग कार्यालय परिसर में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। प्रशासन के अधिकारियों ने विधायक को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह ट्रैक्टर छोड़े जाने की मांग।



अमेठी में नाबालिग के साथ बंदूक की नोक पर दुष्कर्म का आरोप, आरोपी फरार

15 वर्षीय लड़की के घर में घुसकर वारदात का आरोप, मां को भी जान से मारने की धमकी; 5 अक्टूबर को दर्ज हुई प्राथमिकी

महानगर मेट्रो ब्यूरो

अमेठी। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के रामगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर बंदूक की नोक पर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि उसी गांव का करीब साढ़े 17 साल का एक नाबालिग लड़का 3 अक्टूबर की रात करीब डेढ़ बजे लड़की के घर में घुसा और हथियार के बल पर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, घटना के दौरान नाबालिग लड़की ने शोर मचाया। उसकी आवाज सुनकर उसकी मां मौके पर पहुंची। आरोप है कि आरोपी ने पीड़िता की मां को भी हथियार दिखाकर धमकाया और कहा कि अगर घटना के बारे में किसी को बताया गया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। इस धमकी के बाद आरोपी वहां से भाग गया। घटना के बाद परिवार ने मामले की जानकारी जुटाई और पुलिस से शिकायत की। मामले में पीड़िता की मां ने 5 अक्टूबर को रामगंज थाने पहुंचकर पुलिस को लिखित शिकायत दी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि गांव का ही नाबालिग लड़का रात के समय घर में घुसा और बंदूक के बल पर उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। घटना में आरोपी की भूमिका और वारदात से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है। रामगंज थाना प्रभारी राम राज कुशवाहा ने बताया कि नाबालिग लड़की की मां की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार, पीड़िता की चिकित्सकीय जांच कराई जा रही है। जांच के दौरान पीड़िता और उसके परिवार के बयान भी लिए जा रहे हैं। पुलिस घटनास्थल से जुड़े तथ्यों और मामले में सामने आए आरोपों की भी पड़ताल कर रही है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती आरोपी को जल्द पकड़ना है। घटना के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है। पुलिस टीमों को उसकी तलाश में लगाया गया है। उसके संभावित ठिकानों और परिचितों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घटना में इस्तेमाल किए गए कथित हथियार की स्थिति क्या है और वह आरोपी तक कैसे पहुंचा। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस पीड़िता की पहचान और उससे जुड़ी निजी जानकारी को सार्वजनिक नहीं कर रही है। जांच के दौरान चिकित्सकीय रिपोर्ट और पीड़िता के बयानों को भी महत्वपूर्ण साक्ष्य के तौर पर देखा जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद गांव में भी मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। पीड़ित परिवार आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल मामले में आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। जांच पूरी होने के बाद ही घटना से जुड़े सभी तथ्यों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।



20 रुपए के मोमोज पर बवाल! छात्र पर दुकानदार ने फेंका खौलता तेल, चेहरा-कान गंभीर रूप से झुलसे

महानगर मेट्रो ब्यूरो

ग्वालियर। हजीरा थाना क्षेत्र के पुरानी रेशम मिल चौराहे पर 20 रुपए के मोमोज को लेकर शुरू हुआ एक मामूली विवाद देखते ही देखते गंभीर घटना में बदल गया। आरोप है कि मोमोज की प्लेट में संख्या कम होने की शिकायत करने पर ठेले वाले ने 18 वर्षीय छात्र पर कढ़ाई में रखा खौलता हुआ तेल फेंक दिया। गर्म तेल की चपेट में आने से छात्र का चेहरा और कान गंभीर रूप से झुलस गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आरोपी ठेला छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पीड़ित छात्र की पहचान शिवा उर्फ चेतन भदौरिया, उम्र 18 वर्ष, निवासी प्रगति नगर, न्यू रेशम मिल के रूप में हुई है। बताया गया कि शिवा अपने दोस्तों गोलू खान और विकास राजपूत के साथ जिम जाने के लिए घर से निकला था। तीनों दोस्त पुरानी रेशम मिल चौराहे से गुजर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने वहां मोमोज का ठेला देखा और कुछ खाने के लिए रुक गए। शिवा ने ठेले पर 20 रुपए के मोमोज का ऑर्डर किया था। शिवा और उसके दोस्तों के सामने जब मोमोज की प्लेट पहुंची तो उसमें उन्हें अपेक्षा से कम मोमोज दिखाई दिए। इसी बात को लेकर शिवा ने ठेले वाले अंकित से शिकायत की। शुरुआत में यह मामला सामान्य कहासुनी तक सीमित बताया जा रहा है। हालांकि, कुछ ही देर में दोनों के बीच बहस बढ़ने लगी। आसपास मौजूद लोगों के मुताबिक, बातचीत के दौरान दोनों पक्षों के बीच आवाज ऊंची होने लगी और मौके पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। पुलिस को मिली जानकारी और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विवाद के दौरान ठेले वाले अंकित ने शिवा के साथ कथित तौर पर गाली-गलौज की। शिवा ने इसका विरोध किया तो कहासुनी और बढ़ गई। आरोप है कि इसी दौरान अंकित ने शिवा को धक्का दिया। इसके बाद विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया और आरोप है कि अंकित ने मोमोज बनाने के लिए रखी कढ़ाई से खौलता हुआ तेल उठाकर शिवा की ओर फेंक दिया। गर्म तेल सीधे शिवा के शरीर के ऊपरी हिस्से पर जा गिरा। इससे उसके चेहरे और कान गंभीर रूप से झुलस गए। अचानक हुई इस घटना से वहां मौजूद शिवा के दोस्तों और आसपास के लोगों में भी हड़कंप मच गया। बताया गया कि शिवा दर्द से परेशान हो गया और उसके दोस्तों ने तत्काल उसकी मदद करने की कोशिश की। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। घटना के बाद आरोपी ठेले वाला मौके पर नहीं मिला। आरोप है कि घटना के तुरंत बाद वह अपना ठेला वहीं छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल की जानकारी ली और आसपास के लोगों से पूछताछ की। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि घटना के समय मौके पर कितने लोग मौजूद थे और विवाद के दौरान वास्तव में क्या-क्या हुआ। पुलिस के लिए अब घटना के पूरे क्रम को स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है। शुरुआती जानकारी में विवाद की वजह 20 रुपए के मोमोज और प्लेट में कम संख्या को बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कहासुनी किस बात को लेकर बढ़ी और क्या विवाद से पहले दोनों पक्षों के बीच कोई अन्य बात को लेकर कहासुनी हुई थी। घटना के बाद पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल सकती है। चौराहे और आसपास की दुकानों पर लगे कैमरों से घटना से पहले और बाद की गतिविधियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। फुटेज के आधार पर यह भी पता लगाया जा सकता है कि आरोपी घटना के बाद किस दिशा में गया और उसके साथ उस समय कोई अन्य व्यक्ति मौजूद था या नहीं। पुलिस ने पीड़ित छात्र और उसके दोस्तों से भी घटना को लेकर जानकारी जुटाई है। इसके अलावा प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।



‘दो कचौड़ी एक चाय, हमारा भी स्टाइपेंड बढ़ाए’, उज्जैन में आयुर्वेद छात्रों ने खोला मोर्चा

महानगर मेट्रो ब्यूरो

उज्जैन। धन्वंतरि अस्पताल में बीएएमएस के छात्र-छात्राओं का स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर शुरू हुआ प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। करीब 250 छात्र-छात्राएं आंदोलन में शामिल हैं। छात्रों का कहना है कि जब एमबीबीएस इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ाया जा सकता है तो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में प्रशिक्षण ले रहे छात्रों के मानदेय में भी समानता होनी चाहिए। छात्रों ने स्पष्ट किया है कि उन्हें केवल घोषणा नहीं चाहिए, बल्कि स्टाइपेंड बढ़ाने का लिखित आदेश चाहिए। जब तक सरकार की ओर से लिखित आश्वासन नहीं मिलता, तब तक आंदोलन जारी रखने की बात कही गई है। प्रदर्शन के दौरान छात्र-छात्राओं ने अलग-अलग नारों के जरिए अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। आंदोलन के दौरान ‘दो कचौड़ी एक चाय, हमारा भी स्टाइपेंड बढ़ाए’ जैसे नारे लगाए गए। छात्रों का कहना है कि मौजूदा स्टाइपेंड में उन्हें कई तरह की आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका तर्क है कि अस्पताल में ड्यूटी और प्रशिक्षण के दौरान वे नियमित रूप से अपनी सेवाएं देते हैं, ऐसे में उनके मानदेय में भी उचित बढ़ोतरी होनी चाहिए। आंदोलन के दूसरे दिन छात्रों ने यज्ञ का आयोजन किया। इसमें छात्र-छात्राओं ने आहुति देकर शासन-प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की। छात्रों ने कहा कि उनका आंदोलन किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि समान स्टाइपेंड की मांग को लेकर है। उनका कहना है कि सरकार उनकी मांग पर गंभीरता से विचार करे और जल्द लिखित आदेश जारी करे, ताकि आंदोलन को समाप्त किया जा सके। प्रदर्शन के दौरान 2 छात्राएं 24 घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल पर भी बैठी हैं। छात्र-छात्राओं ने कहा कि वे अपनी मांग को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार की ओर से लिखित आदेश नहीं मिलता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने जरूरत पड़ने पर आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी भी दी है।



स्कूल बस में चढ़ते समय बिगड़ी छात्र की तबीयत, मां के सामने ही मौत;

महानगर मेट्रो ब्यूरो

उज्जैन। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सोमवार सुबह एक बेहद दुखद घटना सामने आई। स्कूल जाने के लिए घर से निकले 10वीं कक्षा के छात्र की अचानक तबीयत बिगड़ गई और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि छात्र स्कूल बस में चढ़ने की तैयारी कर रहा था, तभी अचानक वह गिर पड़ा। उस समय उसकी मां भी स्कूल बस के पास मौजूद थीं। मां के सामने बेटे की तबीयत बिगड़ने से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। परिजन तत्काल उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। मामला उज्जैन शहर की श्रीकृष्ण कॉलोनी का है। यहां रहने वाला विधान 10वीं कक्षा में पढ़ता था। सोमवार सुबह वह रोज की तरह तैयार होकर स्कूल जाने के लिए घर से निकला था। परिवार के मुताबिक, उस समय उसकी तबीयत सामान्य थी और किसी तरह की परेशानी नजर नहीं आ रही थी। वह स्कूल बस के पास पहुंचा और जैसे ही बस में चढ़ने लगा, अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद वह वहीं गिर पड़ा। अचानक छात्र के गिरने से आसपास मौजूद लोग उसकी मदद के लिए दौड़े। स्कूल बस के पास मौजूद उसकी मां ने भी बेटे को संभालने की कोशिश की। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के अन्य लोग भी मौके पर पहुंचे। छात्र को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। परिजनों को उम्मीद थी कि इलाज के बाद उसकी हालत में सुधार होगा, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जानकारी में डॉक्टरों की ओर से छात्र की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। हालांकि, कम उम्र में अचानक हुई मौत के वास्तविक कारण की चिकित्सकीय पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। मौत के कारण को लेकर चिकित्सकीय जांच और अन्य औपचारिक प्रक्रियाएं की जा रही हैं। परिवार के लिए यह घटना इसलिए भी बेहद सदमे वाली है क्योंकि छात्र सुबह बिल्कुल सामान्य तरीके से स्कूल जाने के लिए घर से निकला था। विधान की अचानक मौत की खबर परिवार और आसपास के लोगों तक पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। जिस बेटे को परिवार रोज स्कूल भेजता था, उसकी अचानक मौत की खबर से घर में मातम पसर गया। कॉलोनी के लोग भी घटना से स्तब्ध हैं और परिवार को ढांढस बंधाने के लिए पहुंच रहे हैं। विधान के पिता संजय फल कारोबारी हैं। परिवार के लोगों के मुताबिक, विधान पढ़ाई में काफी होनहार था और कक्षा में अच्छे प्रदर्शन के लिए जाना जाता था। पढ़ाई के साथ-साथ उसकी खेलकूद में भी रुचि थी। वह टेबल टेनिस और दौड़ जैसी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेता था और कई प्रतियोगिताओं में पुरस्कार भी जीत चुका था। विधान के दोस्तों ने बताया कि वह पढ़ाई को लेकर गंभीर रहने के साथ ही स्कूल की अन्य गतिविधियों में भी सक्रिय रहता था।



मंच से हंसते बोले सीएम मोहन यादव, ठहाकों से गूंज उठा सभागार

महानगर मेट्रो ब्यूरो

भोपाल। राजधानी भोपाल के रवींद्र भवन में आयोजित बुंदेली समागम में मुख्यमंत्री मोहन यादव का हल्का-फुल्का अंदाज देखने को मिला। कार्यक्रम में बुंदेली संस्कृति, युवाओं और रोजगार जैसे विषयों पर चर्चा के दौरान छतरपुर की चर्चित बुंदेली बाल कलाकार बिन्नू रानी ने मुख्यमंत्री से ऐसा सवाल पूछ लिया, जिस पर पूरा सभागार ठहाकों और तालियों से गूंज उठा।

कार्यक्रम के दौरान बिन्नू रानी ने मुख्यमंत्री से बुंदेली अंदाज में पूछा कि उन्होंने प्रदेश की ‘जिज्जियों’ यानी बहनों के लिए तो काफी कुछ किया है, लेकिन अब ‘बिन्नुओं’ यानी बेटियों के लिए उनका क्या योजना है। सवाल सुनकर मुख्यमंत्री मोहन यादव मुस्कुराए और मजाकिया अंदाज में जवाब देते हुए कहा, ‘तुमको मालूम नहीं, लाड़ली बहना ही बहुत महंगी पड़ गई। वैसे यह अंदर की बात है। मुझे क्या मालूम था कि मुख्यमंत्री बनते ही इतनी भारी मार पड़ती है।’ मुख्यमंत्री के इस जवाब के बाद सभागार में मौजूद लोग हंसने लगे और तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। इसके बाद मोहन यादव ने बिन्नू रानी से मजाकिया अंदाज में कहा कि अभी वह इस योजना का लाभ लेने के लिए छोटी हैं। थोड़ी और बड़ी हो जाएंगी, तब योजना का फायदा मिल जाएगा। मुख्यमंत्री की इस चुटकी पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने जमकर तालियां बजाईं। बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने लाड़ली बहना योजना का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद सरकार की आर्थिक जिम्मेदारियों और योजनाओं पर होने वाले खर्च का वास्तविक अंदाजा हुआ। उन्होंने कहा कि महिलाओं के हित में शुरू की गई इस योजना का दायरा बढ़ा है और इसके लिए सरकार को लगातार आर्थिक संसाधनों की व्यवस्था करनी पड़ती है। मोहन यादव ने बताया कि लाड़ली बहना योजना की शुरुआत 1000 रुपये प्रतिमाह की राशि से हुई थी। बाद में इसे बढ़ाकर 1250 रुपये किया गया और अब पात्र महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक चुनौतियों के बावजूद सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से योजनाओं को आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के खाते में सीधे राशि पहुंचने से उन्हें अपनी जरूरतों के लिए परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलती है। सरकार का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना ही नहीं, बल्कि महिलाओं की भागीदारी और आत्मनिर्भरता को बढ़ाना भी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2026 तक प्रदेश की करीब 1.25 करोड़ महिलाओं को लाड़ली बहना योजना का लाभ मिल रहा है।



mahangarmetro.com
महानगर मेट्रो
अहमदाबाद, (बुधवार)
07 अक्टूबर 2026

महिला पत्रकार से बदसलूकी के आरोपी एसीपी विवेक भगत का पदभार रुका

महानगर मेट्रो ब्यूरो

नई दिल्ली। महिला पत्रकार से कथित बदसलूकी के मामले में घिरे एसीपी विवेक भगत को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त का कार्यभार देने के आदेश में दिल्ली सरकार ने संशोधन किया है। सरकार के नए आदेश के मुताबिक, मामले की जांच पूरी होने तक विवेक भगत अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त का कार्यभार नहीं संभालेंगे। वह फिलहाल एसीपी के पद पर ही रहेंगे।



दिल्ली सरकार के अनुसार, विवेक भगत ने स्वयं पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि महिला पत्रकारों से कथित बदसलूकी के मामले की जांच पूरी होने तक उन्हें अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त का कार्यभार न दिया जाए। उन्होंने कहा कि पहले आरोपों की जांच और सत्यापन होना चाहिए और जांच संतोषजनक तरीके से पूरी होने तक उनके पदभार को रोका जाए। दरअसल, दिल्ली सरकार ने 5 अक्टूबर को दानिप्स संवर्ग के 12 अधिकारियों को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त के पद का कार्यभार देने का आदेश जारी किया था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस संबंध में प्रस्ताव 25 अगस्त को शुरू किया गया था, यानी महिला पत्रकार से कथित बदसलूकी की मौजूदा घटना से पहले। 5 अक्टूबर को मंजूरी मिलने के बाद यह आदेश जारी किया गया था। विवेक भगत को भी इस सूची में शामिल किया गया था। आदेश सामने आने के बाद इसे उनके पदोन्नति से जोड़कर देखा जा रहा था और विपक्ष की ओर से भी सवाल उठाए गए थे। अब दिल्ली सरकार ने संशोधित आदेश जारी करते हुए विवेक भगत को दिए जाने वाले अतिरिक्त कार्यभार पर रोक लगा दी है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त का कार्यभार स्थायी पदोन्नति नहीं होता।

जंतर-मंतर मारपीट मामले में स्वतंत्र भारद्वाज को बड़ी राहत

महानगर मेट्रो ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हुई कथित मारपीट के मामले में स्वतंत्र भारद्वाज को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने मंगलवार को उनकी अंतरिम जमानत को नियमित जमानत में बदल दिया। इसके बाद अब उन्हें इस मामले में दोबारा जेल नहीं जाना होगा और मुकदमे की आगे की कार्रवाई जमानत पर रहते हुए चलेगी। भारद्वाज के वकील उमेश चंद्र शर्मा के मुताबिक, अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत की पुष्टि की। बचाव पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि अंतरिम जमानत के दौरान स्वतंत्र भारद्वाज ने अदालत की ओर से लगाई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया। वहीं, अभियोजन पक्ष की ओर से उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत बताई गई थी। अदालत ने फिलहाल नियमित जमानत मंजूर कर ली है। हालांकि, मामले में लगाए गए आरोपों पर अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है। आगे की सुनवाई के दौरान सामने आने वाले साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर मामले की कानूनी स्थिति तय होगी। यह मामला 23 जून 2026 को जंतर-मंतर पर आयोजित एक प्रदर्शन के दौरान हुई कथित मारपीट से जुड़ा है। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान स्वतंत्र भारद्वाज ने अनुसूचित जाति से जुड़े एक शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की थी। बाद में मामले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी गई थीं। पुलिस के मुताबिक, शुरुआती शिकायत में जातिसूचक टिप्पणी का उल्लेख नहीं था, लेकिन बाद में दर्ज कराए गए बयान में इस तरह का आरोप सामने आया। इसी आधार पर मामले में अतिरिक्त धाराएं जोड़े जाने की बात कही गई थी। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने अलग-अलग पहलुओं को लेकर पूछताछ भी की। स्वतंत्र भारद्वाज को सितंबर में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था और वह तिहाड़ जेल में रहे। इसके बाद 15 सितंबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें 3 सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी। अंतरिम जमानत देते समय अदालत ने उनके सामने कई शर्तें रखी थीं। उन्हें मामले से जुड़े सामाजिक माध्यमों पर संदेश, साक्षात्कार या सार्वजनिक बयान देने से रोका गया था। इसके अलावा शिकायतकर्ता, उसकी बेटी और मामले से जुड़े गवाहों से संपर्क करने या उन्हें प्रभावित करने की कोशिश नहीं करने के निर्देश भी दिए गए थे। अदालत ने अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान उनके आचरण को लेकर रिपोर्ट भी मांगी थी।



INDIA ब्लॉक के प्रदर्शन में बॉडी कैमरा लगाकर उतरी दिल्ली पुलिस

महानगर मेट्रो ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली विपक्षी दलों के प्रस्तावित मार्च को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। प्रदर्शन के दौरान होने वाली गतिविधियों और पुलिस की कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए पुलिसकर्मियों को बॉडी कैमरों से लैस किया गया है। नई दिल्ली जिले में 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। संसद भवन, निर्वाचन सदन और अन्य संवेदनशील स्थानों के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई है। विपक्षी गठबंधन के 140 से ज्यादा सांसद मंगलवार को विशेष गहन पुनरीक्षण और चुनाव आयोग के खिलाफ संसद से सड़क तक मार्च निकालने की तैयारी में हैं। प्रस्तावित मार्च को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के साथ-साथ निगरानी व्यवस्था भी बढ़ाई है। ड्यूटी पर तैनात कई पुलिसकर्मी बॉडी कैमरे लगाए हुए नजर आए। नई दिल्ली जिले के पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा भी बॉडी कैमरे के साथ ड्यूटी पर तैनात हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, बॉडी कैमरे लगाने का मुख्य उद्देश्य प्रदर्शन के दौरान होने वाली घटनाओं की वास्तविक वीडियो रिकॉर्डिंग रखना है। इससे किसी घटना को लेकर बाद में विवाद होने या पुलिस पर कोई आरोप लगाए जाने की स्थिति में वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर घटनाक्रम की जांच की जा सकेगी। पुलिस के पास प्रदर्शन के दौरान मौके की गतिविधियों का प्रत्यक्ष दृश्य रिकॉर्ड भी उपलब्ध रहेगा। इससे पहले सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस पर कई तरह के आरोप लगाए गए थे। इसके बाद प्रदर्शन और विरोध कार्यक्रमों के दौरान पुलिसकर्मियों के शरीर पर लगाए जाने वाले कैमरों के इस्तेमाल पर ज्यादा जोर दिया गया है। पुलिस का मानना है कि रिकॉर्डिंग से प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच होने वाली घटनाओं को समझने में मदद मिलेगी और बाद में किसी भी विवाद की स्थिति में तथ्य सामने रखे जा सकेंगे। नई दिल्ली जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इनमें पुरुष पुलिसकर्मियों की 27 कंपनियां और महिला पुलिसकर्मियों की 4 कंपनियां शामिल हैं। आमतौर पर एक पुलिस कंपनी में करीब 100 से 115 जवान होते हैं। संसद भवन, संसद मार्ग गोलचक्कर, निर्वाचन सदन और आसपास के महत्वपूर्ण स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। विपक्षी मार्च से पहले निर्वाचन सदन के आसपास भी सुरक्षा घेरा मजबूत किया गया है।



'नाम-निशान पर हमारा स्वाभाविक हक' सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट ने रखी दावेदारी अयोग्यता की कार्यवाही

महानगर मेट्रो ब्यूरो

नई दिल्ली। शिवसेना के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान एकनाथ शिंदे गुट ने अपने पक्ष में दलीलें पेश कीं। शिंदे गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एन.के. कौल ने चुनाव आयोग के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि आयोग ने राजनीतिक दल से जुड़े विवाद में सभी जरूरी पहलुओं और संभावित परीक्षणों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया था। कौल ने दलील दी कि चुनाव आयोग को चुनाव से जुड़ी प्रक्रियाओं और राजनीतिक दलों के विवाद में इस्तेमाल किए जाने वाले परीक्षण तय करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि आयोग यह तय नहीं करता कि कोई व्यक्ति किस पद पर रहेगा, बल्कि उसका काम यह निर्धारित करना है कि किसी राजनीतिक दल से जुड़े विवाद में किस आधार या परीक्षण के जरिए फैसला किया जाए। उन्होंने चुनाव चिह्न आदेश का हवाला देते हुए कहा कि इसमें आरक्षित और मुक्त चुनाव चिह्न का प्रावधान है। आरक्षित चुनाव चिह्न मान्यता प्राप्त



राजनीतिक दलों को दिए जाते हैं। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा उसके चुनावी प्रदर्शन, वोट प्रतिशत और अलग-अलग राज्यों में चुनाव लड़ने जैसे आधारों पर मिलता है। कौल ने कहा कि आरक्षित चुनाव चिह्न किसी राजनीतिक दल की महत्वपूर्ण राजनीतिक संपत्ति होता है, क्योंकि मतदाता अक्सर पार्टी की पहचान उसके चुनाव चिह्न से करते हैं। इसलिए किसी दल में विभाजन होने की स्थिति में चुनाव आयोग के सामने यह तय करने की जिम्मेदारी आती है कि राजनीतिक दल की वास्तविक पहचान और उसके संगठनात्मक स्वरूप को किस आधार पर निर्धारित किया जाए। शिंदे गुट की ओर से दलील दी गई कि पार्टी में विभाजन की स्थिति में चुनाव आयोग के सामने मुख्य रूप से 2 रास्ते हो सकते हैं। पहला, किसी एक गुट को वास्तविक राजनीतिक दल मानकर उसे आरक्षित चुनाव चिह्न दिया जाए। दूसरा, यह माना जाए कि राजनीतिक दल में ऐसा कोई विभाजन नहीं हुआ है। जब तक विवाद का अंतिम समाधान नहीं होता, तब तक दोनों पक्षों को अंतरिम चुनाव चिह्न देने की व्यवस्था भी की जा सकती है। कौल ने कहा कि बाद में जिस गुट को वास्तविक राजनीतिक दल माना जाएगा, आरक्षित चुनाव चिह्न उसी गुट को दिया जा सकता है। उनके मुताबिक, केवल इस आधार पर चुनाव आयोग की प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता कि पार्टी से जुड़े विधायकों की अयोग्यता पर फैसला अभी बाकी है। उन्होंने सुभाष देसाई और सादिक अली मामलों का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव आयोग को यह तय करने का अधिकार है कि किसी राजनीतिक दल के विवाद में कौन सा परीक्षण लागू किया जाए। राजनीतिक दल अपनी ओर से अलग-अलग परीक्षण सुझा सकते हैं, लेकिन विधायी बहुमत भी किसी विवाद के समाधान के लिए एक वैध आधार हो सकता है। कौल ने यह भी तर्क दिया कि यदि चुनाव आयोग की कार्यवाही को विधायकों की अयोग्यता की प्रक्रिया पूरी होने तक रोक दिया जाए तो पूरा विवाद अनिश्चित समय तक लंबित रह सकता है। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के फैसले में समय लग सकता है और उस फैसले के खिलाफ आगे कानूनी चुनौती भी दी जा सकती है। शिंदे गुट की ओर से कहा गया कि ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग का फैसला लंबे समय तक टलने से राजनीतिक दल के सामने व्यावहारिक मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अगर किसी दल को लंबे समय तक अंतरिम चुनाव चिह्न के साथ चुनाव लड़ना पड़े तो मतदाताओं के बीच पुराने चुनाव चिह्न के साथ उस दल की पहचान और जुड़ाव कमजोर हो सकता है।

दिल्ली के सखी वन स्टॉप सेंटरों की मासिक रिपोर्ट अब सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी जाएगी

महानगर मेट्रो ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को लोक नायक अस्पताल स्थित सखी वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण कर वहां महिलाओं और बच्चियों को दी जा रही सुविधाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के सभी सखी वन स्टॉप सेंटरों की विस्तृत मासिक रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय भेजने के निर्देश दिए। रिपोर्ट में सेंटर पर पहुंचने वाले मामलों की संख्या के साथ पुलिस को दी गई सूचना, प्राथमिकी की स्थिति, आरोपी के खिलाफ की गई कार्रवाई और पीड़िता को उपलब्ध कराई गई सहायता का पूरा विवरण दर्ज करना होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि हिंसा या किसी अन्य परेशानी की शिकार महिला को केवल तत्काल सहायता देना पर्याप्त नहीं है। उसे सम्मान, सुरक्षा और प्रभावी कानूनी व न्यायिक सहयोग भी मिलना चाहिए। उन्होंने सेंटर पर आने वाली महिलाओं और बच्चियों की शिकायतों को संवेदनशीलता के साथ सुनने और उनकी जरूरत के अनुसार तत्काल सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया। रेखा गुप्ता ने निर्देश दिया कि जरूरत के अनुसार पीड़िताओं को चिकित्सा सुविधा,



पुलिस सहायता, कानूनी परामर्श, मनोवैज्ञानिक परामर्श और अस्थायी आश्रय उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि सखी वन स्टॉप सेंटर का उद्देश्य पीड़ित महिला को अलग-अलग सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से बचाते हुए एक ही स्थान पर आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने पॉक्सो से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे मामलों से जुड़े रिकॉर्ड को पूरी गोपनीयता के साथ अलग से व्यवस्थित रखा जाए। मामलों की जानकारी और कार्रवाई का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पीड़ित बच्चियों की पहचान और उनसे जुड़ी संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक न हो। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने सेंटर की साफ-सफाई, भोजन और रहने की व्यवस्था का भी जायजा लिया। उन्होंने वहां उपलब्ध सुविधाओं के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली और पीड़ित महिलाओं तथा बच्चियों को रहने के दौरान किसी तरह की परेशानी नहीं होने देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सखी वन स्टॉप सेंटर में हिंसा से प्रभावित महिलाओं और बच्चियों को एक ही स्थान पर चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक परामर्श और कानूनी सहायता जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसलिए सेंटरों की व्यवस्थाओं में किसी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए और उनकी नियमित निगरानी की जानी चाहिए। रेखा गुप्ता ने अधिकारियों से कहा कि सेंटरों में आने वाली महिलाओं और बच्चियों को किसी भी स्तर पर असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने उपलब्ध सुविधाओं की नियमित समीक्षा करने और जरूरत के अनुसार उनमें सुधार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मासिक रिपोर्ट के जरिए प्रत्येक सेंटर में आने वाले मामलों, उन पर हुई कार्रवाई और पीड़िताओं को मिली सहायता की स्थिति की लगातार निगरानी की जाएगी। इससे मामलों के निस्तारण की स्थिति पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाने में मदद मिलेगी।

महाराष्ट्र में 3 आईएएस अधिकारियों के तबादले, संजय खंडारे वन विभाग भेजे गए; संजय यादव और वैष्णवी बी की भी नई जिम्मेदारी

महानगर मेट्रो ब्यूरो

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 3 अधिकारियों का तबादला किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजय जगन्नाथ खंडारे को वन विभाग का अपर मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वह इससे पहले पर्यटन विभाग में अपर मुख्य सचिव के पद पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे। 1996 बैच के महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी संजय खंडारे को मंत्रालय में वन विभाग में नई जिम्मेदारी दी गई है। पर्यटन विभाग में उनके स्थान पर 2009 बैच के आईएएस अधिकारी संजय यादव को सचिव नियुक्त किया गया है। संजय यादव इससे पहले समग्र शिक्षा अभियान, मुंबई के राज्य परियोजना निदेशक के पद पर कार्यरत थे। तबादला आदेश के तहत 2019 बैच की आईएएस अधिकारी वैष्णवी बी. को भी नई जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें नागपुर मंडल का अपर आयुक्त नियुक्त किया गया है। वह इससे पहले नागपुर नगर निगम में



अपर नगर आयुक्त के पद पर कार्यरत थीं। संजय जगन्नाथ खंडारे 1996 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। प्रशासनिक सेवा के दौरान उन्होंने राज्य सरकार के कई महत्वपूर्ण विभागों में जिम्मेदारियां संभाली हैं। उनके कार्य अनुभव में सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग में प्रमुख सचिव, शहरी विकास से जुड़े पद और मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण में अपर आयुक्त जैसी जिम्मेदारियां शामिल रही हैं। खंडारे ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भी सेवाएं दी हैं। उनके लंबे प्रशासनिक अनुभव में मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण से जुड़ी जिम्मेदारी प्रमुख रही है, जहां उन्होंने कई वर्षों तक काम किया। अब उन्हें वन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। 2009 बैच के आईएएस अधिकारी संजय यादव को मंत्रालय में पर्यटन विभाग का सचिव बनाया गया है। वह इससे पहले मुंबई में समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक के रूप में काम कर रहे थे। अब उन्हें पर्यटन विभाग की प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2019 बैच की आईएएस अधिकारी वैष्णवी बी. को नागपुर मंडल का अपर आयुक्त नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह नागपुर नगर निगम में अपर नगर आयुक्त के पद पर कार्यरत थीं। उन्होंने अप्रैल 2025 में यह जिम्मेदारी संभाली थी। इससे पहले वह जिला परिषद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर भी काम कर चुकी हैं। महाराष्ट्र सरकार के इस प्रशासनिक फेरबदल के बाद तीनों अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां संभालनी होंगी। तबादलों के तहत संजय खंडारे वन विभाग, संजय यादव पर्यटन विभाग और वैष्णवी बी. नागपुर मंडल में अपनी नई जिम्मेदारी निभाएंगी।

न थाली में खाना, न सोने को बिस्तर! छात्रावासों की बदहाली के खिलाफ मुंबई पहुंचे आदिवासी छात्र

महानगर मेट्रो ब्यूरो

मुंबई। महाराष्ट्र के आदिवासी छात्रावासों में बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर छात्रों का आक्रोश अब राजधानी मुंबई तक पहुंच गया है। राज्य के अलग-अलग जिलों से 300 से ज्यादा आदिवासी छात्र सोमवार को मुंबई पहुंचे और तिलक भवन में डेरा जमा लिया। छात्रों ने छात्रावासों में खाने, पीने के पानी, रहने और सोने की व्यवस्था में कथित खामियों को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। छात्रों ने राज्यपाल से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखने की मांग की, लेकिन अनुमति नहीं मिलने के बाद पुलिस ने तिलक भवन के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी। छात्रों का कहना है कि वे अपनी समस्याओं को लेकर पहले आजाद मैदान में प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन वहां प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली। इसके बाद अलग-अलग जिलों से आए छात्र तिलक भवन में ही रुक गए। छात्रों के मुताबिक, वे एक दिन से वहीं ठहरे हुए थे और अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों से बातचीत की उम्मीद कर रहे थे। सोमवार को जब छात्र तिलक भवन से बाहर निकलने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच तनाव की स्थिति बन गई। आरोप है कि पुलिस ने कई छात्रों को जबरन बसों में बैठाया और हिरासत में ले लिया। छात्रों को बसों में ले जाने के



दौरान मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पुलिस की कार्रवाई को लेकर छात्रों और उनके समर्थकों ने नाराजगी जताई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मुंबई युवा कांग्रेस अध्यक्ष जीनत शबरीन भी छात्रों के समर्थन में तिलक भवन पहुंचीं। उन्होंने छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि युवा अब चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने सरकार पर छात्रों की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। छात्रों के रहने की व्यवस्था तिलक भवन में कांग्रेस की ओर से किए जाने की बात भी सामने आई है। छात्रों ने छात्रावासों की जो स्थिति बताई है, उसने व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि कई आदिवासी छात्रावासों में पीने के लिए साफ पानी तक उपलब्ध नहीं है। खाने की गुणवत्ता को लेकर भी लगातार शिकायतें मिल रही हैं। कई छात्रावासों में पर्याप्त बिस्तर नहीं होने की वजह से छात्रों को जमीन पर सोना पड़ता है। कुछ जगहों पर एक ही बिस्तर पर 2-2 छात्रों के सोने की मजबूरी होने का दावा किया गया है। छात्रों के मुताबिक, संभाजीनगर के एक छात्रावास में करीब 200 छात्राओं के लिए सिर्फ एक स्नानघर उपलब्ध है। ऐसे में छात्राओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। छात्रों ने कहा कि छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त कमरे, बिस्तर, शौचालय, स्नानघर और स्वच्छ पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन कई जगह इन सुविधाओं की स्थिति बेहद खराब है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की प्रमुख मांगों में केंद्रीय रसोई व्यवस्था को बंद करना भी शामिल है। छात्रों का आरोप है कि केंद्रीय रसोई से मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता खराब है और पिछले 2 वर्षों में इस व्यवस्था को लेकर लगातार शिकायतें सामने आती रही हैं। छात्रों ने दावा किया कि खराब भोजन और छात्रावासों की अव्यवस्था के कारण कई छात्रों की मौत हुई है। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि और मौतों के वास्तविक कारणों की आधिकारिक जांच के निष्कर्ष अलग से सामने आना बाकी है।

पूरे महाराष्ट्र में 16 अक्टूबर से 10 प्रतिशत पानी की कटौती, अल नीनो के बीच सरकार ने बनाई

महानगर मेट्रो ब्यूरो

मुंबई। महाराष्ट्र में कम बारिश और संभावित सूखे जैसी स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने 16 अक्टूबर 2026 से सभी शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों में कम से कम 10 प्रतिशत पानी की कटौती लागू करने का फैसला किया है। महानगर पालिका, नगर पालिका और ग्राम पंचायतों को पानी की आपूर्ति में यह कटौती लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि अल नीनो के प्रभाव और कम बारिश को देखते हुए राज्य में उपलब्ध जल भंडार का बेहद सावधानी से इस्तेमाल करना जरूरी है। सरकार ने पानी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए 31 अगस्त 2027 तक के लिए बांधवार और उपयोग के हिसाब से जल प्रबंधन योजना तैयार की है। इसमें सबसे पहली प्राथमिकता पीने के पानी को दी गई है। सरकार का कहना है कि आने वाले महीनों में पानी की कमी बढ़ने की स्थिति को देखते हुए अभी से जल संरक्षण के उपाय लागू करना जरूरी है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 265 तालुकों में सूखा घोषित किया है। इन क्षेत्रों में सूखे के शुरुआती संकेत तय करने वाले 'ट्रिगर-1' मानदंड लागू हुए हैं। कम बारिश और लंबे समय तक सूखे की स्थिति के कारण कई क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ी है। गिरीश महाजन के मुताबिक, अगले साल भी अल नीनो का प्रभाव रहने की संभावना को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभागों और स्थानीय निकायों को पानी का सोच-समझकर इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने साफ किया है कि पानी के भंडार का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा सरकार की योजना के तहत बांधों और जलाशयों में उपलब्ध पानी के इस्तेमाल की योजना बनाते समय पीने के पानी को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। वाष्पीकरण, गाद जमा होने और बिना अनुमति पानी निकाले जाने जैसी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए 31 अगस्त 2027 तक पीने के पानी का भंडार सुरक्षित रखने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा प्रत्येक बांध में उपलब्ध पानी का 10 प्रतिशत अतिरिक्त आपातकालीन भंडार रखने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार के मुताबिक, भविष्य में अगर पानी की स्थिति और खराब होती है तो इस अतिरिक्त भंडार का इस्तेमाल किया जा सकेगा। बेहद जरूरी स्थिति में तकनीकी जांच के बाद बांधों के मृत भंडार से पानी लेने की संभावना भी रखी गई है। सभी महानगर पालिकाओं, नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों को 16 अक्टूबर से कम से कम 10 प्रतिशत पानी की कटौती लागू करने के साथ पानी के रिसाव को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा गया है।



बीड में चरवाहों पर संकट, चारे से लेकर पानी की किल्लत! सरकार से लगाई गुहार

महानगर मेट्रो ब्यूरो

बीड। महाराष्ट्र के बीड जिले में पानी और चारे की कमी अब पारंपरिक रूप से पशुपालन पर निर्भर चरवाहा समुदाय के लिए बड़ी परेशानी बनती जा रही है। जिले के कई इलाकों में कम बारिश और बढ़ती गर्मी के कारण चरागाह और खेत सूख गए हैं। ऐसे में भेड़-बकरियों और दूसरे पशुओं के लिए हरा और सूखा चारा जुटाना मुश्किल हो गया है। पानी की उपलब्धता भी लगातार कम होने से पशुओं के साथ-साथ चरवाहों और उनके परिवारों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चरवाहों का कहना है कि पहले जिन इलाकों में पशुओं के चरने के लिए पर्याप्त घास मिल जाती थी, वहां अब स्थिति बदल गई है। खेतों और खुले चरागाहों में घास नहीं बची है। इसके कारण भेड़-बकरियों के झुंड लेकर उन्हें चारे की तलाश में दूर-दूर तक जाना पड़ रहा है। लगातार बढ़ती गर्मी के बीच लंबी दूरी तय करने से पशुओं की सेहत पर भी असर पड़ रहा है। चारे और पानी की कमी के कारण कई पशु कमजोर और बीमार पड़ने की शिकायतें सामने आ रही हैं। चरवाहों के मुताबिक समस्या सिर्फ पशुओं तक सीमित नहीं है। जिन परिवारों की आजीविका पूरी तरह भेड़-बकरियों और दूसरे पशुओं पर निर्भर है, उनके सामने अब आर्थिक संकट भी गहराता जा रहा है। पशुओं को पर्याप्त चारा नहीं मिलने से उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, वहीं पानी की व्यवस्था के लिए भी अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है। पशुधन कमजोर होने की स्थिति में परिवारों की आमदनी पर सीधा असर पड़ने की चिंता भी बनी हुई है। पानी का संकट बढ़ने से कई चरवाहा परिवारों के सामने अपने और पशुओं दोनों के लिए पानी जुटाने की चुनौती खड़ी हो गई है। गर्मी के कारण पशुओं को सामान्य दिनों की तुलना में अधिक पानी की जरूरत होती है, लेकिन स्थानीय स्तर पर पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होने से परेशानी बढ़ रही है। चरवाहों का कहना है कि यदि समय रहते चारे और पानी की व्यवस्था नहीं की गई तो आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। इसी समस्या को देखते हुए स्थानीय चरवाहों ने प्रशासन से तत्काल चारा छावनियां शुरू करने की मांग की है। उनका कहना है कि चारा छावनियां शुरू होने से भेड़-बकरियों के लिए भोजन की व्यवस्था हो सकेगी और पशुपालकों को अपने पशुधन को बचाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही जिन इलाकों में पीने के पानी की उपलब्धता कम है, वहां टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाने की मांग भी की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रकांत हजारे ने भी चरवाहों की इस समस्या को सामने रखते हुए सरकार से तत्काल ध्यान देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी वर्गों के लिए होती है और इस समय भेड़-बकरियां पालकर जीवनयापन करने वाले परिवारों को मदद की जरूरत है।



जेट ईंधन की बढ़ती कीमतों से उड़ानें महंगी, सरकार ने संभाला मोर्चा

पश्चिम एशिया संकट के चलते एटीएफ की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर

नई दिल्ली ।

पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण विमान ईंधन (एटीएफ) की रिकॉर्ड उच्च कीमतों ने नागर विमानन मंत्रालय की चिंता बढ़ा दी है। मंत्री के. राममोहन नायडू ने मंगलवार को घोषणा की कि मंत्रालय इस मुद्दे पर विमानन कंपनियों और तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के साथ गहन बातचीत कर रहा है, ताकि बढ़ते परिचालन लागत के बोझ को कम किया जा सके। नायडू ने बताया कि एटीएफ किसी भी एयरलाइन की कुल परिचालन लागत का लगभग 40 प्रतिशत होता है। इसकी लगातार बढ़ती कीमतों के कारण एयरलाइंस को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के मद्देनजर, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने हाल ही में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए ईंधन अधिभार बढ़ाने की घोषणा की थी। इंडिगो ने बताया कि पश्चिम एशिया की भू-राजनीतिक स्थिति के बाद से एटीएफ की कीमतों में मासिक आधार पर 14 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है, जो इसे पिछले एक दशक के उच्चतम स्तर पर ले गई है। मंत्रालय का लक्ष्य इन चुनौतियों का समाधान निकालना है।

टाटा स्टील को घरेलू इस्पात मांग में 8-10 फीसदी वृद्धि का अनुमान

नई दिल्ली ।

टाटा स्टील के एक प्रमुख अ धिकारी ने मंगलवार को अनुमान जताया कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में भारत की घरेलू इस्पात मांग में 8-10 प्रतिशत की ठोस वृद्धि देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय राजधानी में इंडियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट (आईएफक्यूएम) की संगोष्ठी से इतर उन्होंने इस्पात खपत वाले सभी क्षेत्रों की मजबूती को इस सकारात्मक दृष्टिकोण का कारण बताया। उन्होंने इस वृद्धि का मुख्य कारण इस्पात की खपत करने वाले सभी क्षेत्रों की मजबूत स्थिति को बताया, जिससे भारतीय इस्पात उद्योग के लिए एक बेहद सकारात्मक माहौल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि मांग 8-10 प्रतिशत होनी चाहिए, क्योंकि इस्पात की खपत करने वाले सभी क्षेत्र काफी मजबूत हैं। इसलिए हम इस्पात उद्योग की संभावनाओं को लेकर काफी सकारात्मक हैं। प्रस्तावित नीदरलैंड परियोजना पर उन्होंने बताया कि कंपनी बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर से पहले स्थानीय सरकार के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है। इसमें कोक ओवन बंद करने और इस्पात स्लैग के वर्गीकरण व प्रबंधन जैसे प्रमुख मुद्दों को हल किया जाना है। टाटा स्टील नीदरलैंड के आईजेमुइडेन स्थित अपने 70 लाख टन वार्षिक क्षमता वाले संयंत्र में कम कार्बन उत्सर्जन वाली प्रक्रियाओं को अपनाकर उत्पादन क्षमता बढ़ाने, लागत घटाने और मार्जिन सुधारने पर केंद्रित है।

भारतीय सेवा क्षेत्र में आया बूम, सितंबर में वृद्धि 3 महीने के उच्चतम स्तर पर

मजबूत घरेलू और बढ़ती अंतरराष्ट्रीय मांग से मिला समर्थन

नई दिल्ली ।

भारत के सेवा क्षेत्र ने सितंबर में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है, जो तीन महीने के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। मंगलवार को जारी मासिक सर्वेक्षण (एचएसबीसी इंडिया सेवा पीएमआई) के आंकड़ों के अनुसार, मजबूत घरेलू मांग और नए ऑर्डर में तेजी ने इस क्षेत्र की वृद्धि को महत्वपूर्ण समर्थन दिया है।

मौसमी रूप से समायोजित एचएसबीसी इंडिया सेवा पीएमआई कारोबारी गतिविधि सूचकांक अगस्त के 54.1 से बढ़कर सितंबर में 55.2 हो गया, जो जून के बाद गतिविधियों में सबसे तेज बढ़ोतरी का संकेत देता है। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही का औसत पिछली अवधि के स्तर से ऊपर नहीं जा सका और मार्च 2022 तक के तीन महीनों के बाद सबसे कमजोर रहा।

सेवा क्षेत्र की यह तेजी डिजिटल समाधान, खाद्य, बीमा, ऋण, सॉफ्टवेयर, परिवहन और पर्यटन एवं यात्रा सहित कई क्षेत्रों में बढ़ती मांग से प्रेरित है। इसके अतिरिक्त, भारतीय सेवाओं की अंतरराष्ट्रीय मांग में भी सुधार देखा गया, जिसमें जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों से नए ऑर्डर मिले। एचएसबीसी की एक अर्थशास्त्री ने पुष्टि की कि घरेलू और निर्यात मांग दोनों ने सेवा क्षेत्र के सुधार को गति दी है। रोजगार के मोर्चे पर, बेहतर ऑर्डर और आगामी परियोजनाओं के कारण सेवा प्रदाताओं ने सितंबर में अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती की, हालांकि वृद्धि की दर अगस्त की तुलना में धीमी रही। इस बीच, कच्चे माल की लागत का दबाव भी कम हुआ है, जिससे बिक्री कीमतें बढ़ाने की आवश्यकता में कमी आई है।

शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुआ

सेंसेक्स 685, निफ्टी 220 अंक उछला

मुंबई ।

भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को भी तेजी के साथ बंद हुआ। वहीं गत दिवस भी बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ था। इस प्रकार सप्ताह के दूसरे करोबारी दिन भी बाजार में ये उछाल दुनिया भर से मिले अच्छे संकेतों के साथ ही खरीददारी हावी रहने से आया है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआईद्ध) की मौद्रिक नीति समीक्षा के परिणामों के पहले निवेशकों ने जमकर खरीदारी की जिससे भी बाजार ऊपर आया है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट और मजबूत संकेतों से भी घरेलू बाजार को बल मिला है।

इससे दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों पर आधारित मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य सूचकांक सेंसक्स 685.34 अंक की बढ़त के साथ ही 73,067.81 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 220.35 अंक बढ़कर 22,776.10 के स्तर पर बंद हुआ।

आज फार्मा और केमिकल के साथ ही प्राइवेट बैंकिंग और ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयरों में तेजी रही।

दूसरी ओर आईटी शेयरों में मुनाफावसूली रही। जिससे निफ्टी आईटी इंडेक्स आज सबसे ज्यादा टूटने वाला सेक्टर बना। निफ्टी के शेयरों में ट्रेंट, बीएसई और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाले शेयरों में



शामिल रहे।

वहीं छोटे और मझोले शेयरों में भी तेजी रही। मुख्य सूचकांकों के साथ-साथ छोटे और मध्यम कंपनियों के शेयरों में भी भारी उछाला देखा गया। मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स ने मुख्य सूचकांकों में भी तेजी रही।

इससे पहले आज सुबह सेंसेक्स और निफ्टी मंगलवार को शुरुआती कारोबार में बढ़त के साथ खुले। बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 120.22 अंक चढ़कर 72,535.41 अंक पर जबकि एनएसई निफ्टी 47.15 अंक की बढ़त के साथ 22,603.10 अंक पर रहा। वहीं आज एशियाई बाजारों में जापान का निक्की 225 और हांगकांग का हैंगसेंग बढ़त में कारोबार कर रहे थे। इसके अलावा रसायन, ऊर्जा, वित्तीय सेवाओं और सीमेंट क्षेत्र के शेयर भी बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे।

रुपया सपाट बंद हुआ

मुंबई ।



अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया मंगलवार को एक पैसे की गिरावट के साथ ही 96.36 पर तकरीबन सपाट बंद हुआ। शुरुआती कारोबार में रुपया चार पैसे टूटकर 96.39 प्रति डॉलर पर आ गया। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की निरंतर निकासी से घरेलू मुद्रा पर दबाव है। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि हालांकि घरेलू शेयर बाजार में सकारात्मक रुख और डॉलर सूचकांक में कमजोरी ने रुपये को निचले स्तर पर समर्थन दिया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 96.29 प्रति डॉलर पर खुला। बाद में टूटकर 96.39 प्रति डॉलर पर आ गया जो पिछले बंद भाव से चार पैसे की गिरावट है। रुपया सोमवार को 10 पैसे टूटकर 96.35 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इस बीच दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दिखाने वाला डॉलर सूचकांक 0.04 फीसदी की गिरावट के साथ 102.12 पर रहा।

एलन मस्क फिर ट्रिलियनेयर क्लब में, 1 ट्रिलियन डॉलर पार हुई नेटवर्थ

टेस्ला और स्पेसएक्स के शेयरों में उछाल से संपत्ति में भारी वृद्धि

वाशिंगटन ।

तकनीकी दिग्गज एलन मस्क ने एक बार फिर अपनी संपत्ति से दुनिया को चौंका दिया है। उनकी नेटवर्थ का आंकड़ा फिर से 1 ट्रिलियन डॉलर (लगभग 92 लाख करोड़ रुपये) को पार कर गया है। यह उपलब्धि उनकी कंपनियों, विशेषकर टेस्ला और स्पेसएक्स के शेयरों में जबरदस्त उछाल का परिणाम है। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार सोमवार को मस्क की कुल संपत्ति 65 अरब डॉलर बढ़कर 1.04 ट्रिलियन डॉलर हो गई। भारतीय मुद्रा में यह आंकड़ा लगभग 92 लाख करोड़ रुपये और एक दिन का इजाफा करीब 5.7 लाख करोड़ रुपये बैठता है। उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा टेस्ला और स्पेसएक्स में उनकी हिस्सेदारी (98 फीसदी से अधिक) से आता है। इन्हीं कंपनियों के शेयरों में हालिया तेजी ने उन्हें फिर इस मुकाम पर पहुंचाया है। गौरतलब है कि मस्क ने जून में पहली बार यह आंकड़ा छुआ था, लेकिन बाद में शेयरों में गिरावट से उनकी नेटवर्थ कम हो गई थी। अब तीन महीने बाद उन्होंने जोरदार वापसी की है। अक्टूबर की शुरुआत से स्पेसएक्स के शेयरों में लगभग 13 फीसदी और टेस्ला के शेयरों में करीब 6.7 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। स्पेसएक्स की यह तेजी अगस्त के निचले स्तरों से 58 फीसदी की रिकवरी दर्शाती है, जिसे मॉर्गन स्टेनली के विश्लेषकों का भी समर्थन मिला है। वहीं टेस्ला की तीसरी तिमाही की उम्मीद से बेहतर बिक्री रिपोर्ट ने भी निवेशकों का भरोसा बढ़ाया, जिससे शेयरों में उछाल आया।

भारत-ईएफटीए टेपा का एक साल पूरा, व्यापार बाधाएं हटाने को बनेगा विशेष समूह

नई दिल्ली।



भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के बीच व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौते (टीईपीए) को लागू हुए एक साल पूरा हो चुका है। इस महत्वपूर्ण मौके पर, दोनों पक्षों ने व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेष समूह गठित करने पर सहमति जाहिर की है। यह समूह दोनों देशों के बीच कारोबार बढ़ाने में आ रही बाधाओं की पहचान कर उन्हें दूर करने के उपायों पर चर्चा करेगा।

विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम), सिबी जॉर्ज ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाइ परमेलिन के बीच हुई हालिया बातचीत में टीईपीए के तहत चल रहे सहयोग और इसके क्रियान्वयन में हुई प्रगति पर विस्तृत चर्चा हुई। सचिव जॉर्ज ने कहा कि इस समझौते के तहत दोनों पक्षों की ओर से किए गए वादों के क्रियान्वयन में संतोषजनक प्रगति हुई है।

सिबी जॉर्ज ने बताया, दोनों पक्षों ने विशेष समूह गठित करने पर सहमति जाहिर की है, जो व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने तथा दोनों देशों के बीच मौजूद किसी भी अड़चन को दूर करने से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा करेगा। भारत-ईएफटीए टीईपीए व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता मार्च 2024 में हस्ताक्षरित हुआ था। ईएफटीए में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन शामिल हैं।

विदेश मंत्रालय के सचिव ने बताया कि स्विस राष्ट्रपति परमेलिन 7 अक्टूबर को आयोजित होने वाले प्रॉस्पेरिटी समिट में भी हिस्सा लेंगे। यह सम्मेलन भारत-ईएफटीए के लागू होने की पहली वर्षगांठ के मौके पर आयोजित किया जा रहा है। जॉर्ज ने कहा, प्रॉस्पेरिटी समिट भारत और ईएफटीए देशों के नीति-निर्माताओं तथा कारोबार जगत को एक मंच पर लाने का महत्वपूर्ण अवसर होगा। उन्होंने परमेलिन की स्विट्जरलैंड के फेडरल काउंसलर फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स, एजुकेशन एंड रिसर्च के रूप में टीईपीए वार्ताओं में व्यक्तिगत भूमिका को भी रेखांकित किया। टीईपीए के अलावा, भारत और स्विट्जरलैंड के बीच आर्थिक संबंधों से परे विज्ञान, अंतरिक्ष, शिक्षा और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है। स्विट्जरलैंड यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के कार्यक्रमों का हिस्सा है और द्विपक्षीय स्तर पर भी अंतरिक्ष सहयोग को आगे बढ़ाया गया है, जिसका प्रमाण 2024 में स्विस शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार राज्य सचिव का इसरो दौरा है। परमेलिन की मौजूदा भारत यात्रा इसी व्यापक साझेदारी को और मजबूत करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

कर्नाटक में बीयर की बढ़ती खपत से डीके सरकार की ताबड़तोड़ कमाई

आबकारी राजस्व में बंपर उछाल

बेंगलुरु ।

शराब मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के बावजूद, राज्य सरकारों के लिए राजस्व का एक बड़ा स्रोत बनी हुई है। इसी कड़ी में, कर्नाटक की डीके शिवकुमार सरकार ने हाल ही में आबकारी विभाग से जबरदस्त कमाई दर्ज की है। जुलाई से सितंबर 2026 के दूसरे क्वार्टर के दौरान, राज्य को 11,595.88 करोड़ का राजस्व मिला, जो पिछले साल इसी अवधि के 10,303.94 करोड़ रुपये से 12.54 प्रतिशत अधिक है। इस महत्वपूर्ण वृद्धि का मुख्य कारण बीयर और इंडियन मेड लिकर (आईएमएल) की बिक्री में उल्लेखनीय बढ़ोतरी रही है।

कर्नाटक सरकार के आंकड़ों के अनुसार, इस अवधि में बीयर की बिक्री में अप्रत्याशित उछाल दिखाई दिया। जुलाई-सितंबर 2026 के दौरान 126.68 लाख केस बॉक्स बीयर बेची गई, जबकि बीते साल यह आंकड़ा 84.63 लाख केस बॉक्स था। यह सालाना आधार पर करीब 49.69 प्रतिशत की भारी वृद्धि को दिखाता है। बीयर की बढ़ती लोकप्रियता का सीधा असर सरकार की आय पर पड़ा, जिससे आबकारी राजस्व 1,234.50 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,463.07 करोड़ रुपये हो गया, जो 18.52 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। इंडियन मेड लिकर (आईएमएल) की बिक्री में भी वृद्धि हुई, हालांकि यह बीयर जितनी तेज नहीं रही। इस दौरान 171.69 लाख केस बॉक्स आईएमएल बिकी, जो पिछले साल के 169.12 लाख केस बॉक्स से 1.52 प्रतिशत से अधिक है। आईएमएल से सरकार को 9,033.21 करोड़ रुपये का राजस्व मिला, जो पिछले वर्ष के 7,968.69 करोड़ रुपये से 13.36 प्रतिशत अधिक है। लाइसेंस फीस और जुर्माने जैसे अन्य स्रोतों से प्राप्त राजस्व लगभग स्थिर रहा, जो 1,099.60 करोड़ रुपये दर्ज किया गया।

अदाणी पावर और भूटान ने 770 मेगावाट जलविद्युत परियोजना पर किए हस्ताक्षर

- निर्माण कार्य 2027 की पहली छमाही में शुरू होने की उम्मीद

मुंबई ।

अदाणी पावर और भूटान की सरकारी बिजली कंपनी ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन (डीजीपीसी) ने भूटान में 770 मेगावाट की चामखारछू-1 जलविद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए एक शेयरधारक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय भूटान के झेमगांग जिले में चामखारछू नदी पर स्थित यह परियोजना, भूटान की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता बढ़ाने और क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग मजबूत करने का लक्ष्य रखती है। यह दोनों साझेदारों के बीच दूसरी बड़ी जलविद्युत परियोजना है। भूटान के प्रधानमंत्री ल्योंछेन दाशो शेरिंग तोबगे की उपस्थिति में हुए इस समझौते के तहत, परियोजना बीओटी (बनाओ-चलाओ और सौंप दो) मॉडल पर अदाणी पावर (49 फीसदी) और डीजीपीसी (51फीसदी) की साझेदारी से विकसित होगी। इसकी रियायत अवधि वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने से 30 साल होगी। निर्माण कार्य 2027 की पहली छमाही में शुरू होने की उम्मीद है, और इसे छह साल के भीतर चालू करने का लक्ष्य है। अदाणी पावर के एक अ धिकारी ने कहा कि यह परियोजना ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करेगी, कार्बन उत्सर्जन घटाएगी और गर्मियों में अतिरिक्त हरित बिजली भारत को निर्यात करने में सहायक होगी।

घरेलू इस्पात मांग में बड़ी उछाल की उम्मीद- टाटा स्टील

नई दिल्ली ।

टाटा स्टील के एक व रिष्ठ अ धिकारी ने घरेलू इस्पात उद्योग के लिए एक सकारात्मक तस्वीर पेश की है।

उन्होंने मंगलवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में देश में इस्पात की मांग में 8-10 प्रतिशत की वृद्धि देखी जा सकती है। इसके साथ ही, उन्होंने नीदरलैंड स्थित संयंत्र के प्रस्तावित परिवर्तन कार्यक्रम को लेकर डच सरकार से जारी बातचीत की भी जानकारी दी।

उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में इंडियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट (आईएफक्यूएम) की संगोष्ठी 2026 से इतर भारतीय इस्पात उद्योग की संभावनाओं पर बात करते हुए यह अनुमान लगाया।

उन्होंने बताया कि इस्पात की खपत करने वाले सभी क्षेत्र काफी मजबूत स्थिति में हैं, जिससे इस्पात उद्योग की संभावनाओं को लेकर कंपनी काफी सकारात्मक है।

प्रस्तावित नीदरलैंड परियोजना के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि कंपनी वहां की सरकार के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है ताकि बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले कुछ अहम मुद्दों को सुलझाया जा सके।

इन मुद्दों में कोक ओवन को बंद करना और इस्पात स्लैग का वर्गीकरण एवं प्रबंधन शामिल हैं। टाटा स्टील का नीदरलैंड के आईजेमुइडेन में लगभग 70 लाख टन वार्षिक क्षमता वाला एक इस्पात संयंत्र है। कंपनी का लक्ष्य इस संयंत्र में कम कार्बन उत्सर्जन वाली उत्पादन प्रक्रियाएं स्थापित कर लागत कम करना, उत्पाद मिश्रण एवं मार्जिन बेहतर बनाना है।

8वें वेतन आयोग से बढ़ेगा कर्मचारियों का बैंक बैलेंस, लाखों के एरियर की तैयारी!

नई दिल्ली ।

केंद्र की मोदी सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है। केंद्र सरकार हर 10 साल में एक वेतन आयोग का गठन करती है, और चूंकि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से प्रभावी थीं, जिसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है, इसके बाद 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। इसका अर्थ यह है कि जब भी नया वेतन आयोग आधिकारिक तौर पर लागू होगा, कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से लेकर लागू होने की तारीख तक का पूरा अंतर एकमुश्त एरियर के रूप में मिलेगा।

वर्तमान में, वेतन आयोग देश के विभिन्न राज्यों का दौरा कर कर्मचारी यूनियनों और पेंशनभोगियों से उनके काम और वेतन संबंधी सुझाव ले रहा है। आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट जमा करने के लिए 18 महीने का समय मिलेगा, जिसका मतलब है कि यह रिपोर्ट मई 2027 के आसपास केंद्र सरकार को सौंपी जा सकती है। इसके बाद, सरकार मंत्रियों के एक समूह का गठन करेगी जो सिफारिशों की समीक्षा करेगा, और अंत में केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में अतिरिक्त 3 से 6 महीने लग सकते हैं, जिससे अंतिम लागू होने की तारीख 2027 के अंत तक जा सकती है। हालांकि, यह स्पष्ट है कि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने के कारण, कर्मचारियों को लगभग 20 से 24 महीनों का मोटा एरियर प्राप्त होगा।

आप समझते हैं कि 50,000 रुपये की मूल सैलरी पर एरियर की गणना कैसे होगी। मान लीजिए किसी कर्मचारी की वर्तमान बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है और उस 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) मिल रहा है, तब उसकी कुल सैलरी 80,000 रुपये (50,000 + 30,000) होगी। अगर सरकार 8वें वेतन आयोग के तहत 2.57 का फिटमेंट फैक्टर चुनती है, तब नई बेसिक सैलरी बढ़कर 1,28,500 रुपये हो जाएगी। इस स्थिति में, मौजूदा सैलरी से मासिक अंतर 48,500 रुपये का होगा।

वाणिज्य मंत्री ने अमेरिकी दिग्गजों को भारत में निवेश का न्योता दिया

न्यूयॉर्क में प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात

वॉशिंगटन ।

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूयॉर्क में वैश्विक बीमा, प्रौद्योगिकी और निवेश क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने इन कंपनियों को भारत में उपलब्ध अपार अवसरों का लाभ उठाने और अपने संबंधित क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, खासकर बीमा, वित्तीय सेवाओं और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों में देश की बढ़ती क्षमता को रेखांकित करते हुए।

जी20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने अमेरिका पहुंचे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूयॉर्क में एआईए ग्रुप के चेयरमैन मार्क टकर, मेटलाइफ के अध्यक्ष मिशेल ए. खलाफ, जनरल अटलांटिक के चेयरमैन विलियम ई. फोर्ड और आईबीएम के चेयरमैन अरविंद कृष्णा से अहम बैठकें कीं। गोयल ने एआईए और मेटलाइफ के साथ अपनी चर्चा में भारत के व्यापक नियामकीय सुधारों और बढ़ती बीमा कवरेज मांग पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि '2047 तक सभी के लिए बीमा' की राष्ट्रीय परिकल्पना के अनुरूप, भारत वैश्विक बीमा कंपनियों के लिए दीर्घकालिक वृद्धि का एक आदर्श मंच प्रदान करता है। मंत्री ने भारत के तेजी से बढ़ते बीमा एवं वित्तीय सेवा क्षेत्र और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विशाल प्रतिभा उपलब्धता को भी रेखांकित किया, जो सहयोग के लिए उत्कृष्ट अवसर प्रदान करते हैं।

जनरल अटलांटिक के साथ बैठक में गोयल ने भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था से पैदा हो रहे निवेश अवसरों का लाभ उठाने और द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। आईबीएम के चेयरमैन अरविंद कृष्णा के साथ उन्होंने कृत्रिम मेधा (एआई), क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर बात की।

इसमें भारत की बड़ी प्रतिभा क्षमता और तेजी से बढ़ते डिजिटल उपयोग का लाभ उठाकर वैश्विक समाधान विकसित करने पर जोर दिया गया। गोयल ने अमेरिकी कारोबारियों और भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया।

यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री सितंबर में बढ़कर रिकॉर्ड 4.27 लाख इकाई पहुंची- फाडा

दोपहिया और वाणिज्यिक वाहनों में भी जोरदार उछाल

मुंबई ।

सितंबर में भारत के वाहन खुदरा बाजार ने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल डीलर्स (फाडा) द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, कुल वाहन खुदरा बिक्री सालाना आधार पर 31.82 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि के साथ 25,36,920 इकाई पर पहुंच गई। फाडा की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले महीने यात्री वाहन बिक्री 32.1 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 4,27,213 इकाई रही। दोपहिया वाहनों की मांग भी 33.08 प्रतिशत बढ़कर 17,90,188 इकाई तक पहुंच गई, जबकि तिपहिया वाहनों की बिक्री 22.25 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1,32,570 इकाई दर्ज की गई। वाणिज्यिक वाहनों ने भी शानदार प्रदर्शन किया, जिनकी बिक्री 37.62 प्रतिशत बढ़कर 1,03,557 इकाई हो गई। फाडा के एक अ धिकारी ने इस प्रदर्शन को भारतीय वाहनों की खुदरा बिक्री के लिहाज से अब तक का सबसे अच्छा सितंबर बताया। उन्होंने कहा कि फाडा द्वारा ट्रैक की जाने वाली छह में से पांच श्रेणियों ने इस बार रिकॉर्ड स्तर पर बिक्री दर्ज की है।



बॉस हों पार्ट टाइमर तो ऐसे करें डील

जॉब के दौरान कई परिस्थितियों से दो चार होना पड़ता है। ऐसा हो सकता है कि कंपनी पार्ट टाइम बॉस को नियुक्त कर दे। ऐसी स्थिति में टीम की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बॉस के साथ तालमेल बैठाकर उन्हें फैसले लेने होते हैं...

जब आपके ऑफिस में पार्ट टाइम काम करने वाले बॉस हों और आप फुल टाइमर एम्प्लॉइ हों, तो स्थिति थोड़ी सी नाजुक हो जाती है। ऐसे में पूरी टीम को बॉस के साथ बराबर टच में रहना होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि टीम को फुल टाइमर बॉस की कमी महसूस होती है। टीम को कई मुद्दों पर बातचीत करने की जरूरत होती है। कई बार ऐसा होता है कि पार्ट टाइमर बॉस पूरा समय नहीं दे पाते हैं। आप अपनी कंपनी में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं, तो यहां पर दिए जाने वाले टिप्स कारगर साबित हो सकते हैं। आइए डालते हैं एक नजर –

मानसिकता सही रखें

एक्सपर्ट कहते हैं कि एक पार्ट टाइमर बॉस किसी संस्था में काम करता है, तो वहां पर काम करने वाले लोगों के मन में यह भावना विकसित हो सकती है कि वह पावर का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। बॉस का पद जिम्मेदारी भरा पद होता है और कंपनी बॉस पर भी नजर रखती है। याद रखें कि इसके लिए कंपनी हमेशा ही अपने स्तर पर सही व्यक्ति का चुनाव करती है। ऐसे में यह है कि टीम भी सही मानसिकता के साथ बॉस को सहयोग दे और अपना काम करे। वह कॉरपोरेट जगत के वैल्यू को समझे।

कम्यूनिकेशन का होता है अहम रोल

जहां बॉस पार्ट टाइम काम करते हैं और उनके साथ काम करने वाले बाकी लोग फुल टाइम जॉब करते हैं, वहां पर कम्यूनिकेशन का रोल अहम हो जाता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि ऐसी स्थिति में टीम को बॉस के साथ कम्यूनिकेशन लेवल हाई रखना पड़ता है। एक बार कम्यूनिकेशन करने का स्टाइल फिक्स हो जाता है, तो बाद में चीजों को बदल पाना आसान नहीं होता है। जब कम्यूनिकेशन सही रहेगा तो प्रॉब्लम का निपटारा भी पलक झपकते ही हो जाएगा। ऐसे में पार्ट टाइमर बॉस के संग भी टीम बेहतर रिजल्ट दे सकती है।

फैसला लेने की कला सीखें

आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं, जहां फुल टाइमर बॉस नहीं हैं, तो जरूरी है कि टीम का हर एक सदस्य खुद पर भरोसा दिखाए और फैसला लेने की कला सीखे। याद रखें कि जब बॉस फुल टाइमर नहीं होते हैं, तो सबसे ज्यादा दिक्कत फैसला लेने में ही होती है। वर्कप्लेस पर कई बार आपको पलक झपकते ही बड़े फैसले लेने होते हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा यह होता है कि आप आज के कॉम्पिटिशन भरे माहौल में टीम में तेजी कैसे लाएं। जॉब एक्सपर्ट कहते हैं कि इससे निपटने के लिए कंपनियों को चाहिए कि वह फैसला लेने के अधिकार को बांट दे। इससे जहां टीम के सदस्यों में कॉन्फिडेंस पैदा होता है, वहीं समय के भीतर फैसला लेने से काम में तेजी भी आती है।

...तो आप भी हैं कामयाब लीडर

एक लीडर में अपनी बात को असरदार तरीके से दूसरों तक पहुंचाने का हुनर आना चाहिए। एक लीडर, अगर वह अपनी बात अपने साथ काम करने वालों को बेहतर तरीके से कम्यूनिकेट कर पाने में समर्थ है, तो इससे कामकाजी माहौल ऊर्जा से भर जाता है, लोग उत्साह से काम में जुटते हैं और उनकी रचनात्मकता काम में झलकने लगती है। एक दूरदर्शी सोच रखने वाला लीडर एक जुनूनी टीम बनाने में यकीन रखता है। यह टीम एक समान लक्ष्यों के लिए पूरे जोशोखरोश से काम करती है। अपना कारोबार फैलाती किसी भी कंपनी को एक मजबूत मैनेजमेंट के साथ-साथ ऐसी टीम की भी दरकार रहती है, जो साथ काम करने वाले लोगों के बीच आपसी एकता, यकीन और आदर की बुनियाद पर बनी हो। कामयाबी का राज है, कामकाज में साफ-सुथरापन। एक कामयाब लीडर इस बात की अहमियत जानता है और अच्छे कामकाज के लिए अपने एंप्लॉई के साथ एक बेहतर समझ विकसित करता है। इससे न सिर्फ कामकाज का बिना किसी रुकावट के निपटारा होता जाता है, बल्कि टीम के भीतर एक खुशनुमा कामकाजी माहौल भी बरकरार रहता है।



इन बातों का ध्यान रखें तो कदम चूमेगी कामयाबी

जब आप अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट होते हैं, तो यह जान जाते हैं कि आप कौन हैं? आप क्या हैं? आपको क्या करना है और आप क्या चाहते हैं? अगर ये चीजें आपके दिमाग में साफ हैं, तो आपकी सफलता का पहला चरण सुनिश्चित हो जाता है।

बनें योग्य

कामयाब होने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि आप खुद को योग्य बनाएं। क्योंकि आप तब तक ऊपर नहीं चढ़ सकते, जब तककि आप में योग्यता नहीं हो। इसलिए पहले खुद को योग्य बनाना जरूरी होता है। इसके लिए लगातार प्रयत्न करना पड़ेगा। याद रखें कि कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है।

दबाव झेलने की क्षमता

जब जिम्मेदारी बढ़ेगी तो दबाव के साथ-साथ अवरोध भी उत्पन्न होगा। ऐसे में इस तरह की विपरीत परिस्थितियों को झेलने की क्षमता आपमें जरूर होनी चाहिए। वैसे जब आपको एवरेस्ट पर चढ़ाई करनी हो तो रास्ते में दिक्कतें तो आएंगी ही। दिक्कतों का सामना करने से ही सफलता का दरवाजा खुलता है।

भरपूर एकाग्रता जरूरी

इसके बिना तो आप साइकल भी नहीं चला सकते। एकाग्रता एक ऐसी चीज है, जो हर जगह काम आती है। आप अपने काम में इसके द्वारा ही परफेक्शन लाते हैं। किसी भी काम को साधारण से असाधारण बनाने के लिए एकाग्रता की जरूरत होती है। इसके माध्यम से आप बड़े से बड़े लक्ष्य को भेद सकते हैं।

रचनात्मकता भी जरूरी

एक प्रफेशनल की सफलता में उसकी रचनात्मकता का काफी अहम योगदान होा है। इसलिए इस ओर ध्यान देना जरूरी है।

साहस बनाए रखें

कहते हैं रिस्क लेने के बाद ही आगे बढ़ने का रास्ता खुलता है। इसके लिए साहस सबसे जरूरी चीज है। किसी ने सही कहा है कि हिम्मत रखने वालों की कभी हार नहीं होती इसलिए जीतने के लिए साहस बहुत जरूरी है।





हार्डवेयर फील्ड में खूब हैं जॉब, मस्त सैलरी

आज शायद ही ऐसा कोई ऑफिस हो, जहां का कामकाज कंप्यूटर पर आधारित न हो। इसके अलावा, घर, स्कूल आदि जगहों पर भी सभी कामकाज कंप्यूटर पर ही किए जाते हैं। अगर ये सुचारू रूप से काम न करें, तो सारा कामकाज अचानक ठप हो सकता है। बैंकों और अन्य सरकारी कार्यालयों में नेटवर्क फेल होने की वजह से काम ठप रहने की खबरें आपने अक्सर पढ़ी होंगी, तब इस नेटवर्क को सही करने के लिए हार्डवेयर प्रफेशनल्स की ही मदद ली जाती है। नेटवर्किंग दरअसल कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर ऐसा जाल बनाने का फील्ड है जिसमें कोई संस्थान काम कर सके। कुल मिलाकर, कंप्यूटर इंस्टॉलेशन से लेकर, इसकी मेंटेनेंस और रोजमर्रा के ऐडमिनिस्ट्रेशन तक का सारा जिम्मा कंप्यूटर सपोर्ट स्पेशलिस्ट्स यानी हार्डवेयर इंजिनियर्स के जिम्मे होता है।

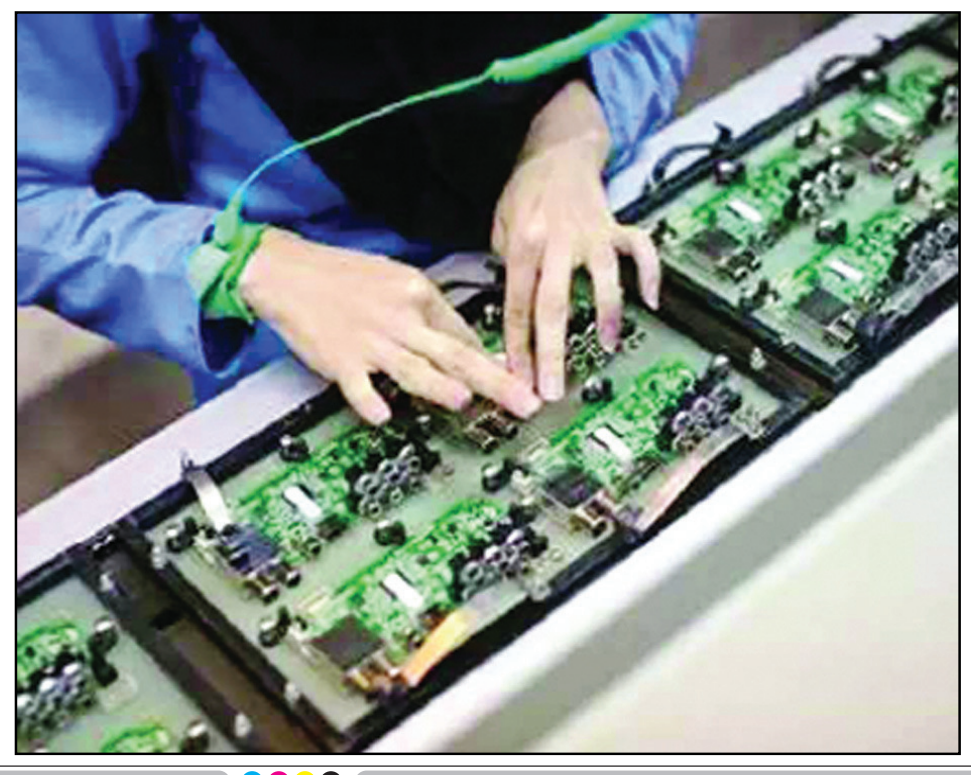
कोर्स

हार्डवेयर इंजिनियर बनने के लिए मुख्य रूप से दो बेसिक कोर्स करने पड़ते हैं। पहला, हार्डवेयर और दूसरा बेसिक नेटवर्किंग। हार्डवेयर रिलेटिड कोर्स से कंप्यूटर पार्ट्स के बारे में तमाम तकनीकी जानकारी मिलती है। एक हार्डवेयर इंजिनियर या सिस्टम ऐडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए ये दोनों कोर्स करने बेहद जरूरी हैं। नेटवर्किंग में इससे आगे कोई एक्सपर्ट बनना हो, तो अपनी पसंद के हिसाब से कुछ और बेसिक कोर्स करने होंगे, जैसे - लैन (लोकल एरिया नेटवर्क) और वैन (वाइड एरिया नेटवर्क) से जुड़े कोर्स। नेटवर्किंग से जुड़े कोर्स कराने के लिए कई सरकारी और प्राइवेट संस्थान हैं, जिन्होंने इन कोर्सेज के लिए अपनी अलग पहचान बनाई है। नेटवर्किंग सीखने के लिए तीन तरीके हैं - पहला ऑनलाइन स्टडी मटीरियल की मदद से खुद पढ़ाई, दूसरा ऐसे इंस्टिट्यूट्स जो किसी प्रोग्राम से जुड़े नहीं हैं और तीसरा सर्टिफाइड प्रोग्राम।



जॉब की कमी नहीं

एक्सपर्ट्स बताते हैं कि नेटवर्किंग में कोर्स करने के बाद कंप्यूटर सपोर्ट स्पेशलिस्ट, हेल्प डेस्क टेक्निशन, नेटवर्क या सिस्टम ऐडमिनिस्ट्रेटर, कंप्यूटर सिक्यॉरिटी स्पेशलिस्ट के रूप में करियर बना सकते हैं। आज इन एक्सपर्ट्स की जरूरत लगभग हर संस्थान में होती है। फिर चाहे वह कंप्यूटर और डेटा प्रोसेसिंग यूनिट हों, बैंक या अन्य सरकारी कार्यालय, कोई इंडस्ट्री या और कोई छोटी-बड़ी फर्म। जहां भी कामकाज कंप्यूटर आधारित है, वहां इन तकनीकी विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती है। सरकारें जिस तरह ई-गवर्नेंस पर जोर दे रही हैं, उससे यह फील्ड और भी हॉट बनता जा रहा है। इसके चलते स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क और डाटा सेंटर जैसे कई नए फील्ड खुल रहे हैं। कहा जा सकता है कि जब तक कंप्यूटर पर काम होता रहेगा, इन विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती रहेगी। ये किसी भी कंपनी के लिए नेटवर्क और कंप्यूटर सिस्टम की देखभाल से लेकर, एंप्लायीज और कस्टमर्स की तकनीकी जिज्ञासाओं को शांत करने तक का काम करते हैं। एंट्री लेवल पर आपकी जिम्मेदारी केवल नेटवर्क और कंप्यूटर मेंटेनेंस की हो सकती है, लेकिन अनुभव के साथ आपको किसी कंपनी के लिए इंट्रानेट आदि डिवेलप करने का जिम्मा भी दिया जा सकता है।



मनी मैटर्स

बरसों से आईटी फील्ड में अच्छी-खासी सैलरी रही है। हार्डवेयर प्रफेशनल्स के लिए सॉफ्टवेयर प्रफेशनल्स की तरह मौकों की कोई कमी नहीं है। एंट्री लेवल पर आप 25 से 35,000 रुपये महीने की जॉब पा सकते हैं। अनुभव और समय के साथ इसमें बढ़ोतरी होगी।

आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड की दौड़ में शैफाली, चरणी और अटापट्टू शामिल

दुबई (एजेंसी)। भारत की शैफाली वर्मा और श्री चरणी के साथ ही श्रीलंका की कप्तान चामरी अटापट्टू को सितंबर महीने के आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड की रैस में शामिल किया गया है। शैफाली वर्मा ने सितंबर के महीने में सात टी20 मैचों में कुल 360 रन बनाए, जिसमें उनका औसत 72 और स्ट्राइक रेट 184.61 का प्रभावशाली रहा। बल्ले के साथ-साथ, शैफाली ने अपनी ऑफ-स्पिन गेंदबाजी से भी योगदान दिया और पूरे महीने में छह महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए। महिला एशिया कप में वह पांच पारियों में 236 रन बनाकर टूर्नामेंट की शीर्ष स्कोरर रहीं। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल में 64 और श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में 68 रन की महत्वपूर्ण पारियां खेलीं, जिससे भारत को रिकॉर्ड आठवां एशिया कप खिताब जीतने में मदद मिली। जापान में हुए एशियाई खेलों में भी शफाली ने तीन पारियों में 188 रन बनाए। बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल में, उन्होंने सिर्फ 49 गेंदों पर धमाकेदार 100 रन बनाकर अपने करियर का पहला टी20 शतक लगाया।

वहीं, भारत की बाएं हाथ की स्पिनर श्री चरणी ने पूरे सितंबर में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने सात टी20 मैचों में कुल 18 विकेट लिए, जिसमें उनका गेंदबाजी औसत 4.83 और इकॉनमी रेट 3.30 रहा। महिला एशिया कप में चरणी ने भारत की खिताबी जीत में अपनी अहम भूमिका निभाई, जहां उन्होंने टूर्नामेंट में 12 विकेट हासिल किए। श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में 4/20 का उनका स्पेल मैच विजेता रहा। एशियन गेम्स में भी चरणी ने अपनी दबदबा कायम रखा, जापान के खिलाफ 4/10, बांग्लादेश के खिलाफ 2/7 और श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में 2/13 के आंकड़े दर्ज करते हुए कुल आठ विकेट लिए। चरणी ने सितंबर के अंत में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी बनाया, जब वह आईसीसी महिला टी20 प्लेयर रैंकिंग्स में 817 रेटिंग अंकों के साथ महिला क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा रेटिंग हासिल करने वाली गेंदबाज बन गईं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की मेगन शुट्ट के 806 अंकों का रिकॉर्ड तोड़कर यह उपलब्धि हासिल की।

इसके अलावा श्रीलंका की कप्तान चामरी अटापट्टू भी इस अवॉर्ड की मजबूत दावेदार हैं। उन्होंने सितंबर में ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए सात टी20 में 226 रन बनाए, जिसमें उनका बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट 140.37 रहा। साथ ही, उन्होंने अपनी ऑफ-स्पिन से 14 विकेट भी हासिल किए,



उनका गेंदबाजी औसत 10.21 रहा।

इस प्रकार, शफाली वर्मा की विस्फोटक बल्लेबाजी, श्री चरणी की रिकॉर्डतोड़ गेंदबाजी, और चामरी अटापट्टू के दमदार ऑलराउंड प्रदर्शन ने प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड की दौड़ को बेहद रोमांचक बना दिया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि किसे ये अवॉर्ड मिलता है।

दिल्ली कैपिटल्स के मुख्य कोच बने गांगुली



नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली कैपिटल्स ने आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सत्र को देखते हुए भारतीय क्रिकेट के दिग्गज और पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को अपना नया मुख्य कोच बनाया है। फ्रेंचाइजी को उम्मीद है कि कि गांगुली जैसे अनुभवी के कोच बनने से टीम आईपीएल 2027 सत्र में बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रहेगी। गांगुली पहली बार आईपीएल में मुख्य कोच के तौर पर नजर आयेंगे हालांकि वह पहले भी दिल्ली फ्रेंचाइजी में डायरेक्टर रहे थे। उन्हें हेमंग बदानी की जगह मुख्य कोच बनाया गया है। बदानी पिछले दो साल से दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच थे पर टीम कुछ खास सफलता हासिल नहीं कर पायी। बदानी के अलावा, टीम ने गेंदबाजी कोच मुनाफ पटेल, सहायक कोच इयान बेल और टीम डायरेक्टर वेणुगोपाल राव को भी हटाने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि गांगुली अपनी टीम को अपनी रणनीतिक सोच के अनुरूप ढालने के लिए अपना खुद का सहायोगी स्टाफ बनाना चाहते हैं, जिसके चलते ये बड़े बदलाव किए गए हैं।

गौरतलब है कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए पिछले दो आईपीएल सीज़न बेहद निराशाजनक रहे थे। टीम आईपीएल 2025 में पांचवें और 2026 में छठे स्थान पर रही थी, दोनों बार प्लेऑफ में जगह बनाने में विफल रही। ऐसे में, गांगुली जैसे अनुभवी और सफल लीडर की नियुक्ति को टीम के भाग्य को पलटने के एक बड़े प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। गांगुली साल 2019 से ही फ्रेंचाइजी से जुड़े हुए हैं, जहां उन्होंने पुरुष और महिला दोनों टीमों में डायरेक्टर की भूमिका निभाई थी।

कोचिंग स्टाफ में गांगुली को पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज युवराज सिंह का साथ मिल सकता है, हालांकि इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हेड कोच के तौर पर गांगुली का यह पहला आईपीएल अनुभव होगा, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी लीग एसए 20 लीग में प्रिटोरिया कैपिटल्स के हेड कोच रहते हुए वे अपनी टीम को फाइनल तक ले जाने में सफल रहे थे, जो उनके कोचिंग कौशल का प्रमाण है।

गांगुली ने इस नई भूमिका को लेकर खुशी जाहिर करते हुए कहा, मैं आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स टीम का हेड कोच का पद संभालने को उत्साहित हूं। दिल्ली कैपिटल्स फ्रेंचाइजी मेरे दिल के बहुत करीब रही है और पिछले सालों इसके साथ मेरे रिश्ते और मजबूत हुए हैं। उन्होंने एक मजबूत और निडर टीम बनाने का दावा किया, जो मैदान पर अपने प्रदर्शन से विरोधियों को चुनौती दे सके।

गांगुली दिल्ली कैपिटल्स की टीम में अक्षर पटेल और केएल राहुल जैसे प्रमुख खिलाड़ियों के साथ काम करते दिखेंगे। इस सीज़न से पहले टीम में एक और बड़ा बदलाव ऋषभ पंत की वापसी के रूप में हुआ है। पंत ने दो साल लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी की थी, लेकिन आईपीएल 2026 के समापन के बाद दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच हुए एक बड़े ट्रेड के तहत वे दिल्ली लौटे।

सूर्यकुमार को मुंबई की रणजी ट्रॉफी टीम में भी जगह नहीं मिली

मुम्बई (एजेंसी)। भारतीय टी20 क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव जब से टीम से बाहर हुए हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। यहां तक कि अब उन्हें मुंबई की रणजी ट्रॉफी टीम में भी जगह नहीं मिली है, जिससे उनके प्रथम श्रेणी करियर पर गंभीर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ये इससे भी समझा जा सकता है कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) की चयन समिति ने आगामी रणजी ट्रॉफी सत्र के पहले मैच के लिए सूर्यकुमार से उनकी उपलब्धता पूछी थी। सूर्यकुमार ने 11 अक्टूबर से वानखेड़े स्टेडियम में चंडीगढ़ के खिलाफ होने वाले इस मुकाबले के लिए खेलने के लिए सहमति दी थी। इसके बाद भी उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया, जिसने चयन प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं।



एमसीए के चयन प्रमुख राजेश पवार ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि सूर्यकुमार ने पिछले 18 महीनों से कोई लाल गेंद का क्रिकेट मैच नहीं खेला है, इसलिए चयन समिति चाहती है कि वे कुछ मैच खेलकर अपनी लय हासिल करें और फिर टीम में वापसी करें। हालांकि, इस तर्क पर सवाल उठ रहे हैं कि जब चयनकर्ताओं को उनकी हालिया प्रथम श्रेणी फॉर्म का पता था, तो उन्होंने पहले उनसे संपर्क कर उपलब्धता क्यों पूछी? यह घटना चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता और सूर्यकुमार के प्रति रवैये पर संदेह पैदा करती है। पूर्व कप्तान सूर्यकुमार को जिस तरह से पहले कप्तानी से हटाकर टीम से बाहर किया गया और अब रणजी टीम में भी जगह नहीं दी गई, वह किसी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। सूर्या के लिए यह एक बड़ा झटका है, जिससे उनके आत्मविश्वास पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

आईसीसी के सितंबर माह के प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड के लिए शुभमन, अभिषेक और रजा में होगा मुकाबला

मुम्बई (एजेंसी)। भारत के अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के अलावा जिम्बाब्वे के अनुभवी ऑलराउंडर सिकंदर रजा को सितंबर 2026 में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आईसीसी मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड के लिए नामांकित किया गया है। अभिषेक ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया था। उन्होंने इस सीरीज में 76.33 की शानदार औसत से कुल 229 रन बनाए। सीरीज के पहले मैच में ही उन्होंने सिर्फ 32 गेंदों पर 82 रन की तूफानी पारी खेलकर भारत को धमाकेदार जीत दिलाई थी। उनकी प्रतिभा का असली सबूत सीरीज के तीसरे मैच में देखने को मिला, जब उन्होंने महज 45 गेंदों पर 108 रन की ऐतिहासिक पारी खेली। इस दौरान उन्होंने सिर्फ 30 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जो टी20 में सबसे तेज शतक का नया रिकॉर्ड बन गया। उनकी इस अद्भुत पारी में 11 छक्के शामिल थे और उनका स्ट्राइक रेट 317.64 रहा। अभिषेक की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर भारत ने तीसरे मैच में पावरप्ले में 100/0 का रिकॉर्ड स्कोर खड़ा किया। उन्हें इस मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और वह पूरी सीरीज के प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे। इस शानदार प्रदर्शन के साथ उन्होंने टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में दूसरा स्थान मजबूत किया, जिससे उनकी पहचान एक उभरते हुए सुपरस्टार के रूप में स्थापित हुई।

वहीं भारतीय टीम के एक और सितारे, शुभमन गिल ने सितंबर माह में एकदिवसीय क्रिकेट में अपना शानदार फॉर्म जारी रखा। वेस्टइंडीज के खिलाफ तिरुवनंतपुरम में उन्होंने 108 गेंदों पर 110 रन की महत्वपूर्ण पारी खेलकर भारत को 296 रन के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा करने में मदद की। यह गिल के एकदिवसीय करियर का 10वां शतक था। इसके अलावा, गिल ने सितंबर में एक और यादगार प्रदर्शन करते हुए मात्र 62 गेंदों में शतक और 117 गेंदों में दोहरा शतक पूरा किया, जिससे उन्होंने 223 रन की नाबाद पारी खेली। यह सफल वनडे रन चेज में किसी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बन गया। कप्तान के रूप में भी उन्होंने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए, जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है।

वहीं जिम्बाब्वे के अनुभवी ऑलराउंडर सिकंदर रजा भी इस अवॉर्ड की दौड़ में शामिल हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में अपनी टीम के लिए प्रभावशाली प्रदर्शन किया। भले ही जिम्बाब्वे वह सीरीज हार गया, लेकिन रजा ने बल्ले और गेंद दोनों से अहम योगदान दिया। पहले वनडे में उन्होंने 57 रन बनाकर जिम्बाब्वे की पारी को संभाला, जो उनके अनुभव और कौशल का प्रमाण था। सितंबर के इस रोमांचक महीने में अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और सिकंदर रजा तीनों ने ही अलग-अलग फॉर्मेट में अपने खेल से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है। उनके इन उत्कृष्ट प्रदर्शनों ने इस महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड के मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है।

भुवनेश्वर हांगकांग सिक्स सीरीज के लिए भारतीय टीम के कप्तान बने

मुम्बई। अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को हांगकांग सिक्स सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है। भुवनेश्वर के अलावा स्पिन ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या और तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर नितीश राणा को भी टीम में शामिल किया गया है। भूवी के नाम से लोकप्रिय भुवनेश्वर ने भारतीय टीम के लिए पिछला मुकाबला नवंबर 2022 में खेला था। हांगकांग सिक्स सीरीज के लिए भुवनेश्वर को भारतीय टीम की कप्तानी दी गयी है। टीम में भुवनेश्वर के अलावा आईपीएल से भी कुछ खिलाड़ियों को अवसर मिला है। हांगकांग सिक्स सीरीज की शुरुआत 30 अक्टूबर से होगी। वहीं टूर्नामेंट का समापन 01 नवंबर को होगा। इस टूर्नामेंट में कुल 12 टीमें हिस्सा लेंगी। इन टीमों को 4 पूल्स में बांटा गया है। पूल-ए में- हांगकांग चीन, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है। वहीं पूल-बी में श्रीलंका, बांग्लादेश और स्कॉटलैंड है। पूल-सी में- भारत, पाकिस्तान और यूएई है। पूल-डी में- दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान और ओमान है।

विश्व कप से पहले 47 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेलेगी भारतीय टीम

मुम्बई। भारतीय क्रिकेट टीम ने अगले साल होने वाले एकदिवसीय विश्व कप की तैयारियां शुरु कर दी हैं। इसी के तहत ही भारतीय टीम अब विश्वकप से पहले कुल 18 टी20, 20 एकदिवसीय और 9 टेस्ट मैच खेलेगी, इससे विभिन्न प्रारूपों में खिलाड़ियों की क्षमता और अनुकूलनशीलता की असली परीक्षा होगी। इन अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के अलावा, विश्व कप में संभावित रूप से चुने जाने वाले भारतीय खिलाड़ी प्रतिष्ठित आईपीएल और एशिया कप जैसे महत्वपूर्ण टूर्नामेंटों में भी अपनी उतरेंगे। । यह कार्यक्रम टीम प्रबंधन और खिलाड़ियों दोनों के लिए कार्यभार प्रबंधन और चोट से बचाव की रणनीति बनाने में एक बड़ी चुनौती पेश करेगा। एकदिवसीय विश्व विश्व कप से पहले भारतीय टीम का यह व्यस्त कार्यक्रम मार्च 2027 तक चलेगा, जिसके बाद विश्व कप से ठीक पहले कुछ और अहम दौरे संभावित हैं। सितंबर और अक्टूबर 2026 में, भारतीय टीम अपने घर में तीन एकदिवसीय और पांच टी20 मैचों की एक सीरीज खेलेगी। इसके तुरंत बाद, अक्टूबर और नवंबर 2026 में, टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर जाएगी, जहाँ उसे पांच टी20, पांच एकदिवसीय और दो टेस्ट मैचों की एक लंबी सीरीज खेलनी होगी। वहीं दिसंबर 2026 में, भारतीय टीम तीन एकदिवसीय मैचों की सीरीज श्रीलंका के साथ खेलेगी। वहीं नए साल, यानी जनवरी 2027 की शुरुआत, भारतीय टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन एकदिवसीय मैचों की सीरीज से करेगी। जनवरी से मार्च 2027 के बीच, क्रिकेट प्रेमियों को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच प्रतिष्ठित बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के तहत पांच टेस्ट मैचों की रोमांचक सीरीज देखने को मिलेगी। इस कड़ी टेस्ट सीरीज के बाद, भारतीय खिलाड़ी आईपीएल और एशिया कप जैसे टूर्नामेंटों की तैयारी में जुट जाएंगे। विश्व कप से ठीक पहले, भारतीय टीम के वेस्टइंडीज दौरे की संभावना भी प्रबल है, जहाँ टीम को पांच टी20, तीन एकदिवसीय और दो टेस्ट मैच खेलने पड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त, एकदिवसीय विश्व कप से ठीक पहले दक्षिण अफ्रीका का दौरा भी संभावित है, इस दौरे पर दोनों टीमों के बीच छह वनडे मैच खेले जाने की उम्मीद है।

हरमनप्रीत ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तानी से इस्तीफा दिया

मंधाना को मिल सकती है कमान

मुम्बई (एजेंसी)। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अचानक ही तीनों प्रारुपों की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। महिला क्रिकेट टीम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाली हरमनप्रीत ने इस अवसर पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि यह फैसला उनके लिए आसान नहीं था। इस घोषणा के बाद, भारतीय महिला टीम की अगली कप्तान के नाम पर अटकलें तेज हो गई हैं, इसमें स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना सबसे आगे हैं। मंधाना लंबे समय से टीम की उप-कप्तान रही हैं और तीनों प्रारुपों में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, इस कारण से उन्हें इस पद के लिए सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है।

अपनी पोस्ट में, हरमनप्रीत ने लिखा, आज, मैं सभी प्रारुपों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान के पद से हट रही हूं हालांकि यह मेरे लिए कोई आसान फैसला नहीं था। उन्होंने अपने कप्तानी केको याद करते हुए कहा कि इसमें इसमें कई यादें, भावनाएं, त्याग और ऐसे पल शामिल हैं जो जिंदगी भर मेरे साथ रहेंगे। हरमनप्रीत ने कहा कि उन्होंने टीम को अपना सब कुछ दिया–अपना खून, अपना पसीना, अपना समय र कई बार, अपने खेल और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को भी एक तरफ रखना पड़ा, क्योंकि उनका मानना था कि टीम पहले आनी चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया कि एक कप्तान के रूप में, उन्हें मुश्किल फैसले लेने पड़े, जो हमेशा समझ में नहीं आए या आसान नहीं थे, और कभी-कभी उन्हें व्यक्तिगत कीमत भी चुकानी पड़ी। लेकिन हर फैसले का एक ही लक्ष्य था और वह ये कि टीम को बेहतर बनाना और अन्य खिलाड़ियों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन लेन।

हरमनप्रीत ने अपने कप्तानी करियर के दौरान सबसे बुरे पल, दिल टूटना, संदेह और ऐसे दिन देखे जब कुछ भी टीम के पक्ष में नहीं गया, और साथ ही जीत, जश्न, देश का प्रतिनिधित्व करने का गर्व और हर कुर्बानी के सफल होने के ऊंचे पल भी देखे। उन्होंने शांति और भावनाओं से भरे दिल के साथ कप्तानी छोड़ने की बात कही, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है कि उनकी टीम अच्छी स्थिति में है प्रतिभा, चरित्र, विश्वास और भविष्य से भरी हुई है। अपनी पोस्ट के अंत में, उन्होंने लिखा, मुझे लगता है कि मैंने अपना फर्ज निभाया है। मैंने इस टीम को अपना सब कुछ दिया। अब, मेरे लिए पन्ना पलटने का समय आ गया है। कप्तानी आज खत्म हो सकती है, लेकिन भारतीय क्रिकेट के लिए मेरा प्यार कभी नहीं होगा। उन्होंने सभी टीममेट्स, कोच, सपोर्ट स्टाफ, मैनेजमेंट, बीसीसीआई, परिवार और प्रशंसकों का धन्यवाद किया।



हरमनप्रीत ने पिछले लगभग एक दशक से भारतीय महिला क्रिकेट को अपनी सेवाएं दी हैं, जिसमें उन्होंने 2016 में टी20 टीम की कप्तानी संभाली थी। उनकी अगुवाई में भारत ने एकदिवसीय विश्वकप के साथही कई एशिया कप खिताब और हाल ही में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, जो उनकी कप्तानी की प्रमुख उपलब्धियां हैं। हरमनप्रीत ने कहा है कि अब वह बतौर खिलाड़ी भारतीय टीम को अपनी सेवाएं देती रहेंगी।

चीन ओपन टेनिस टूर्नामेंट : प्रशंसक की आंख में शॉट लगाने से मेदवेदेव हुए अयोग्य, जोकोविच फाइनल में पहुंचे



बीजिंग। यहां खेले गये चीन ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में रूसी टेनिस खिलाड़ी डेनिल मेदवेदेव का एक शॉट सीधे एक प्रशंसक की आंख में लगने से अयोग्य होकर बाहर हो गये। इससे सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच सीधे टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए। यह घटना जब हुई तब मेदवेदेव सर्बियाई खिलाड़ी जोकोविच से 7-5, 5-3 से पीछे चल रहे थे। रूसी खिलाड़ी ने गुस्से में एक शॉट मारा जो सीधे स्टैंड्स में बैठे एक दर्शक की आंख में लग गया। इस अप्रत्याशित हादसे से सभी लोग सकते में पड़ गये। ये हादसा तब हुआ जब मेदवेदेव एक अंक हारने से निराशा थे। उन्होंने बैकबोर्ड से टकराकर वापस आ रही गेंद पर इतनी तेजी से शॉट लगाया कि गेंद सामने बैठे एक दर्शक की बाईं आंख में जा लगी। दर्शक तुरंत अपनी आंख पकड़कर दर्द से कराह उठा, जिससे खेल कुछ समय के लिए रुक गया। घायल दर्शक को तुरंत स्टेडियम कर्मचारियों की मदद से उपचार के लिए बाहर ले जाया गया। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए, अंपायर मोहम्मद लाहयानी और एटीपी अधिकारियों ने मेदवेदेव को मैच से आगे खेलने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। मेदवेदेव ने घटना के बाद नेट के पास आकर जोकोविच से हाथ मिलाया और कहा कि उन्हें इस घटना का बेहद दुख है और वह दर्शक से भी माफी मांगना चाहते हैं। वहीं जोकोविच ने इस घटना पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए मेदवेदेव के प्रति सहानुभूति जताई। साथ ही कहा कि साल 2020 यूएस ओपन में उन्हें भी इसी तरह एक लाइन जज को अनजाने में गेंद लगने के कारण अयोग्य घोषित किया गया था। जोकोविच ने कहा, मुझे उम्मीद है कि उस व्यक्ति को ज्यादा चोट नहीं आई होगी। दूसरी ओर मुझे डेनिलमेदवेदेव के लिए भी बुरा लग रहा है क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि किसी बड़े मैच में अयोग्य घोषित होने पर कैसा महसूस होता है। मुझे भरोसा है कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा। ये एक मानवीय भूल थी।

एबी डिविलियर्स को उम्मीद : 2027 विश्व कप दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट की नई पीढ़ी को प्रेरित करेगा

नई दिल्ली। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स को उम्मीद है कि 2027 पुरुष वनडे विश्व कप, जिसे दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे और नामीबिया के साथ मिलकर होस्ट करेगा, देश के क्रिकेटरों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित करेगा। उन्होंने बताया कि कैसे 2003 में देश में हुए एडिशन ने 19 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की चाहत रखने वाले उनके शुरुआती सफर को आकार दिया था। दक्षिण अफ्रीका 2 अक्टूबर से 21 नवंबर, 2027 तक 50 ओवर के इस मेगा इवेंट की सह-मेजबानी करेगा। डिविलियर्स ने एक विशेष चैट में बताया, 2003 वर्ल्ड कप ने मेरे करियर में बहुत बड़ा रोल निभाया। मुझे याद है कि यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिटोरिया में एक क्रिकेटिंग क्लिनिक में एडम गिलक्रिस्ट ने मेरी विकेटकीपिंग स्किल्स पर काम किया था। तीन साल बाद, मैंने उनके खिलाफ टेस्ट मैच और वनडे क्रिकेट खेला। उन्होंने आशा व्यक्त की कि 2027 वर्ल्ड कप का भी दक्षिण अफ्रीका के युवाओं पर वैसा ही असर पड़ेगा, जो एक दिन अपने देश का प्रतिनिधित्व करने की उम्मीद कर रहे हैं। डिविलियर्स ने इस आयोजन के आर्थिक लाभों और पर्यटन को बढ़ावा देने की क्षमता पर भी जोर दिया, साथ ही उम्मीद जताई कि प्रोटियाज टीम इस बार बेहतर प्रदर्शन करेगी, क्योंकि 2003 में उनका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था।

अर्जेंटीना के लिए आखिरी बार मैदान पर उतरेंगे लियोनेल मेस्सी, भावुक होगी विदाई

नई दिल्ली (एजेंसी)। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी मंगलवार को अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए आखिरी बार मैदान पर उतरेंगे। ब्यूनस आयर्स में बेनिन के खिलाफ होने वाले मैत्री मुकाबले को मेस्सी की विदाई के लिए खास बनाया गया है। इस मुकाबले को 'द नाइट दैट नो वन वॉन्ट्स टू एंड' यानी 'वह रात जिसे कोई खत्म नहीं करना चाहता' नाम दिया गया है।

हजारों फैंस रहेंगे मौजूद

39 वर्षीय मेस्सी के आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबले को देखने के लिए ब्यूनस आयर्स के एस्टाडियो मोनुमेंटल में हजारों प्रशंसकों के जुटने की उम्मीद है। अर्जेंटीना फुटबॉल संघ (एफ़ा) ने इस मुकाबले को सिर्फ एक फुटबॉल मैच के बजाय मेस्सी के शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर को सम्मान देने वाला खास पल बताया है।

मेस्सी ने कहा- 'इन पलों की कमी महसूस होगी'

मेस्सी ने अर्जेंटीना की टीम से जुड़ने और अपने आखिरी अभ्यास सत्र की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं। उन्होंने लिखा कि ये ऐसे खास पल हैं, जिनकी उन्हें आगे कमी महसूस होगी। मेस्सी ने पहले ही अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास का संकेत देते हुए कहा था कि अब समय आ गया है। इसके बाद एफ़ा ने उन्हें एक आखिरी मुकाबला खेलने के लिए मनाया, ताकि उन्हें सम्मानजनक विदाई दी जा सके।

विश्व कप जीतना रहा करियर का सबसे बड़ा पल

मेस्सी ने 2022 में कतर में अर्जेंटीना को विश्व कप जिताकर अपने करियर का सबसे बड़ा सपना पूरा किया था। इस खिताब के साथ उन्होंने अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना की उपलब्धि की बराबरी भी की।

हालांकि, मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना जुलाई में लगातार दूसरी बार विश्व कप जीतने से चूक गया। न्यू जर्सी में खेले गए फाइनल में अर्जेंटीना को स्पेन के खिलाफ 0-1 से हार का सामना करना पड़ा।

अर्जेंटीना के लिए सबसे ज्यादा गोल

मेस्सी ने अर्जेंटीना के लिए अब तक 207 मुकाबले खेले हैं और उनके नाम 125 गोल हैं। वह राष्ट्रीय टीम के सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। विश्व कप में भी मेस्सी के नाम 21 गोल दर्ज हैं। वह और उनके लंबे समय के प्रतिद्वंद्वी क्रिस्टियानो रोनाल्डो उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्होंने छह विश्व कप में हिस्सा लिया है।

2016 के बाद बदला मेस्सी का अंतरराष्ट्रीय सफर

मेस्सी ने 2016 में कुछ समय के लिए अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम से संन्यास लिया था। हालांकि, इसके बाद उनका अंतरराष्ट्रीय करियर शानदार दौर में पहुंचा। उन्होंने 2021 और 2024 में कोपा अमेरिका का खिताब जीता, जबकि 2022 में अर्जेंटीना को विश्व कप चैंपियन बनाया।



इसके बाद अर्जेंटीना की टीम ने लगातार बड़े टूर्नामेंटों में शानदार प्रदर्शन किया।

क्लब फुटबॉल में इंटर मियामी से जारी रहेगा सफर

अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से विदाई के बाद मेस्सी क्लब स्तर पर खेलते रहेंगे। वह फिलहाल इंटर मियामी का हिस्सा हैं। हाल ही में उन्होंने टीम के साथ कैम्पियोनेस कप जीता, जो क्लब के लिए उनका चौथा खिताब है। मेस्सी की अर्जेंटीना से विदाई के साथ अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल के एक ऐतिहासिक अध्याय का अंत होगा, लेकिन क्लब स्तर पर उनका सफर जारी रहेगा।

पाक सरकार पर बरसे शास्त्री, बोले इमरान खान को तत्काल रिहा किया जाये

मुम्बई। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री ने पाकिस्तान सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि पाक टीम के पूर्व कप्तान इमरान खान को तत्काल जेल से रिहा किया जाये। शास्त्री ने पाकिस्तान सरकार द्वारा इमरान के साथ किए जा रहे व्यवहार को अमानवीय बताते हुए उसकी कड़ी निंदा की और कहा कि देश को पहला एकदिवसय विश्व कप दिलाने वाले खिलाड़ी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। शास्त्री ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान की सरकार इमरान खान के साथ जो कर रही है, वह किसी भी मायने में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। शास्त्री ने इस स्थिति पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा, मैं कोई राजनेता नहीं हूं, लेकिन उनके साथ जिस तरह का सलूक किया जा रहा है, वह देखना वास्तव में हैरान करने वाला है। कोई भी किसी इंसान के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करता। इमरान के साथ इस समय जो हो रहा है, वह उसके बिल्कुल भी हकदार नहीं हैं। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं कह रहा, बल्कि पूरे विश्व में ऐसे कई क्रिकेटर होंगे जो मेरी इस बात का समर्थन करेंगे।



लक्ष्मण के रोल में दो बार रिजेक्ट हुआ, राम के रोल में चुना गया

'यारियां' से अपना एक्टिंग डेब्यू करने वाले देव शर्मा अभिनय की दुनिया में आने से पहले थिएटर और असिस्टेंट डायरेक्टर का अनुभव लेकर फिल्म मेकिंग और अभिनय की बारीकियां सीख चुके थे। 'मुजफ्फर नगर', 'जंक्शन वाराणसी', 'बेखुदी' जैसी कई फिल्मों में काम कर चुके देव इन दिनों चर्चा में हैं अपनी ताजा-तरीन फिल्म महाकाव्य 'श्री रामायण कथा' से। इस फिल्म में वे श्री राम की भूमिका में हैं।

सोशल मीडिया पर यह खबर सुर्खियों में है कि देव शर्मा को 'रामायण' में लक्ष्मण के किरदार के लिए एक नहीं, बल्कि दो बार रिजेक्ट किया गया था। अपनी नई फिल्म में भगवान राम का किरदार निभा रहे देव कहते हैं, 'हां, यह सच है। 'रामायण' में श्रीराम का किरदार मिलने से पहले मैं दो बार लक्ष्मण के लिए रिजेक्ट हुआ था। पहली बार (आदि पुरुष) में मेरा लुक टेस्ट अच्छा गया था, लेकिन उस रोल के लिए 20-25 और लोग भी कोशिश कर रहे थे। मुझे लगता है कि जिस कलाकार को चुना गया, उस दिन उसका अभिनय मुझसे थोड़ा बेहतर रहा होगा। दूसरी बार (रामायण) में भी बात कास्टिंग और शारीरिक बनावट के अनुपात की थी। अगर राम का किरदार निभाने वाला कलाकार 6 फीट 1 इंच का है और लक्ष्मण के लिए कोई 6 फीट 3 इंच का है, तो कद-काठी के अनुपात को देखते हुए उसे शुरुआत में ही रिजेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि परंपरागत रूप से लक्ष्मण को कद में राम से छोटा दिखाया जाता है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि रणबीर कपूर ने मुझे उस रोल से निकलवाया या मेरे साथ किसी तरह का नेपोटिज्म हुआ।'

पहले लगा रामायण मेरी किस्मत में नहीं

उन्होंने आगे कहा, 'ऐसा कुछ नहीं था। कलाकारों के चयन के अपने मापदंड होते हैं और फैसला उन्हीं के आधार पर लिया जाता है। दो बार रिजेक्ट होने के बाद मुझे लगा कि शायद 'रामायण' मेरे नसीब में नहीं है और मैंने तय कर लिया कि अब यह नहीं करना। लेकिन फिर निर्देशक अभिषेक का फोन आया। मुझे लगा कि वह फिर लक्ष्मण के लिए बुला रहे हैं, तो मैंने साफ कह दिया कि अब मैं यह किरदार नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा, 'मैं आपको लक्ष्मण के लिए नहीं, राम जी के लिए बुला रहा हूं।' उस पल लगा कि हम इंसान भगवान से छोटी-छोटी चीजें मांगते हैं, जबकि हमारी किस्मत में शायद उससे कहीं बड़ी चीज लिखी होती है। जिस किरदार के लिए मैं दो बार रिजेक्ट हुआ, आखिरकार उसी 'रामायण' में मुझे श्रीराम बनने का मौका मिला।'

कृष 3 में असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहा

अभिनय की दुनिया में आने से पहले देव शर्मा राकेश रोशन के साथ 'कृष 3' में असिस्टेंट के तौर पर काम कर चुके हैं। वे बताते हैं, 'जब मैं असिस्टेंट के रूप में जुड़ा, तो विशाखापट्टनम से ग्रेजुएशन करने और तेलुगू अच्छी होने का मुझे काफी फायदा मिला।

फिल्म की शूटिंग साउथ के रामोजी राव स्टूडियो में हो रही थी और क्राउड मैनेजमेंट से लेकर लोकल लोगों से कम्यूनिकेट करने तक मेरी भाषा की जानकारी बहुत काम आई। राकेश सर इस बात से काफी इम्प्रेस थे कि हमारा कम्यूनिकेशन इतनी आसानी से हो जाता था। मेरे लिए यह किसी सुपरपावर से कम नहीं था। राकेश सर की सबसे खास बात उनकी विनम्रता और जमीन से जुड़ा होना था। उनके सेट पर आर्टिस्ट और क्रू के बीच कोई फर्क नहीं किया जाता था।

अपने भीतर के राम को जगाने की जरूरत है

राम को लेकर की जाने वाली राजनीति पर वे कहते हैं, 'देखिए, जो लोग राम या रामायण जैसे विषयों का इस्तेमाल सिर्फ राजनीति के लिए कर रहे हैं, उनका भला नहीं होने वाला। किसी भी विषय को किस तरह लिखा जा रहा है, उसका कंटेंट क्या है, उसे बनाने वाले की नीयत क्या है और वे कहना क्या चाहते हैं, यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। बचपन से हम अपने माता-पिता से संस्कार और सभ्यता सीखते हैं। हमारी संस्कृति, धरोहर और इतिहास हमें बेहतर इंसान बनने की सीख देते हैं। श्रीराम का चरित्र भी इन्हीं मूल्यों की मिसाल है, चाहे नारी सम्मान हो, त्याग हो, भाईचारा हो या जिम्मेदारी को समझकर उसे निभाना। ऐसी फिल्मों के जरिए हमें इन्हीं मूल्यों की बात करनी चाहिए। राम हर मन में बसते हैं, लेकिन रावण भी हर मन में मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारी परवरिश, संस्कार और कर्म तय करते हैं कि हम अपने भीतर के राम को मजबूत करते हैं या रावण को हावी होने देते हैं। हमें अपने राम को बाहर खोजने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने भीतर के राम को जगाने की जरूरत है।'



ब्रेकअप के बाद जिंदगी बदल गई है

अभिनेत्री उदिति सिंह इस समय रियलिटी शो 'बिग बॉस-20' में नजर आ रही हैं। शो के दौरान उदिति ने अपने एक्स-बॉयफ्रेंड और अभिनेता करण वाही के साथ रिलेशनशिप को लेकर खुलकर बात की। उदिति ने बताया कि कैसे 'कोविड-19' लॉकडाउन के दौरान उनका रिश्ता खराब होने लगा था। साथी कंटेस्टेंट स्काउट से बात करते हुए उदिति ने कहा कि अलग होने के बाद उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पूरी तरह बदल गई। उदिति ने कहा, 'ब्रेकअप के बाद मेरे लिए यह एक तरह से वरदान साबित हुआ। क्योंकि उसके बाद मेरा पूरा करियर, मेरी पूरी लाइफ, सब कुछ बदल गया था।' उन्होंने आगे बताया कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने और उनके एक्स-पार्टनर ने एक गोल्डन रिट्रीवर डॉग को अडॉप्ट किया था, जिसका नाम 'नोआ' है। उदिति सिंह ने कहा, 'हमने लॉकडाउन में साथ में नोआ नाम का गोल्डन रिट्रीवर लिया था, तो उसी को लेकर हमारे बीच काफी झगड़े शुरू हो गए थे। उस वक्त कोविड भी था, तो हम दोनों पर सफाई का काफी काम रहता था। मेरा सफाई करने का तरीका अलग था और उसका अलग। फिर वह इस बात को लेकर थोड़ा डॉमिनेट भी करता था और कहता था, 'तुम्हें नहीं आता।' क्योंकि वह उम्र को लेकर बहुत ज्यादा सोचता था, उसके लिए हर चीज ऐसी थी कि 'तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम्हें ये-वो नहीं आता।', 'तुम नोआ को नहीं संभाल पाओगी।' तो मुझे लगता था कि मेरा पार्टनर बहुत डीमोटिवेट करने वाला है।' उदिति ने आगे कहा, 'ऐसा ही होता है, जब दो लोगों का एक होना नहीं लिखा होता है, तो बात-बात पर लड़ाई होती है और जब एक होना लिखा होता है, तब सब कुछ अच्छा होता है।' उदिति का यह बयान 'बिग बॉस 20' के घर में करण के साथ अपने रिश्ते को लेकर पहले की गई बातों के बाद आया है। दोनों के रिश्ते के बारे में साल 2019-20 के आसपास सभी को पता था, उस वक्त करण ने उदिति के साथ तस्वीरें भी शेयर की थीं। बताया जाता है कि उनका रिश्ता काफी सीरियस था। उदिति ने पहले घरवालों को बताया था कि दोनों करीब ढाई साल तक साथ रहे थे और शादी तक की बात भी हुई थी।



बिग बॉस से बाहर आते ही छलका ईशा रिखी का दर्द

सलमान खान होस्टेड रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में आए दिन कुछ न कुछ नया और धमाकेदार देखने को मिल रहा है। इसमें कुल 16 कंटेस्टेंट्स ने हिस्सा लिया, जिसमें से दो प्रतियोगी रोहैद खान और ईशा रिखी अभी तक बाहर हो गए हैं। तीन हफ्ते घर में रहने के बाद अब बादशाह की एक्स वाइफ ने शो से बाहर आते ही सोशल मीडिया पर एक लंबा-चौड़ा नोट शेयर किया है। ईशा ने इंस्टाग्राम पर शेयर किए पोस्ट में लिखा, 'बिग बॉस के घर के अंदर बिताए तीन हफ्ते... तीन हफ्ते जिनमें मैंने बहुत सारी भावनाएं, अनुभव, चुनौतियां, हंसी, आंसू और ऐसी यादें जी हैं, जिन्हें मैं हमेशा अपने साथ रखूंगी। वापस आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि आपका प्यार और सपोर्ट मेरे लिए कितना मायने रखता है।' ईशा ने पोस्ट में आगे लिखा, 'उन सभी लोगों का दिल से शुक्रिया, जो मेरे साथ खड़े रहे, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, मुझे चीयर किया। उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। मैं हर राय, हर मैसेज और इस सफर का किसी भी तरह हिस्सा रहे हर एक इंसान के लिए आभारी हूं।' ईशा ने आगे बताया, 'पिछले कुछ हफ्ते मेरे लिए आसान नहीं थे। मेरे कुछ इमोशनल ब्रेकडाउन हुए, कुछ ऐसे पल आए जब मैं अपनी बात ठीक से नहीं कह पाई और कुछ मौकों पर शायद मैं वैसा नहीं दिख पाई, जैसा मैं खुद को दिखाना चाहती थी। मुझे पता है कि शायद मैंने आपमें से कुछ लोगों को निराश किया होगा और अगर ऐसा हुआ है तो मुझे सच में अफसोस है। मैं अभी भी इन सब चीजों को समझ रही हूं, खुद को बेहतर तरीके से जानने की कोशिश कर रही हूं और इस पूरे अनुभव से सीख रही हूं।'

ईशा ने क्यों कहा शुक्रिया

अपनी बात खत्म करते हुए ईशा ने लास्ट में लिखा, 'लेकिन एक बात जो मैं आप सभी को बताना चाहती हूं, वह यह है कि मैंने आपका प्यार महसूस किया। भले ही मैं खुद ज्यादा कुछ जाहिर नहीं कर पाई, लेकिन यह बात मेरे लिए शब्दों में बयां करने से कहीं ज्यादा मायने रखती है। मेरे साथ खड़े रहने, मुझे समझने और लगातार मेरा सपोर्ट करने के लिए आपका शुक्रिया। मैं सच में, बहुत-बहुत आभारी हूं।'

कौन हैं ईशा रिखी

ईशा रिखी पंजाबी अभिनेत्री हैं। उन्होंने साल 2013 में आई फिल्म 'जट्ट बॉयज पुत्त जट्टा दे' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। इसके बाद वह 'हैप्पी गो लकी', 'अरदास' और 'मिंडो तसीलदारनी' जैसी कई फिल्मों में दिखाई दीं। इस साल की शुरुआत में ईशा रैपर-सिंगर बादशाह से शादी करने को लेकर सुर्खियों में आई थीं। हालांकि, दोनों का रिश्ता पांच महीने ही चला और दोनों ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए अपने अलग होने का ऐलान भी कर दिया। इसके बाद ईशा ने 'बिग बॉस 20' में हिस्सा लिया था और अब वह वहां से भी बाहर हो गई हैं।



इश्वाक सिंह ने वाणी के साथ काम करने का अनुभव किया साझा

इन दिनों अपनी फिल्म 'गांधारी' को लेकर चर्चा में चल रहे इश्वाक सिंह ने 'पाताल लोक', 'रॉकेट बॉयज' और 'बर्लिन' जैसे प्रोजेक्ट्स में गंभीर और दमदार किरदार निभाए हैं। लेकिन अब अभिनेता एक अलग अंदाज में नजर आने वाले हैं। वह वाणी कपूर के साथ फिल्म 'सर्वगुण संपन्न' में रोमांटिक किरदार निभाते दिखेंगे। दोनों की यह पहली ऑनस्क्रीन जोड़ी होगी। फिल्म में काम करने के अनुभव को लेकर इश्वाक ने बताया, 'शूटिंग का अनुभव बहुत अच्छा रहा। यह एक बेहतरीन टीम थी, को-एक्टर बहुत अच्छे थे और डायरेक्टर सोनाली भी बहुत प्यारी हैं। उनके साथ काम करने में बहुत अच्छा समय बीता।' बता दें कि फिल्म की शूटिंग 2023 में पूरी हो गई थी, लेकिन रिलीज लंबे समय से टली हुई थी। इस बारे में पूछने पर अभिनेता ने कहा, 'देखिए, फिल्म कब रिलीज होगी, फिलहाल मेरे पास इससे ज्यादा जानकारी नहीं है। अब जब टीजर भी अनाउंस हो चुका है, मुझे पूरा यकीन है कि यह जल्द रिलीज होगी।' वाणी कपूर के साथ काम करने के अनुभव पर उन्होंने कहा, 'वाकई में, फिलहाल मुझे इस फिल्म के बारे में बोलने की इजाजत नहीं। पर हां, उनके साथ काम करने में काफी अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को हमारी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री पसंद आएगी।'

लस्ट स्टोरीज 3 में सायरा बनकर छाईं अदिति राव हैदरी

अदिति राव हैदरी इन दिनों हाल ही में रिलीज हुई 'लस्ट स्टोरीज 3' को मिल रहे प्यार और सराहना का आनंद ले रही हैं। फिल्म में अभिनेत्री ने अपने समय से काफी आगे का किरदार निभाया है। सायरा के किरदार में अदिति न सिर्फ वासना, चाहत और महिला सुख की भावनाओं को बखूबी पर्दे पर उतारती हैं, बल्कि पिता और बेटी के रिश्ते की खूबसूरती को भी भावनात्मक रूप से दर्शाती हैं। अभिनेत्री ने अपने वास्तविक जीवन की एक याद को साझा करते हुए बताया कि गजराज राव के साथ इस रिश्ते को पर्दे पर निभाना उनके लिए बेहद निजी और भावुक अनुभव था। फिल्म में गजराज राव उनके ऑन-स्क्रीन ससुर के किरदार में नजर आते हैं। अदिति बताती हैं, जो कुछ कागज पर लिखा गया था, वह बहुत खूबसूरत था। लेकिन जाहिर तौर पर जब निर्देशक अपनी समझ और नजरिए को उसमें जोड़ते हैं और आपके सामने गजराज राव जैसे अभिनेता होते हैं, तो मेरे लिए यह रिश्ता बहुत ही कोमल और भावुक बन गया। कहानी में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, वह उस परिवार की प्रगतिशील सोच थी, जहां ससुर इस लड़की के साथ खड़े होते हैं और उसके सहयोगी बनते हैं। उन्होंने कहा, क्योंकि हर कोई कहता है, 'ये तो हमारे घर की बच्ची है, ये तो हमारी बेटी है।' लेकिन 1987 के दौर में एक लड़की का अपने ससुर में एक ऐसे व्यक्ति को पाना, जिसके साथ वह अपने मन की बात साझा कर सके, मुझे लगता है कि यह वाकई बहुत खूबसूरत है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं, कल ही यह बात मेरे मन में आई कि यह लगभग एक आदर्श प्रेम कहानी जैसी है, जहां इच्छाएं अधूरी हैं, लेकिन वे सभी बहुत सारे प्यार के साथ अधूरी हैं। वह आगे कहती हैं, एक लड़की का अपनी कला के जरिए अपना साहस तलाश पाना, मुझे यह भी बेहद अद्भुत लगता है। पति और ससुर, दोनों का इस सफर में उसका साथ देना बहुत खूबसूरत है, चाहे वह नृत्य हो, संगीत हो, लेखन हो, कविता हो या साहित्य। लड़कियों के लिए और हम सभी के लिए यही हमारी आवाज है। यह हमें अपने होने का एक ऐसा एहसास देता है, जो पूरी तरह हमारा है। अदिति ने कहा, मुझे जिंदगी में यह बात हमेशा बहुत खूबसूरत लगती है। इसलिए मुझे वह सीन बहुत पसंद आया, क्योंकि उसमें बहुत कोमलता थी। मेरे पिता का निधन उस समय हुआ जब उन्हें अभी और जीना चाहिए था। वह बीमार थे। इसलिए मेरे लिए माता-पिता और बच्चे के बीच का कोई भी सीन बहुत... बहुत ज्यादा मायने रखता है। वह मेरे लिए बेहद भावुक था। वह बहुत खूबसूरत था।



नीरज के पक्ष में प्रचार से अनंत का साफ इनकार, बोले- पिछले चुनाव में मेरे खिलाफ अभियान चला तो पार्टी ने कार्रवाई क्यों नहीं की; सीएम आवास पर भी हुई बैठक

जदयू में अनंत सिंह की बगावत से बढ़ा घमासान, सुलह के लिए ललन सिंह ने संभाला मोर्चा

महानगर मेट्रो ब्यूरो

पटना। पटना स्नातक सीट से जदयू उम्मीदवार नीरज कुमार के समर्थन को लेकर विधायक अनंत सिंह के अलग रुख ने पार्टी के भीतर चल रहे विवाद को और चर्चा में ला दिया है। अनंत सिंह ने साफ कर दिया है कि वह नीरज कुमार के पक्ष में प्रचार नहीं करेंगे। पार्टी नेतृत्व ने मामले को शांत करने और अनंत सिंह को समझाने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को दी। ललन सिंह ने अनंत सिंह से बातचीत की और उनकी शिकायतें सुनीं। बातचीत के बाद उन्होंने दावा किया कि अनंत सिंह अब पार्टी के फैसले को लेकर खुले तौर पर बयान नहीं देंगे। ललन सिंह ने बताया कि अनंत सिंह की मुख्य शिकायत पिछले विधानसभा चुनाव से जुड़ी है। उनका कहना है कि जब वह चुनाव लड़ रहे थे, तब उनके खिलाफ अभियान चलाया गया और नीरज कुमार ने उनका विरोध किया। अनंत सिंह का आरोप है कि इसके बावजूद पार्टी की ओर से उस समय कोई कार्रवाई नहीं की गई। ललन सिंह ने भी माना कि उस समय प्रदेश इकाई की ओर से कार्रवाई नहीं करना चूक थी। उन्होंने कहा कि जब कोई क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया भी होती है और ताली दोनों हाथों से बजती है। अनंत सिंह ने ललन सिंह के सामने यह भी सवाल उठाया कि जब पार्टी की ओर से एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें वह और उनके खिलाफ प्रचार करने वाले लोग शामिल हुए थे, तब उन्होंने अपनी शिकायतें रखीं, लेकिन उनके सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं मिला। अनंत का कहना है कि यदि पार्टी में अनुशासन की व्यवस्था है तो वह सभी नेताओं के लिए समान होनी चाहिए। लन सिंह के बयान के बाद जदयू के वरिष्ठ नेता संजय झा ने कहा कि उन्होंने पार्टी के हित में काम किया है। वहीं मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि ललन सिंह के संज्ञान में जो बातें आईं, उन्होंने उन्हें पार्टी के सामने रखा और मामले को सुलझाने का प्रयास किया। चौधरी ने कहा कि पार्टी को लग रहा है कि ललन सिंह की कोशिश के बाद विवाद खत्म होने की ओर है। उन्होंने कहा कि ललन सिंह ने मामले के समाधान का रास्ता बताया है और पार्टी पूरे घटनाक्रम को देख रही है। मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने भी विवाद को लेकर कहा कि ललन बाबू ने आश्वासन दिया है कि सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी के बड़ी संख्या में विधायकों में से केवल एक विधायक के अलग रुख की बात सामने आई है और उन्हें उम्मीद है कि वह वापस आ जाएंगे। उन्होंने नीरज कुमार के नहीं हारने की बात भी कही। ववाद के बीच देर शाम मुख्यमंत्री आवास पर जदयू नेताओं की बैठक हुई। इसमें संजय झा, मंत्री विजय कुमार चौधरी और अशोक चौधरी शामिल हुए। बैठक में पार्टी के भीतर अनुशासन बनाए रखने और अनंत सिंह-नीरज कुमार विवाद को सुलझाने पर चर्चा हुई। इससे पहले 5 अक्टूबर की सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित ललन सिंह के आवास पर उनसे मुलाकात की थी। दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक



बंद कमरे में बातचीत हुई थी इसके बाद दिल्ली रवाना होने से पहले ललन सिंह ने पटना एयरपोर्ट पर अनंत सिंह से हुई बातचीत के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अनंत सिंह ने कहा है कि जब नीतीश सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था, तब वह राजद में रहते हुए भी नीतीश सरकार के समर्थन में थे। उनकी पत्नी ने भी सरकार का समर्थन किया था। ललन सिंह के अनुसार, अनंत ने समर्थन के पीछे नीतीश कुमार के प्रति सम्मान को वजह बताया।

RE-2 सड़क का अधूरा हिस्सा पूरा कराने पहुंची टीम, विरोध के बाद पथराव

महानगर मेट्रो ब्यूरो

इंदौर। बंगाली चौराहा से पीपल्याहाना के बीच RE-2 सड़क के करीब एक किलोमीटर लंबे अधूरे हिस्से का काम पूरा कराने के लिए मंगलवार सुबह नगर निगम और प्रशासन ने बाधक निर्माण हटाने की कार्रवाई शुरू की। सुबह करीब 11 बजे निगम और प्रशासन की टीम जेसीबी, पोकलेन और पुलिस बल के साथ बिचौली कांकड़, शिव नगर और शिव दर्शन नगर पहुंची। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और रिमूवल टीम तथा पुलिस पर पथराव शुरू हो गया। इससे मौके पर अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। पुलिस ने प्लास्टिक पाइप से लोगों को खदेड़कर स्थिति नियंत्रित की। पथराव में दो लोगों को चोटें आईं, जिन्हें अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है। एसडीएम घनश्याम धनगर के अनुसार RE-2 सड़क की कुल लंबाई 4.25 किलोमीटर और चौड़ाई 45 मीटर है। इसमें से 3.20 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि करीब एक किलोमीटर हिस्सा पिछले तीन साल से अधूरा पड़ा है। इस प्रोजेक्ट पर अब तक करीब 55 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। सड़क के रास्ते में कुल सात बस्तियां बाधक हैं, पिपलियाहाना-बिचौली कांकड़ क्षेत्र में 325 परिवारों का पहले ही व्यवस्थापन किया जा चुका है। इनमें 303 परिवार आवासीय प्रकोष्ठों में रह रहे हैं। कोर्ट के स्थगन आदेश के कारण 22 मकानों को पहले नहीं हटाया गया था।



फॉर्म-6 में बदलाव के आरोपों पर भाजपा का जवाब, संबित पात्रा बोले- चुनाव आयोग ने नहीं बदला फॉर्म

हानगर मेट्रो ब्यूरो

नई दिल्ली। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्ट्रक्र को लेकर फॉर्म-6 में कथित बदलाव का मुद्दा मंगलवार को भाजपा और राहुल गांधी के बीच विवाद का केंद्र बना रहा। राहुल गांधी की ओर से लगाए गए आरोपों पर भाजपा ने जवाब देते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने फॉर्म-6 में कोई बदलाव नहीं किया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि SIR की प्रक्रिया के लिए फॉर्म-6 के साथ एक अतिरिक्त घोषणापत्र जोड़ा गया था। उन्होंने कहा कि इसे फॉर्म-6 में बदलाव के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। संबित पात्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई को बिहार में स्ट्रक्र को बरकरार रखा था। उनके मुताबिक, अदालत ने स्ट्रक्र के लिए अतिरिक्त दस्तावेजी प्रक्रिया की जरूरत को भी स्वीकार किया था। वहीं 5 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने फॉर्म-6 के किसी संशोधित संस्करण को मंजूरी नहीं दी थी। इसके बाद अदालत ने चुनाव आयोग से इस संबंध में जानकारी और रिकॉर्ड मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए सवाल किया कि यदि फॉर्म में बदलाव किया गया है तो उसे किसने और किस अधिकार के तहत किया। था।



अरबाज-शूरा की बेटी सिपारा का पहला जन्मदिन, सलमान-सलीम समेत पूरा खान परिवार पहुंचा

महानगर मेट्रो ब्यूरो।

मुंबई। अभिनेता और फिल्म निर्माता अरबाज खान और शूरा खान की बेटी सिपारा खान का सोमवार को पहला जन्मदिन मनाया गया। मुंबई स्थित अरबाज खान के घर पर आयोजित जन्मदिन समारोह में खान परिवार के कई सदस्य शामिल हुए। पार्टी में सलीम खान, सलमान खान, सोहेल खान सहित परिवार के अन्य सदस्य पहुंचे और बेटी के पहले जन्मदिन के जश्न में शामिल हुए। सामने आए वीडियो में सलीम खान कार से अरबाज के घर पहुंचते दिखाई दिए। उनके साथ उनकी पत्नी सलमा खान भी थीं। बाद में सलीम खान को सोहेल खान के साथ घर से बाहर निकलते देखा गया। सोहेल उन्हें कार तक पहुंचने में मदद करते नजर आए। इस दौरान अभिनेत्री हेलेन भी उनके साथ दिखाई दीं। सलीम खान की सार्वजनिक मौजूदगी ने भी लोगों का ध्यान खींचा। इस साल की शुरुआत में उनके ब्रेन हैमरेज के बाद करीब एक महीने तक अस्पताल में रहने की खबर सामने आई थी। अस्पताल से छुट्टी के बाद मार्च 2026 में ईद के मौके पर वे पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए थे। इसके बाद कई महीनों बाद उन्हें इस पारिवारिक समारोह में देखा गया। सलमान खान भी पहुंचे सिपारा के जन्मदिन समारोह में सलमान खान भी पहुंचे।



शंकर महादेवन बोले- संगीत सिर्फ सुर-ताल नहीं, दिल तक पहुंचने वाला एहसास भी जरूरी

महानगर मेट्रो ब्यूरो

मुंबई। सा रे गा मा पा का नया सीजन 19 सितंबर 2026 से जी टीवी पर शुरू हो चुका है। इस सीजन में देशभर से आए गायक अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। शो के जज और संगीतकार शंकर महादेवन ने इस बार के सीजन की भव्यता, नए कलाकारों की प्रतिभा और संगीत की ताकत को लेकर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि किसी कलाकार की पहचान केवल सुर, ताल और तकनीकी दक्षता से नहीं होती, बल्कि उसकी आवाज में मौजूद वह खास एहसास भी महत्वपूर्ण होता है, जो सीधे श्रोताओं के दिल तक पहुंचता है। शंकर महादेवन के मुताबिक इस बार शो को पहले से कहीं बड़े स्तर पर तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि शो में करीब 100 म्यूजिशियन और लगभग 100 कोरस सिंगर्स शामिल हैं। इसके अलावा देश के अलग-अलग राज्यों से लोक कलाकार और स्थानीय डांसर्स भी कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। ओडिशा, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम सहित विभिन्न राज्यों के कलाकार अपनी-अपनी संस्कृति की झलक प्रस्तुत कर रहे हैं। उनके अनुसार संगीत और संस्कृति के इस मेल ने शो को और समृद्ध बनाया है। उन्होंने कहा कि सा रे गा मा पा करीब 31 साल पुराना और मूल गायन रियलिटी शो है। किसी प्रस्तुति को केवल भव्य सजावट और बड़े मंच से प्रभावशाली नहीं बनाया जा सकता। उसके भीतर आत्मा और जीवन होना जरूरी है और इस शो का जीवन उसका संगीत है। शंकर ने कहा कि इस बार संगीत के साथ जो दृश्य और ध्वनि अनुभव जोड़ा गया है, वह दर्शकों के लिए नया अनुभव लेकर आया है। शंकर ने बताया कि उन्होंने अपने दोनों बेटों सिद्धार्थ और शिवम को भी शो का पहला एपिसोड बिना पहले से बताए दिखाया। दोनों संगीत से जुड़े हैं, संगीत रचना करते हैं और प्रस्तुति भी देते हैं। शो का स्तर देखकर वे भी हैरान रह गए। नए कलाकारों को लेकर शंकर ने कहा कि वह किसी गायक में केवल सुर या रियाज नहीं देखते, बल्कि उसके पूरे व्यक्तित्व और आवाज के प्रभाव को महसूस करते हैं। उनके मुताबिक हर कलाकार का अपना एक 'ऑरा' होता है। कई बार कोई कलाकार केवल कुछ पंक्तियां गाता है और लोग उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। यही वह खासियत है, जिसे केवल तकनीकी पैमाने पर नहीं मापा जा सकता।



आधी रात संजय यदुवंशी के घर पहुंची पुलिस, दीवार फांदकर अंदर घुसी; परिवार से तीखी बहस



महानगर मेट्रो ब्यूरो

सुल्तानपुर। अवधी गायक और कॉमेडियन संजय यदुवंशी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस सोमवार देर रात उनके घर पहुंची। धम्मौर थाना क्षेत्र के उघड़पुर गांव स्थित घर के गेट पर ताला लगा होने के बाद पुलिसकर्मी दीवार फांदकर अंदर दाखिल हुए। हालांकि, संजय घर पर नहीं मिले। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान उनके पिता, मां और भाई की पुलिसकर्मियों से तीखी बहस हो गई। घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में धम्मौर थाना प्रभारी विपेंद्र कुमार वर्मा संजय को तलाशते नजर आ रहे हैं। वीडियो में वह कहते सुनाई दे रहे हैं कि उन्हें संजय चाहिए और वह तुरंत चाहिए। इस पर संजय की मां ने कहा कि संजय घर पर नहीं है और रात में किसी के घर में घुसने का अधिकार नहीं है। इस पर इंस्पेक्टर ने नाराजगी जताते हुए कहा कि एक इंस्पेक्टर की पावर समझ में नहीं आती और वह उन्हें उनका अधिकार बताएंगे। परिवार ने पुलिसकर्मियों पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। संजय यदुवंशी ने भी पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पूछा कि पुलिस उन्हें किस मामले में गिरफ्तार करना चाहती है और उनकी गिरफ्तारी का वारंट कहां है। हालांकि, पुलिस अधिकारियों ने परिवार और संजय के आरोपों को खारिज किया है। सीओ रितिक कपूर के अनुसार, थाना कोतवाली नगर में जफरुल हसन ने अपने बेटे शबीब रजा के साथ मारपीट और जानलेवा हमले का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में संजय यदुवंशी आरोपी हैं और फरार चल रहे हैं। पुलिस इसी मामले की जांच के तहत उनकी तलाश कर रही थी। सोमवार देर रात पुलिस टीम ने संजय के घर दबिश दी, लेकिन वह वहां नहीं मिले। संजय के पिता सियाराम यादव का आरोप है कि धम्मौर थाना प्रभारी छह से अधिक पुलिसकर्मियों के साथ रात में घर पहुंचे थे। घर का दरवाजा बंद होने पर पुलिसकर्मी गेट कूदकर अंदर आए। आवाज सुनकर परिवार के सदस्यों की नींद खुल गई। पुलिसकर्मियों को रोकने की कोशिश करने पर बहस शुरू हो गई। सियाराम यादव का दावा है कि इस दौरान इंस्पेक्टर ने संजय और उनके दूसरे बेटे शिवा के बारे में पूछा और उनके साथ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यदि उनके बच्चों को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस की होगी।

SHO को निलंबित करने की मांग

संजय यदुवंशी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि धम्मौर थाने के एसएचओ रात करीब 12 बजे उनके घर पहुंचे और परिवार के साथ गाली-गलौज की। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर उनके खिलाफ ऐसा कौन सा मुकदमा है। संजय ने चेतावनी दी कि यदि एसएचओ को निलंबित नहीं किया गया तो वह लखनऊ में धरना देंगे।

वीडियो में पुलिस और परिवार के बीच तीखी बहस

संजय यदुवंशी के घर पुलिस दबिश का वीडियो सामने आया है। इसमें पुलिस अधिकारी संजय को तुरंत बुलाने की बात कहते नजर आ रहे हैं। संजय की मां ने रात में घर में घुसने पर आपत्ति जताई, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। परिवार ने पुलिस पर अभद्रता के आरोप लगाए हैं, जबकि सीओ का कहना है कि पुलिस जानलेवा हमले के मामले में आरोपी की तलाश में दबिश देने पहुंची थी।

भारत की अर्थव्यवस्था को वर्ल्ड बैंक का बड़ा भरोसा, FY27 की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 7.1% किया

महानगर मेट्रो ब्यूरो

नई दिल्ली। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर 7.1 प्रतिशत कर दिया है। इससे पहले अप्रैल में जारी अनुमान में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर 6.6 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था। मंगलवार, 6 अक्टूबर को जारी 'इंडिया डेवलपमेंट अपडेट' में वर्ल्ड बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था के मजबूत प्रदर्शन को रेखांकित करते हुए विकास दर के अनुमान में 0.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक व्यापार में चुनौतियों और दुनिया में जारी तनाव के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के दौरान भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रही। वर्ल्ड बैंक के अनुसार निवेश और घरेलू खपत भारत की आर्थिक वृद्धि के प्रमुख आधार बने हुए हैं। वर्ल्ड बैंक ने बताया कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मांग मजबूत रहने से अर्थव्यवस्था को गति मिली है। अच्छी कृषि स्थिति, किसानों को मिलने वाली सरकारी प्रत्यक्ष सहायता और सब्सिडी से ग्रामीण मांग को मजबूती मिली। वहीं कर राहत और जीएसटी में कटौती के बाद शहरी क्षेत्रों में भी उपभोक्ता खर्च बढ़ा है। घरेलू खपत में आई मजबूती को आर्थिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। वैश्विक स्तर पर प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भारत के निर्यात ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है।



स्पेलिंग से लेकर सरनेम और पूरा नाम बदलने तक अलग-अलग दस्तावेज जरूरी

महानगर मेट्रो ब्यूरो

नई दिल्ली। आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग सुधारने, शादी के बाद सरनेम बदलने या पूरा नाम बदलने वालों के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। आधार जारी करने वाली संस्था यूआईडीएआई ने नाम में सुधार और बदलाव से जुड़ी प्रक्रिया को अलग-अलग श्रेणियों में बांट दिया है। अब हर तरह के नाम परिवर्तन के लिए निर्धारित दस्तावेज और प्रक्रिया का पालन करना होगा। एक ही दस्तावेज के आधार पर हर प्रकार का नाम बदलाव नहीं किया जा सकेगा। यूआईडीएआई की नई व्यवस्था में नाम में मामूली सुधार से लेकर बड़े बदलाव तक के लिए अलग नियम तय किए गए हैं। इसका उद्देश्य आधार रिकॉर्ड में गलतियों और संभावित धोखाधड़ी को रोकना तथा नाम में किए जाने वाले बदलाव की सही तरीके से जांच करना है। नाम में छोटी-मोटी स्पेलिंग की गलती सुधारने, मिडिल या लास्ट नेम जोड़ने अथवा हटाने और नाम का क्रम बदलने जैसे बदलाव को 'माइनर नेम चेंज' माना जाएगा। उदाहरण के तौर पर ऋद्ध को ऋद्धद्बद्ध करना इसी श्रेणी में आएगा। इसके लिए एक मान्य पहचान पत्र देना होगा। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के मामले में परिवार के मुखिया के आधार पर संबंध का प्रमाण भी मान्य रहेगा। यदि आवेदक के मूल दस्तावेज सही थे, लेकिन आधार में डेटा एंट्री के दौरान ऑपरेटर की गलती से नाम गलत दर्ज हो गया, तो इसे अलग श्रेणी में रखा गया है। ऐसे मामलों में वयस्कों के लिए Anne&ure B और बच्चों के लिए Anne&ure C के साथ पहचान या संबंध का प्रमाण देना होगा। बदला जाने वाला नाम पहले जमा किए गए दस्तावेजों से मेल खाना चाहिए। दस्तावेजों में अंतर होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। शादी या तलाक के बाद सरनेम बदलने के लिए पहचान पत्र के साथ Anne&ure D का एफिडेविट देना होगा। इसमें स्पष्ट करना होगा कि नाम में बदलाव शादी या तलाक के कारण किया जा रहा है।



अखिलेश की हिरासत के बाद यूपी में सपा का प्रदर्शन, लखनऊ-आगरा समेत कई जिलों में पुलिस से झड़प

महानगर मेट्रो ब्यूरो

लखनऊ। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को लेकर दिल्ली में विपक्षी नेताओं के 'सेव डेमोक्रेसी' मार्च को पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया गया। दिल्ली की घटना के विरोध में मंगलवार को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने अखिलेश यादव की रिहाई और चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों पर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। गोरखपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए 'वोट चोर इस्तीफा दो' के नारे लगाए। कई स्थानों पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति बनी रही। लखनऊ में भी सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने सड़क से हटाने की कोशिश की। सपा की ओर से पुलिस कार्रवाई का विरोध किया गया। वहीं आगरा में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और सपाइयों के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति बनी। प्रदर्शनकारी मुख्य



चुनाव आयुक्त का पुतला लेकर पहुंचे थे, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी द्वारा एक सपा कार्यकर्ता को टांग अड़ाकर गिराने और उसके साथ मारपीट किए जाने का दावा भी सामने आया है। सीतापुर के सिधौली में मंगलवार दोपहर करीब ढाई बजे सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता कोतवाली परिसर में धरने पर बैठ गए और अखिलेश यादव की रिहाई की मांग की। धरने में शामिल सपा नेता रमेश कुमार यादव ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दे को लेकर ज्ञापन देने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन विपक्षी नेताओं और सांसदों को हिरासत में ले लिया गया। बहराइच में भी अखिलेश की हिरासत की सूचना के बाद सपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा गया। दोपहर करीब तीन बजे जिलाध्यक्ष रामहर्ष यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के बाहर एकत्र हुए और प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार और पुलिस के खिलाफ नारे लगाए तथा अखिलेश यादव की रिहाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ता सड़क पर लेट गए, जिससे रास्ता बाधित हुआ और जाम की स्थिति बन गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने का प्रयास किया तो दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की हुई। इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष रामहर्ष यादव और पुलिस के बीच भी झड़प की बात सामने आई। महिला कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों के बीच भी धक्का-मुक्की होने की सूचना है। दिल्ली में विपक्षी दलों का मार्च मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर आयोजित किया गया था। पुलिस ने मार्च को चुनाव आयोग कार्यालय की ओर बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद विपक्षी नेताओं ने धरना दिया और कई नेताओं को हिरासत में लिया गया।

रामवास के पास टायर फटने के बाद बस हुई अनबैलेंस, आग ने कुछ ही मिनटों में पूरी बस को चपेट में लिया; डेढ़ घंटे में बुझी आग

महानगर मेट्रो ब्यूरो

उज्जैन। उज्जैन से करीब 15 किलोमीटर दूर रामवास क्षेत्र में मंगलवार दोपहर उज्जैन से इंदौर जा रही एक बस में अचानक आग लग गई। घटना दोपहर करीब 12:15 बजे हुई। बस में उस समय करीब 12 यात्री सवार थे। बस से अचानक धुआं उठता देखकर यात्रियों में घबराहट फैल गई। आग बढ़ने से पहले ही सभी यात्री बस से कूदकर बाहर निकल आए। इसके कुछ ही मिनट बाद आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में किसी यात्री के हताहत होने की जानकारी नहीं है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रामवास क्षेत्र में चलते समय बस का टायर फट गया था। इससे बस अनबैलेंस हो गई और इसी दौरान उसमें आग लग गई। घटना की सूचना मिलने के करीब 45 मिनट बाद चार दमकल वाहन मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तब तक बस पूरी तरह जल चुकी थी और मौके पर केवल उसका चेचिस बचा था। पुलिस और संबंधित विभाग घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं। जलकर खाक हुई बस की पहचान को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के बयानों में अंतर सामने आया है। बस पुरानी डीजल इंजन वाली बताई जा रही है। उस पर भगवा रंग का रेडियम लगा था और कांच पर 'मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा' लिखा हुआ था। सामने आए वीडियो में भी बस के आगे 'मुख्यमंत्री सुगम बस सेवा परिवहन' लिखा दिखाई दे रहा है। उज्जैन कलेक्टर रोशन सिंह ने इसे किसी निजी ऑपरेटर की बस बताया है। वहीं, उज्जैन ऋद्धह संतोष मालवीय के अनुसार जलने वाली बस सूत्र सेवा की गाड़ी थी। ऋद्धह ने बताया कि यह बस हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कार्यक्रम के लिए भोपाल भी गई थी। बस की वास्तविक पहचान को लेकर संबंधित विभाग से जानकारी जुटाई जा रही है। 25 सितंबर को हुआ था मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का शुभारंभ मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का प्रदेश स्तर पर शुभारंभ 25 सितंबर 2026 को भोपाल के बीएचईएल दशहरा मैदान में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया था। इस दौरान प्रदेश के सात प्रमुख शहरों के लिए 351 इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसों को हरी झंडी दिखाई गई थी।



उज्जैन में चलती बस में लगी भीषण आग

रामवास के पास जली बस की पहचान को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के बयान अलग-अलग सामने आए हैं। कलेक्टर रोशन सिंह ने इसे निजी ऑपरेटर की बस बताया, जबकि ऋद्ध संतोष मालवीय के अनुसार बस सूत्र सेवा की थी। बस पर 'मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा' लिखा था। ऋद्ध के मुताबिक यह बस हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कार्यक्रम के लिए भोपाल भी गई थी। संबंधित विभाग से बस की पहचान की जानकारी जुटाई जा रही है।

printed, Published and Owned by SARABJIT MAKAN and Printed by ILEVAN HASMUKHRAI THAKAR Printed at Jay Graphics & Printers, C/15, Vikram Chambers, Ashram Road, Ahmedabd - 380009. and published from F/1 first floor, rajas apartment, near old railway crossing, maninagar east maninagar, Ahmedabad, Gujarat-380008. Editor SARABJIT MAKAN, Mo.: 9638877700, 9662420070.